

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 सितम्बर, 1995

खण्ड 2, अक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 26 सितम्बर, 1995

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदेन की मेज पर राजे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)24

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)27
अध्यक्ष द्वारा आबजर्वेशन—	
राज्य में आई बाढ़ पर बहस होने सम्बन्धी	(2)53
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(2)56
धोषणाएं—	
(क) अध्यक्ष द्वारा —	
(1) पैनल आफ चेयरमैन	(2)57
(2) कमेटी आ न पैटीशगज	(2)57
(ख) सचिव द्वारा—	
राष्ट्रपतिराज्य पाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(2)57
बिजनैस एडवाइज री कमेटी की पहेली रिपोर्ट पेश करना	(2)58
सदन की मेज पर रखे गये / पुनः रखे गये कागज—पत्र	(2)60
वर्ष 1989— 90 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना	(2)63
विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना—	

(1) प्रो० सम्पत सिंह, एम०एल०ए० तथा प्रतिराक्ष के नेता के विरुद्ध	(2)63
(2) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम० एल० ए० के विरुद्ध	(2)64
(3) श्री कर्ण सिंह दलाल एम० एल० ए० के विरुद्ध	(2)65
(4) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, एम० एच० ए० के विरुद्ध	(2)65
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—	
राज्य में आई बाढ़ सम्बंधी	(2)66
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा	(2)90
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(2) 91
बैठक का समय बढ़ाना	(2)113
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(2)113

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 सितम्बर, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर— 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Persons Living Below Poverty Line

***1192. Dr. Ram Parkash :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the percentage of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes living below the poverty line in the State at present separately; and

(b) the per capita Income of the persons referred to in part (a) above in urban and rural areas in the State separately.?

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता)

(क) गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की पहचान “उपभोक्ता व्यय” सम्बन्धी नमूना सर्वेक्षण द्वारा की जाती है, जो भारतसरकार के राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण का एक भाग है और पाँच वर्षों के पश्चात् किया जाता है। वर्ष 1987— 88 में योजना आयोग ने गरीबी रेखा को, पौष्टिकता की आवश्यकता जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400

कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले व्यय के आधार पर परिभाषित किया था। अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित सूचना अलग से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण में उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इन श्रेणियों से सम्बन्धित सूचना ग्रामीण विकास तथा स्थानीय निकाय विभागों द्वारा लाभकारी प्रोग्रामों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से किये गए सर्वेक्षणों में उपलब्ध है।

इन विभागों द्वारा वर्ष 1991-92 की कीमतों के आधार पर किये गये सर्वेक्षणों से उपलब्ध ग्रामीण तथा शहरी दनेरत्र' में अनुसूचित जातिया तथा पिछड़े वर्गों की प्रतिशत आवंटन नीचे दी गई है।

	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जातियां	40.6	33.5
पिछड़े वर्ग	21.5	संकलन नहीं किया

(ख) अनुसूचित जातियो तथा पिछड़े वर्गों की प्रति व्यक्ति आय अलग से तैयार नहीं की जाती।

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के संबंध में न तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने कोई आकड़े उपलब्ध करवाए है, न ही इन श्रेणियों से संबंधित सूचना ग्रामीण विकास तथा स्थानीय निकाय विभाग ने दी है। और न इन अनुसूचित जाति और

पिछड़े वर्ग की प्रति व्यक्ति आय बताई गई है। इसके बावजूद सरकार द्वारा यह दावा है कि वह पिछड़े बर्ग, दलित वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों का जीवन स्तर उठाने के कदम उठा रही है। मैं समझता है कि इन आकड़ों के अभाव में यह अन्धेरे में लाठी मारने वाली बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा इनके बारे में आखिरी सर्वेक्षण कब किया गया था? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जब से वर्तमान मन्त्रिमंडल का गठन हुआ है, तब से यानि जून, 1991 से अब तक ऐसे कौन से नए पग उठाए गए हैं जिनसे इन वर्गों का जीवन स्तर या इनकी स्थिति को बेहतर बनाया गया है? मैं यह बात सरकार के ऊपर हूँ। छोड़ता हूँ कि क्या बहु इन पगों को कारगर मानती है, क्या इनकी हालत सुधर रही है क्या सरकार चाहेगी कि जो प्रति व्यक्ति आय है, उसका व्यौरा इकट्ठा किया जात ताकि एक आधार बनाया जाय। एक कि गरीबी की रेखा से कितने आदमी नीचे हैं? क्या सरकार इस बारे में अब कोई सर्वेक्षण करेगी?

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को जबाब में बताया है कि केन्द्रीय सरकार के योजना विभाग की तरफ से यह कार्य किया जाता है। 1987-88 की जो सर्वे रिपोर्ट थी वह स्टेट के पास आकड़ों के साथ उपलब्ध है। उसकी सूचना मैंने पटल पर रखी है। हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है, अपनी सेट की एजेंसी के आधार पर सर्वे करने का, वह एच० आर० डी० ए० और लोकल बाडीज के द्वारा प्रयास किया गया है। हमारी स्टेट में इतने ऐसे आदमी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उसको 1991-92 की जो रिपोर्ट

आकड़ों के आ धार पर आई है, बह मैंने आपको बताई है। हरियाणा प्रदेश में टोटल परिवारों की संख्या 26 लाख है जिनमें से 6.29 लाख परिवार शिडयूल्ड कास्टस से संबंधित हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज के 2.55 लाख परिवार रूरल एरिया के हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है और अर्बन एरियाज में 1.35 लाख बैकवर्ड क्लासिज के परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है। जो फार्मूला केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले व्यय के आधार पर परिभाषित किया था लेकिन हमने इनका एक आल्टरनेट रास्ता निकाल कर आय के हिसाब से फार्मूला बनाया है। जिस परिवार की रूरल एरियाज में 11 हजार रुपए पर ईयर इंकम है उसको गरीबी की रेखा से नीचे रखा गया है और अर्बन एरियाज में जिस परिवार की आय 11850 रुपए पर ईयर है, उसको गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। ऐसे परिवारों को सरकार हर साल गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए भिन्न भिन्न एजेंसियों के द्वारा प्रयास करती है। रूरल और अर्बन एरियाज में भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उनको सरकार भिन्न भिन्न स्कीमों द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के प्रयास कर रही है। मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि हिन्दुस्तान के 25 प्रदेशों में हरियाणा का चौथा नम्बर आता है जिसने गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को ऊपर उठाने के लिए हर तरह की एजेंसी काम कर रही हैं। सरकार की हर वक्त यह कोशिश रहती है कि प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा

योजनाएं बना कर लाभ पहुंचाया जाए गैर गरीबी की रेखा से पर उठाया जाए।

डा० राम प्रकाश: स्पीकर साहब, मेरा काम छात्रों को पढ़ाने का भी का है इसलिए मुझे पता है कि जब क्वेश्चन पेपर हल करना होता है तो कई छात्र जिनको जिस सवाल का जवाब याद हाता है, वह उसी सवाल का जवाब लिख देते हैं मंत्री जी का भी यही हाल है। मैंने तो इनसे 1987-88 के बारे में पूछा ही नहीं। केन्द्रीय सरकार के जो आकड़े मौजूद हैं वह ले लिए हैं। मैंने इनसे यह पूछा है कि सरकार ने इस बारे में कौन से नए कदम उठाए हैं? मैंने इनसे यो सवाल पूछा है उसका इन्होंने 33 परसेंट भी जवाब नहीं दिया, यदि ये उसका 33 परसेंट जवाब दे देते तो इनको पास मार्क्स मिल जाते।

श्री अध्यक्ष: आपने सवाल यह तो नहीं पूछा है कि क्या नए पग उठाए है।

डा० राम प्रकाश: स्पीकर साहब, मैंने सप्लीमेंटरी पूछी है कि क्या नए कदम उठाए है ?

श्री मांगे राम गुप्ता: डाक्टर साहब, गरीब लोगों को जरूरत के मुताबिक सरकार ने उनको गरीबी रेखा से पर उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। डाक्टर साहब, आप पढ़े लिखे है मैंने बताया कि सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को उमर उठाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की एजेंसियां चलाई जैसे आई०आर०डी० बी० की स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से लोगों को बहुत ज्यादा सहायता देते

हैं। यह सहायता सबसिडी के कप में भी है और लोन के रूप में भी है इसी प्रकार से दूसरी और एजेंसिया है।

Construction of Ponds

***1193. Smt. Chandravati :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the district-wise number of ponds/tanks constructed/dug out during the period from January, 1991 to 31st March, 1993 and from 1st April, 1994 to 1995 to-date togetherwith the expenditure incurred thereon , and

(b) whether the persons, engaged for the aforesaid work belong to same villages in which ponds have been constructed/ dug out ?

विकास तथा पंचायत मथो (राव बंसी सिंह):

(क) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) उपर्युक्त कार्य के लिए आमतौर पर उसी गांव अथवा आस-पास के गावों के व्यष्टि ही लगाए गए।

विवरणी

क्र० सं०	जिले का नाम	खोदे गए तालाबों / जोहड़ों की संख्या	खर्च (लाख रुपयों में)	खोदे गये तालाबों / जोहड़ों की संख्या	खर्च (लाख रुपयों में)

		(जनवरी, 91 से मार्च, 93)		(अप्रैल, 94 से 1995 तक)	
1.	अम्बाला	18	7.27	3	2,19
2.	भिवानी	66	25.45	164	111,77
3.	फरीदाबाद	शून्य	—	1	0.65
4.	गुडगांवा	शून्य	—	शून्य	—
5.	हिसार	103	49.06	110	62.82
6.	जीन्द	शून्य	—	शून्य	—
7.	कैथल	4	2.85	9	3,65
8.	करनाल	शून्य	—	शून्य	—
9.	कुरुक्षेत्र	शून्य	—	शून्य	—
10,	नारनौल	14	3,96	57	49.70
11.	पानीपत	शून्य	—	शून्य	
12	रिवाड़ी	21	3.17	03	05.82
13	रोहतक	102	28.20	5	1.13

14	सिरसा	123	46.09	239	42.22
15	सोनीपत	24	5.56	6	2.15
16.	यमुनानगर	शून्य	—	2	8.83
	कुल योग	475	181.63	701	482.93

टिप्पणी: पंचकूला जिले से सम्बन्धित सूचना जिला अम्बाला की सूचना में शामिल है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लोहारू, बाढड़ा और छूछकवास में तालाब खोदने का कार्य करवाया गया है, यदि करवाया गया है तो उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है?

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने अलग-अलग गांवों का स्पेसिफिक नाम अब पूछा है जबकि मेन सवाल इनका जिलेवाइज था कि कितने कितने तालाब प्रत्येक जिले में खोदे गए। मेरे पास इन द्वारा पूछे गए गांवों के बारे में भी सूचना आ गई है। मैं बहन जी को बताना चाहता हूं कि बाढड़ा ब्लॉक के चांदवास, हसावासकला, कादमा, जेवली, बिलावल, मांहडी हरिया पिचोपा कलां लाड, आर्य नगर, बिन्दरावन में तालाब खोदे गए। इसी प्रकार से लोहारू हल्के के बुढेड़ी, घागडवास, सेरला, कुशालमुरा, न्य-हत्पलां, चहडखुर्द, फरतामा खेहर, हरियावास, सिंधानी एक, सिंधानी दो, सिंधानी तीन, मनफेरा, पहाडी, बिठन सेहनसारा, बिठन-2 बिघावा सामयान गांवों में तालाब खोदे गए हैं।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तालाब खुदवाने जरूरी थे। दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तालाब आस-पास के लोगों से खुदवाए गए हैं और क्या इन तालाबों के खुदवाने में ट्रैक्टर भी एम्पलाई किए गए थे।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, जे० आर० वाई० के। स्कीम के तहत जो पैसा दिया जाता है वह सीधा गांव में पहुंचता है। 80 परसेंट पैसा भारत सरकार देती है और 20 परसेंट पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके तहत गांव वाले अपनी स्कीम बना कर हमारे पास भेजते हैं कि हमारे फलां गांव में तालाब बनाया जाए। जिला महेन्द्रगढ़ और बहन जी का जिला भिवानी, यहां पर पीने के पानी की समस्या है, वहां के गांवों की पंचायतें अपने गांवों के लिए स्कीम बनाकर भेजती हैं। स्कीम के मुताबिक पैसा सीधे गांव की पंचायत के पास जाता है और यह अपने आप उसको तालाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तालाब खोदने के लिए जो लेबर लगाई जाती है वह 99 परसेंट गांव से हो लगाई जाती है और अगर आम-पास के गांव से कोई मजदूर आ जाए तो उसको भी लगा लिया जाता है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, जो भी तालाब खुदवाए गए हैं उनमें मैनडेज की स्कीम को फोलों नहीं किया जा रहा है। मेरे हल्के के खोरडा गांव में 5-6 तालाब खुदवाए गए हैं, इसके साथ ही साथ 3-3 और जोहड खुदवाए गए हैं जो सभी ट्रैक्टर इस्तेमाल करके खोदे गए हैं। इनमें मैन-डेज के आधार पर मजदूर

लगाकर तालाब नहीं खोदे गये हैं क्या मंत्री महोदय इस बारे में बताएंगे कि ये तालाब ट्रैक्टर से खुदवाए गए हैं या कि मजदूरों से?

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, क् आपके माध्यम से अपने भाई को बताना चाहता हूं कि इस परपज के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वह गांव वालों की मर्जी से खर्च किया जाता है, हम तो केवल टैक्नीकल राय ही देते हैं। एक्सीयन और दी० डी० ओज० की जिम्मेदारी में सारा काम होता है। जो तालाब खोदे जाते हैं वे गांव वालो द्वारा खोदे जाते हैं, हमारी तरफ से गांव वालों पर कोई असैस नहीं है। उनका रैजाल्यूशन आता क्रश और रैजोल्यूशन आने के बाद हम सारे जिले की डिमांड लगाकर भेज देते हैं। 80 परसेंट भारत सरकार से पैसा आता है और 20 परसेंट राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, चौधरी जिले सिंह जी ने जो सवाल पूछा था वह कुछ अधूरा रहा है। जिस गांव से रैजोल्यूशन आता है उसके लिए सरकार पैसा देती है। में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो काम करवाया जाता है, क्या उसके लिए मैन-डेज यूज होते हैं या कि ट्रैक्टरों के जरिये से तालाब खुदवाये जाते हैं, ये इस बारे क्लीयर कट जवाब देने की कूर पा करें। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह स्कीम बेसिकली रुरल एरियाज के लिए ही है और ता लाब खुदवाने के लिए कितने मैन-डेज खर्च हुत हैं? 6 करोड़, 64 लाख, 56 हजार में से कितनों काम मैन-डेज के दारा हुआ है और कितना काम टैरक्टर्ज के जरिये से करवाया गया है? इसके साथ ही मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी कम्पलेन्ट इनके

पास या इनके विभाग में आई है जिसमें मैन-डेज की बजाए काम टैरक्टर्ज के जरिये करवाने की शिकायत की गई है, अगर कोई शिकायत आई है तो इन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की है?

राय बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रो० सम्पत सिंह जो को बताना चाहूंगा कि यह स्कीम गरीबों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ही है। जहां तक इन्होंने शिकायत प्राप्त होने के बारे में पूछा है तो मैं इनका बताना चाहूंगा कि जब से मेरे पास यह महकमा है, मेरे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है (विघ्न) मेरे पास आज तक एक भी शिकायत नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे खत्म से यह बात साफ है कि जो पैसा खर्च किया जाता है, वह गरीबों के लिए रोजगार जुटाने के लिए खर्च किया जाता है। हमारे माननीय अपोजीशन के लीडर ने यह पूछा है कि कितने मैन डेज लगा कर काम करवाया गया है। तो मैं इनका बताना चाहूंगा कि वर्ष 1991-92 में 3 ते लाख, 3 हमार रोजगार की दिहाड़ियां दी गई, 1992-93 में 32 लाख, 63 हजार, 1993-94 में 34 लाख 93 हजार तथा 1994-95 में 33 लाख 96 हजार तथा वर्ष 1995-96 में अगस्त मास तक 4 लाख 58 हजार लोगों से दिहाड़ियो पर काम करवाया गया ई, से मैन-डेज रहे है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो मैनडेज का पैसा है उसको जोड़ ले और मैनडेज से भाग करेंगे तो एक आदमी पर रोज का पाच रुपए भी नहीं आएगा। अगर अपि कहते है कि ऐसा नहीं है तो आप टोटल कर के देख लें।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के थोडा सा समझने में फर्क रहा है। जो मैंने बोला है वह जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा विकास योजना के बारे में है। ये अलग अलग स्कीमें हैं। अध्यक्ष महोदय 45 रुपए 60 पैसे प्रति व्यक्ति दिहाड़ी पर दिया जाता है।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन्होंने खुद या किसी बड़े आफिसर ने मौके पर जाकर देखा है कि जोहड़ो को वाकई खोदा गया है या नहीं जो बड़े-बड़े लोग हैं उन्होंने जोहड़ो पर करजा कर रखा है। मेरे हल्के में ज्यादातर पीने के पानी की प्रोबलम है और यहां पर जोहड़ों की खुदाई ही नहीं हुई है।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी की संतुष्टि के लिए बताना चाहता हूं कि मैंने कम से कम 100 के लगभग ग्राम पंचायतों का दौरा किया है और खुद जाकर देखा है। जिस तरह से इनका जिला रेतीला है उसी उतर से मेरे जिले का इलाका भी रेतीला ही है। अध्यक्ष महोदय, इनके यहां पर 66 जोहड़ एक बार बनाए हैं और 184 जोहड़ एक बार फिर बनाए हैं अगर फिर मैं भी कोई कमी हो तो ये मुझे बता दें और हम दोनों वहां पर ज्वायंट इन्सपैक्शन कर लेंगे।

श्री अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, है आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना, चाहता हूं कि इन्होंने जो आकड़े दिए हैं, वह तो यहीं बताते हैं कि पैसा पांच जिलों में ही खर्च हुआ है। क्या गुड़गांव और फरीदाबाद में जोहड़ खुदवाने की जरूरत नहीं थी, क्या यहां के लोगों

को रोज गार देने की जरूरत नहीं थी? क्या इन पांच जिलों के अलावा और जिले में इसकी जरूरत नहीं थी?

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत से जिले ऐसे नहीं हैं जहां पर जोहड़ खुदवाने का काम हुआ है। यह काम जे०आर०वाई० के तहत जोहड़ खुदवाने का नहीं है ग्रे ईसमें और भी कई काम आ सकते हैं जोकि वहां की पंचायतों पर डिपैन्ड करता है। जहां कि पंचायत जो काम करवाना चाहे वह उनकी जरूरत के मुताबिक कर दिया जाता है। जैसे भिवानी, महेन्द्र गढ़ और रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अन्दर भी इस तरह से ही तालाबों को खोदा गया है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जैसे ई०एस०टी० है, जे० आर० वाई० हैं, इनके अन्दर भी हम इन कामों के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी अन्य स्कीम्स भी हैं जिन के अन्दर हम खुष्क इलाको में पैसा खर्च कर सकते हैं, इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना कि इस मामले में भेदभाव हो रहा है, ठीक नहीं है इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है क्योंकि पैसा सैक से सीधे डी० सीज० के पास आता है ओर वे ही इस पैसे को खर्च करवाते हैं।

Construction of Bus Stand at Rajaund

***1190. Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether the construction work of the Bus Stand at Rajaund has been started ; if so, the progress made in this regard, so far ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह): जी हां। निर्माण कार्य चौखट स्तर तक हो चुका है।

श्री राम कुमार कटवाल: स्पीकर साहब, पिछले साल के मानसून सत में मैंने यह सवाल पूछा था। मैं मंत्री जी का बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूँ कि इन्होंने कम से कम यह तो माना कि इस बस स्टैंड के निर्माण का कार्य चौखट तक पहुँच गया है। 1990 में यह बस स्टैंड बनना चालू हुआ था लेकिन अभी तक यह केवल चौखट तक ही बना है, इसलिए मुझे तो चौधरी भजन लाल जी की सरकार पर विश्वास नहीं है कि यह सरकार इस बस स्टैंड को बनवा पाएगी। सर, वहाँ पर ईंटें भी पड़ी हुई हैं, बजरी भी पड़ी हुई है, सरिया भी पड़ी हुई है, यानी सारा मैटीरियल वहाँ पर पड़ा है, फिर भी इनकी नीयत उस बस स्टैंड को बनवाने की नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार उस बस स्टैंड को कब तक बनवा देगी?

श्री बलबीर पाल शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस से और माननीय सदस्य से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि सरकार की नीयत में कोई भी खोट नहीं है। हमने इस बस स्टैंड को बनवाने के लिए पी०डब्ल्यू डी० (बी०एंड आर०) के पास पाँच लाख 46 हजार रुपये जमा करवाए हुए हैं और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि हम दस लाख रुपये इनके लिए 15 दिन के अंदर-अंदर और रिलीज कर देंगे। सर, पिछले दो-तीन महीने ले इस बस स्टैंड का काम बारिश की वजह से रुका पड़ा था। चूंकि हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए उसी हिसाब से पैसा रिलीज किया जाता है। हमारी यही कोशिश रही है कि जो भी काम

चालू हुए पड़े हैं, चाहे वह पिछली सरकार ने ही क्यों न चालू किए हों, हम उनको पूरा करेंगे। इसराना, समालखा और महेन्द्रगढ़ आदि कई बस स्टैंड ऐसे, हैं जिन पर पिछली सरकार ने काम चालू करवाया था लेकिन हमने उन को पूरा किया है' और चौधरी भजन लाल जी ने इनका उदघाटन किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको शक नहीं करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बस स्टैंड का काम 90 दिन में पूर्ण कर दिया जाएगा।

श्री राम कुमार कटवाल: सर, मंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार के काम इन्होंने किए हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि,

....

श्री अध्यक्ष: ये जो शब्द कह रहे हैं उनको रिकार्ड न किया जाए।

Handing over of Thermal Power Plants

***1194. Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to handover the Thermal Power Plants to private sector, if so; the reasons thereof ?

Power Minister (Sh. Verender Singh) : No, Sir However private participation has been sought through competitive bidding for construction of Unit-VI of Panipat Thermal Project in view of constraints of resources.

प्रो० छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पानीपत आर फरीदाबाद थर्मल प्लांट्स की कितनी कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स की कितनी वर्किंग कैपेसिटी है एवं इस समय ये कितनी परसेंटेज में बिजली बना रही हैं? इसके अलावा, क्या एन० टी० पी०सी० ने हरियाणा सरकार से यी नहीं कहा है कि आपके थर्मल प्लांट्स की बिजली की जनरेशन की परसेंटेज बहुत ही कम है और अगर आप हमें यह थर्मल प्लांट्स दे देंगे तो हम इनकी बिजली को जनरेशन की परसेंटेज 75 परसेंट तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, वह इससे अराइज नहीं होता।

प्रो० छतर सिंह चौहान: सर, अब मैं इसी से रिलेटेड पूछ लेता हूँ। स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने खुद ही माना है कि private participation has been sought. क्या यह मानते हैं कि 1987-88 में ये बिजली मंत्री थे और आज भी बिजली मंत्री है, क्या उस समय के बिजली बोर्ड और आज के बिजली बोर्ड की कार्यकुशलता में कुछ कमी आ गई है जिसके कारण ये प्राइवेट पार्टिसिपैन्स के लिए ये तैयार हैं? आज जो बिजली की कमी है क्या यह आपके महकमे की इनएफिशिएंसी का द्योतक नहीं है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, जो इससे रैलेवैर सवाल था वह तो मेरे सन्धि ने पूछा नहीं लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ कि

मौजूदा सरकार, बिजली की जो रोजाना की बढ़ती हुई मांग है उसके लिए बहुत ही चिंतित है और इसीलिए बहुत सारे कदम बहुत ही थोड़े दिनों के अंदर उठाए हैं जिससे जो तउली हुई मांग है उसे पूरा किया जा सके। जहां तक यूनिट- 6 का सवाल है, इसके लिए प्राइवेट पार्टीसिपैन्ट्स से बिड्स इनवाइट किए हैं और इसमें अपना हिस्सा भी हमने रखा है। मेरे साथी जो एन०टी०पी०सी० की बात कर रहे हैं कि एन०टी०पी०सी० ने हमें यह कहा है कि यह यूनिट हमें दे दो, हम इसकी ऐफीशियैसी और वर्किंग बढ़ा देंगे। एन०टी०पी०सी० ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा बल्कि हमने उन्हें ऐप्रोच किया था और चौधरी बसो लाल जी भी बार-बार यही कहा करते थे तो हमने कहा कि यूनिट- 6 को अगर आप बनाना चाहें तो बनाइए, हम आपको आफर दे रहे हैं और उसके लिए एन० टी० पी०सी० ने जो कंडीशन रखी, वह सी में विस्तार से बता सकता हूं लेकिन कंडीशन हमें मंजूर नहीं थी इसलिए अब हम इसको प्राइवेट पार्टीसिपैन्ट्स के साथ मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे पग उठाए हैं। समय अनुकूल होगा तब हम बता देंगे कि बिजली के सैक्टर के लिए सरकार कितनी चिंतित है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मती जी से जानकारी चाहूंगा कि यूनिट- 6 कब शुरू की गई, कितना धन इस पर खर्च हो चुका है और कितना होना इस पर बाकी है? जब हरियाणा बिजली बोर्ड इसको बना रहा हूं तो क्या जरूरत पड़ गई है कि आगे प्रोग्रेस बन्द करे और अब एक प्राइवेट पार्टी को आम बुला रहे हैं, क्या इससे प्रदेश में मंहगी बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, जहा तक यूनिट- 6 व ताल्लुक है, इसकी हमने 1969 से शुरूआत की थी और अगर यह शुरूआत हुई-हुई रहती, काम चलता पता तो दिसम्बर-93 में इस यूनिट को कमीशन हो जाना था। पैसे का फाइनेंशियल कंसट्रैट बहुत ज्यादा हुआ है। मशीनरी 120 करोड़ के लगभग की थी, दह मशीनरी अभी हैं लेकिन इसको पूरा नशे कर सके। फाइनेशियल कंसट्रैट के कारण। अब भी बिजली बोर्ड से इतनी शक्ति नहीं है कि अपने आप में यह इसको मुकम्मल कर ले इसलिए प्राइवेट पार्टी की जरूरत पडी और आज जमाना भी प्राइवेटाइजेशन का है, इस रात का आपको भी पता है, अध्यक्ष महोदय और इस हाउस के सभी माननीय मैम्बर्ज को भी पता है कि आज कितना खचीला काम हो गया है। जहां पहले यूनिट 238 करोड़ से तैयार हो जाना था, जून, 1994 में इसकी प्राइस बढ़कर 40.5 करोड़ के करीब हो चुकी थी और आज के दिन बढ़कर लगभग 500 करोड़ के करीब हो गई होगी। इसीलिये हमें प्राइवेट सैक्टर में पार्सईसिपेट करने की आवश्यकता पडी।

प्रो० रामबिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी उर्जा मस्ती महोदय ने फरमाया कि 1989 में यूनिट नम्बर 6 पर इन्होंने काम शुरू किया था मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से व हु पुछना चाहता हूं कि इस यूनिट पर अबे तक कितना व्यय हो चुका है? इसके साथ यह भी बताएं कि जो इन्होंने प्राइवेट ग्लोबलाईजेशन से टैन्डर काल किये थे, उसमें कितने प्राइवेट कंपनियों के टैन्डर इनके पास आए और इस प्रौसैस को इन्होंने कितना आगे बढ़ाया? कही ऐसा न हो कि डाभोल

प्रोजैक्ट व एनरान जैसा हाल हो जाये और बाद में रामराज्य की सरकारों को आकर ऐसे प्रोजैक्टस को फिर रह करना पडे। इनमे प्रौसैस कहां तक पहुंचा है, यह जानकारी भी दें

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये हमारे साथी बहुत पूसने हैं। इनको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अगर इनकी सरकारें आती रही तो यूंही सय कुछ कैंसिल होता रहेगा, ऐसा भी नजर आता है। कोई प्रोग्रेस इस देश व प्रदेश की नहीं हो सकेगी। आज तक अध्यक्ष महोदय लोगों वै देख' लियो है कि बाकायदा मशीनरी खरीदी गई है और बहुत सारे सिविल वर्कस भी हुए हैं जिस पर लगभग 120 करोड़ के करीब खर्चा भी हो चुका है। मशीनरी और सिविल वर्कस बिलकुल इटैक्ट हैं। जहां तक प्राइवेट पार्टीमिपेशन का सम्बन्ध है, उस बारे में हमने न्यूज पेपर्स के द्वारा आफर दो थी और टैकनीकल बिंडज 11 सितम्बर को खोल दी गया है। और हम इनको एग्जामिन कर रहे हैं। फाइनेनशियल बिंडज को तय खोलेंगे जब यह टैकनीकली पूरे पैरामीटर से उतर आएगी।

प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बिजली मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट के उपर कुल कितनी लागत आएगी? यह बता रहे हैं कि पैसे की कमी रही है। इसके साथ यह भी पूछना चाहता हूं कि जो बिजली की जनरेशन होगी उसमें हमारा कितना हिस्सा होगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगी? दूसरा मैनेजमेंट में हमारा कितना हिस्सा होगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिस्सेदारी का सवाल है उसमें हरियाणा सरकार का भी हिस्सा हो सकती है और बिजली बोर्ड का भी हिस्सा हो सकता है। हमने दोनों आप्शन ओपन रखी हैं। जब यह बिडज ओपन हो लेगी और बाद में जब हमारी बात नैगोशीऐशन पर आएगी, तब तय किया जाएगा कि हम कितना हिस्सा अपना रखेंगे,। यह तो समय के अनुसार देखा जाएगा कि मेजर हिस्सा रखें या माइनर रखें लेकिन हम जरूर रखेंगे, यह आश्वासन हाउस को देता हूं। दूसरी बात यह है कि बिजली का प्रयोग कौन करेगा। सारी बिजली हमारी होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करेंगे क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा अपना है। यह एक ज्वायंट वैन्चर कम्पनी होगी, मिल जुल कर जनरेशन करेंगे, वे ही अपना हिस्सा रखेंगे और हम भी रखेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि इस प्रोजैक्ट पर 120 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। क्या ये बताएंगे कि जो स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके लिए इन्होंने कितना पैसा निर्धारित किया है और जो फण्डज हैं, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे और उसको इंस्टाल नरने में कितना धन लगेगा? इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि गांव खुखराना में प्रदूषण फैलेगा, उसको रोकने का इन्तजाम आप कब तक कर देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, पैसा तो हमने खर्च कर दिया है। जब हम हिस्सेदारी की बात उनसे करेंगे उस समय एडजस्टमेंट हो जाएगी और जहां तक गांव में प्रदूषण की बात है, इसके

लिए हम यत्न करेंगे कि उस गांव के लोगो को किसी किस्म की भी तकलीफ न होने पाए।

Amount of loan/grant given to Municipal Committees and Nagar Parishads

***1197. Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—

(a) the total amount of loan given to each Municipal Committee in the State during the years 1992-93 and 1993-94 ; and

(b) the total amount of loan and grant given to each Nagar Parishad in the State during the years 1992-93 and 1993-94 separately ?

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba)

(a) During the years 1992-93 and 1993-94, no loan has been advanced to any of Municipal Committees (B and C Class,) except Municipal Committee, Palwal. in the State.

(b) Statement showing the disbursements of loans and grants to each of the Municipal Committees (A and B Class), which have now been categorised as Nagar Parishad/Municipal Councils under the Constitution (74th Amendment) Act. during 1992-93 and 1993-94 is at Annexure 'A'

ANNEXURE 'A'

Statement showing the amount of loan and grants released to Municipalities (Municipal Council/Nagar Parishad) during the years 1992-93 and 1993-94.

Name of District	Name of Municipal Committee/Municipal Council		Amount of loan advanced		Amount of grants released		Grand Total (Col. 3+4)
			1992-93	1993-94	1992-93	1993-94	
Ambala	1	Ambala City	6,50,505.61	—	6.88,625	7.83.425	21,22,555.61
	2	Ambala Sadar	—		5.50,625	6,08,075	11,58,700.00
Yamuna Nagar	3	Yamuna Nagar	—	—	9,25,625	12.91,000	22,16,625.00
	4	Jagadhri	—		4,45,000	6,19,600	10,64,600.00
Kurukshetra	5	Thanesar	6,0,505.61	—	3,02,625	5,49,275	15,02,405.61
Kaithal	6	Kaithal	—	—	5,55,625	4,86,800	10,42,425.00
Karnal	7	Karnal	7,47,987.35	—	9,30,625	11,17,325	27,95,937 35
Panipat	8	Panipat	6,49,599 . 85	—	12,55,625	16,94,300	35,99,524.85

Sonepat	9	Sonepat	7,47,987.35	—	11,00,625	12,87,950	31,36,562.35
Robb*	10	Rohtak	13,96,272.60	—	10,90,625	13,77,725	38,64,622.60
	11	Bahadurgarh	—	—	4,20,000	5,26,150	9,46,150.00
Faridabad	12	Palwal	6,49,599.85	—	3,45,000	4,03,300	13,97,899.85
Rewari	13	Rewari	6,49,599.85	—	4,80,625	6,97,325	18,27,549.85
Gurgaon	14	Gurgaon	13,96,272.60	—	13,00,625	12,94,750	39,91,647.60
Mohindergarh	15	Narnaul	—	—	3,45,000	3,58,150	7,03,150.00
Hisar	16	Hisar	6,50,505.61	—	13,30,625	13,11,025	32,92,155.61
	17	Hansi		—	4,80,625	4,16,450	8,97,075.00
Sirsa	18	Sirsa	6,49,599.85	—	6,50,625	7,43,000	20,43,224.85
Bhiwani	19	Bhiwani	—	—	6,90,625	7,47,075	14,37,700.00
Jind	20	Jind	6,49,599.85	—	5,30,625	5,73,950	17,54,174.85
		Total :	94,88,035.98	—	1,44,20,000	1,68,86,650	4,07,94,685.9

							8
--	--	--	--	--	--	--	---

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी इस साल अप्रैल से अब तक फिगगर बताने की भी कृपा करें कि सरकार ने किस-किस कमेटी को कितनी ग्रांट या कितना लोन दिया है। मैं यह ली जानना चाहता हूँ कि सरकार का ग्रांट या लोन देने का क्या क्राइटेरिया है?

चौधरी धर्मवीर गाबा: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का सवाल वर्ष 1992-93 और 1993-94 के बारे में था लेकिन फिर भी मैं 1995-96 के बारे में भी बता देता हूँ। इस साल अब तक हमने 250 लाख रुपया दिया है।

श्री राम भजन अग्रवाल: स्पीकर साहब, बाढ़ आने के बाद म्यूनिसिपल कमेटियों की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि रोहतक, भिवानी और दादरी कमेटियों के जो अपने रिसोर्सिज हैं वह उनमें काम नहीं कर सकती। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इन कमेटियों को सरकार कितना फंड देगी ताकि गढ़ में प्रभावित इन शहरों का दोबारा निर्माण हो सके।

चौधरी धर्मवीर गाबा: स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी को चेयरमेनशिप में एक मीटिंग हुई है जिसमें यह क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया गया था जो कमेटी अपने सोर्स से अपना काम चलाने के लिए कम्पीटेंट नहीं है, सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देगी ताकि वे अपने कर्मचारियों को तनखाह दे सकें और निवासियों को सहूलियत दे सकें। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को

गई है, उसमें हमने 25 करोड रुपए म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए मांगे हैं ताकि कमेटियां अपनी डैमेज्ड सड्कों की रिपेयर वगैरह कर सकें।

श्री राम भजन अग्रवाल: स्पीकर साहब, मैं कमेटी वाइज फिगगर जानना चाहता हूं कि कितने कितने पैसे दिए जाएंगे क्योंकि कुछ कमेटियों के पास तो सफाई कर्मचारियों को तनखाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए वे कर्मचारी काम करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आज शहरों में गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं। इसलिए कुछ कमेटियों को तो विशेष अनुदान देने की आवश्यकता है।

चौधरी धर्मवीर गाबा: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि भिवानी में म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारी तो हैं हीं लेकिन उसके बावजूद भिवानी में सफाई के लिए आठ टीमों और काम कर रही हैं जो हमने दूसरी कमेटीज से भेजी हैं। हमने 13 सितम्बर को आदेश जारी कर दिया था कि जिस कमेटी को जितने आदमी चाहिए वह लगा ले और उनको उनके लिए हम रीलीफ फंड से पैसा देंगे।

डा० राम प्रकाश: स्पीकर साहब, मैं आपके हारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि किन्ही म्यूनिसिपल कमेटीज की कुछ राशि सरकारी अदायकों अर्ध-सरकारी अदायकों या आटोनमस बाडीज द्वारा देनी बाकी है? जब उन कमेटियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अगर वे संस्थाएं उनको लोन पर पैसा दे देगी तो उन्हें कुछ काम करने में आसानी रहेगी। क्या आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है।

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का मेन सवाल से संबंध नहीं है।

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय लोन का सवाल इनकम से ताल्लुक रखता है। मंत्री जी लोन देने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तो इनसे एक मोटी मी बात जानना चाह रहा हू कि जिन सरकारी अर्ध-सरकारी अदायगों ने म्यूनिसिपल कमेटी ज का पैसा देना है, अगर वे म्यूनिसिपल कमेटीज को पैसा दे दें तो उनका काम चल सकता है।

(इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ। क्या यह बात इनके नोटिस में है कि हरियाणा प्रदेश की कितनी ऐसी म्यूनिसिपल कमेटीज है जो मोर दैन बन मंथ से अपने कर्मचारियों को तनखाह नहीं दे रही है? मंत्री जी ने एक बात यह भी कही है कि प्रोपोजल बनाकर सैट्रल गवर्नमेंट को लिखा है, यह तो आप पहले भी लिखते रहे है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि फल्ल्ड आने के बाद आपने किस किस म्यूनिसिपल कमेटी को कितनी- कितनी ग्रांट दी है?

चौधरी धर्मवीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, अगर प्रोफ़ैसर साहब किसी पर्टीकुलर कमेटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वह मैं बता सकता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने इनसे सीधा-सा सवाल पूछा है कि इस बाढ़ के आने के बाद आपने किस किस म्यूनिसिपल

कमेटी को कितनी कितनी ग्रांट दी है और दूसरी बात तनखाह के बारे में पूछी है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई जिसके बारे में सभी माननीय सदस्यों को बहुत चिन्ता है। जिस दिन बाढ़ आई हमने उसी दिन सभी डी०सी० को हिदायतें जारी कर दी थी कि जिस जिस इलाके में बाढ़ का पानी निकालने के लिए और लोगों को सुविधाएं देने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है वह फौरन हमसे मांगें। जिस डी० सी० का टेलीफोन आया, टेलीग्राम आया और जिसने जितना पैसा मांगा, सबको वह पैसा री ली ज कर दिया। हमने 23.65 करोड़ रुपए रीलीफ फण्ड का दिया है और 10 या 11 करोड़ रुपया और रीलीज किया है। जिस जिस डी० सी० साहेबान ने जरूरत समझी हमने उनको पैसा दिया है। जहां भी जरूरी है, चाहे वह म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया है और चाहे देहात का एरिया है, जहां पर जरूरी हैं, वही पर वह पैसा खर्च होगा।

श्री अध्यक्ष: अभी ये फिगर्ज अक्युमुलेट हो रही होंगी।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं इनसे यह पूछ रहा हूं कि इस फण्ड के माने के बाद आपने रोहतक भिवानी, बरवाला और हांसी म्यूनिसिपल कमेटी को कितनी कितनी ग्रांट दी है?

चौधरी धर्मवीर गाबा: स्पीकर साहब, इस फण्ड के आने के बाद रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी को 10 लाख रुपए, भिवानी म्यूनिसिपल

कमेटी को 4 लाख रुपए और हांसी म्यूनिसिपल कमेटी को 5 लाख रुपए दिए हैं।

प्रो० छतर सिंह चौहान: दादरी म्यूनिसिपल कमेटी को कितने पैसे दिए हैं?

चौधरी धर्मवीर गाबा: दादरी म्यूनिसिपल कमेटी को 3 लाख रुपए दिए हैं।

Auction of Liquor Vends

***1199. Shri Satbir Singh Kadian :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the districtwise number of country made liquor and Indian made foreign liquor vends auctioned in the State during the years 1993-94 and 1994-95 todate ;

(b) the districtwise and yearwise total income accrued from the auction of the vends as referred to in a part -A' above;

(c) the total income accrued from Excise duty by selling/auction of country made liquor and Indian made foreign liquor vends, Bars and from drinking places (Ahatas) in the State during the years 1991-92, 1992-93, 1993-94 and 1994-95 todate; and

(d) the target if any, fixed for the production of country made liquor together with the quantity of liquor produced during the period as referred to in part 'C' above, yearwise separately ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): प्रश्न से सम्बोधित सभी सूचना की विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) वर्ष 1993- 94, 1994- 95 तथा इस वर्ष अंग्रेजी तथा देसी शराब के ठेकों की जिलावार नीलामी की संख्या निम्न प्रकार है:

क्रमांक	जिले का नाम	निलाम किए गए ठेकों की संख्या					
		1993- 94		1994- 95		1995- 96	
		देसी शराब	अंग्रेजी शराब	देसी शराब	अंग्रेजी शराब	देसी शराब	अंग्रेजी शराब
1	अम्बाला	95	45	100	44	100	44
2.	भिवानी	51	17	44	17	44	17
3	फरीदाबाद पूर्व	24	25	24	25	24	25
4.	फरीदाबाद पश्चिम	38	32	38	30	38	31
5.	गुडगांव	37	35	37	35	37	35
6.	हिसार	72	26	72	27	74	27

7.	जीन्द	38	20	35	19	35	19
8.	जगाधरी	30	18	31	18	31	17
9.	करनाल	65	21	64	19	64	20
10	कुरुक्षेत्र	37	12	38	12	40	13
11.	कैथल	45	12	39	12	39	12
12.	नारनौल	36	11	33	11	33	11
13.	पानीपत	30	16	30	14	29	14
14.	रिवाड़ी	33	15	32	16	30	16
15	रोहतक	46	37	41	41	40	39
16.	सिरसा	61	17	61	17	61	18
17.	सोनीपत	40	26	40	25	34	25
	टोटल	778	385	759	382	753	383

(ख) उपरोक्त भाग 'क' अनुसार जिलावार तथा वर्षवार ठेकों की नीलामी से, हुई कुल आय निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	जिले का नाम	ठेकों की नीलामी से प्राप्त कुल आय (रुपये लाखों में)					
		1993— 94		1994— 95		1995— 96	
		देसी शराब	अंग्रेजी शराब	देसी शराब	अंग्रेजी शराब	देसी शराब	अंग्रेजी शराब
1	अम्बाला	1673.91	689.09	1812.40	805.19	2569.35	926.45
2.	भिवानी	1184.90	262.68	1292.77	323.28	1778.07	371.77
3	फरीदाबाद पूर्व	543.55	888.65	582.60	1020.15	855.00	1173.17
4.	फरीदाबाद पश्चिम	857.00	883.89	988.22	1054.80	1338.98	1233.17
5.	गुडगांव	830.16	1118.04	939.31	1304.00	1665.53	1507.98

6.	हिसार	2759.6	709 91	3265.38	864.66	4240.00	994.84
7.	जीन्द	1183.00	261.26	1427.12	324.88	1854.05	280 09
8.	जगाधरी	961.00	469.70	955.50	489.00	1248.10	562.35
9.	करनाल	1516.30	322.02	1538.46	331.28	1983.86	384.99
10	कुरुक्षेत्र	988.00	194.06	944.65	242.58	1306.50	283.97
11.	कैथल	1074.65	187.93	1322.17	237.34	1794.20	272.94
12.	नारनौल	496.05	167.74	568.58	223.52	738.08	257.05
13.	पानीपत	871.15	320.50	1048.05	399.88	1414.20	459.85
14.	रिवाड़ी	639.95	281.69	583.10	338.47	769.75	389.62
15	रोहतक	1248.60	952.07	1203.25	1069.22	1661.20	1235.07
16.	सिरसा	1614.72	418.43	1742.54	498.96	1960.20	576.58

17.	सोनीपत	1019.35	611.36	1103.30	672.31	1516.25	783.16
	जोड:	19351.45	8739.02	21317.34	10199.52	28688.22	1793.04

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा अब तक राज्य में देसी तथा अंग्रेजी शराब के ठेको की नीलामी, यार तथा भराव पिलाने के स्थानों (आहातों) से प्राप्त कुल आय निम्न प्रकार है:

(रुपये करोडो में)

क्र० सं०	मद का नाम	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	जुलाई, 95 तक कुल प्राप्ति
1	देसी शराब पर आबकारी शुल्क	28.28	46.50	52.80	62.31	67.52	22.56
2	अंग्रेजी शराब तय बीयर पर आबकारी शुल्क	62.51	77.79	77.55	90.02	103.19	30.11
3	बार की लाई सैस फीस	0.98	1.65	1.88	2.40	1.21	0.69
4	आहातों की लाईसैस फीस (शराब पिलाने के स्थान)	0.65					

नोट:—शहरी क्षेत्र के देसी शराब के ठेकेदारों को देसी शराब पिलाने के लिये दिये गये आहातों की सुविधा 1-4-1992 से वापिस से लो गई।

(घ) उपरोक्त (ग) के संदर्भ में देसी सराय के उत्पादन का कोई लक्ष्य नियत नहीं है परन्तु सरकार द्वारा आबकारी नीति का अनुमोदन करते समय देसी शराब का कोटा नियत किया जाता है (जो कि देसी शराब के ठेकों में बांटा जाता है) वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक नियत किया गया कोटा एवं उत्पादित का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	सरकार द्वारा नियत वार्षिक कोटा (लाख प्रूफ लिटर में)	उत्पादित कोटा (लाख प्रूफ लिटर में)
1991-92	265.00	272.72
1992-93	290.00	318.22
1993-94	310.00	299.98
1994-95	310.00	312.04
1995-96	320.00	93.50 (जुलाई 1993 तक)

श्री सतबीर सिंह कादयान: वर्ष 1993-94 और 1994-95 में जो शराब के ठेके दिए गए, क्या वे बोली में दिए गए हैं या वैसे ही दे

दिए गए हैं? इन्होंने जो आकड़े दिए हैं, उस हिसाब से वर्ष 1994-95 में देसी शराब से इन्हें 21317.34 लाख रुपये और अंग्रेजी शराब से 20199.52 लाख रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 1993-94 में देसी शराब से इन्हें 19351.45 लाख रुपये और अंग्रेजी शराब से 8739.02 रुपये प्राप्त हुए। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों में वेरिगेशन क्यों है, क्योंकि इनको देसी शराब से ज्यादा पैसा आया और अंग्रेजी शराब से कम आया?

श्री लछमन दास अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आकड़े-पढ़े हैं, वे गलत पढ़े हैं। पहले तो मैं इनको यह जवाब देता हूँ कि जो भी ठेके दिए गए हैं, वे ओपन ओक्शन में दिए गए हैं। दूसरा उत्तर मैं इनको यह देना चाहता हूँ कि वर्ष 1993-94 में देसी शराब से 16 करोड़ 73 लाख रुपये आए और अंग्रेजी शराब से 193 करोड़ रुपये आए। वर्ष 1993-94 में देसी शराब से 21317.34 लाख रुपये और अंग्रेजी शराब से 10199.52 लाख रुपये आए। वर्ष 1995-96 में देसी शराब से 28688.22 लाख रुपये आए और अंग्रेजी शराब से 11793.04 लाख रुपये आए।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अगले साल यानी 1 अप्रैल 1996 से शराब बंदी के बारे में सरकार की क्या स्पष्ट नीति होगी?

श्री लछमन दास अरोड़ा: मुख्य मंत्री ने कहा है कि अगले साल से देहात में बहुत कम ठेकेदार देंगे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला किया है कि अगले साल पहली अप्रैल से देहात में शराब का कोई ठेकी नहीं खोलेगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: क्या यह सही बात नहीं है कि अंग्रेजी शराब के ठेके 15 परसेंट बढ़ा कर उन्हीं लोगों को तो नहीं दे दिए गए जिनके पास पहले थे? दूसरे, जो मोलैसिज होता है, उससे कितनी शराब बननी चाहिए, और कितनी 'बनी है, क्या इसका कोई हिसाब है? कहने का मतलब है कि मोलैसिज से जो ज्यादा शराब बनी यानी नार्म से ज्यादा बनी वह कहां गई?

श्री लछमन दास अरोड़ा: हमने 15 परसेंट ठेके बढ़ा कर उन्हीं लोगों को नहीं दिए हैं। हर हैंका ओपन आक्शन में दिया है। हमारे ठेके पिछले साल की अपेक्षा इस साल 28.44 परसेंट अधिक बल कर गए हैं। मोलैसिज के बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि मोलैसिज का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। जिस वक्त आक्शन करते हैं, उस वक्त शराब का कोटा फिक्स करते हैं और उसी के मुताबिक डिस्टिलरी का कोटा होता है अगर ऐसी स्थिति हो कि शराब बच गई है तो बाद में जब किसी स्टेट की डिमांड आए तो अपने हिसाब से उसको भेज देते हैं।

Realisation of Excise Duty

***1201 Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether there is any increase in the realisation of Excise duty during the year 1991-92

as compared to the corresponding last year in the State ; if so, the percentage thereof ?

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): हां, राज्य में वर्ष 1991- 92 दौरान आबकारी शुल्क की प्राप्ति से वर्ष 1990-91 की तुलना में 8.02 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री जी के नालेज में यह बात है कि हरियाणा के एक्साईज एण्ड टैक्सेडान के अधिकारी वाकई में स्टेट की आय को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरकार के मन्त्री, अधिकारियों को कार्यवाही करने में रुकावट डालना चाहते हैं? सोनीपत में सेल्ज टैक्स के बारे में मैं इनसे पूछना चाहता हूँ..... (विधन एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माना है कि वर्ष 1991- 92 में स्टेट की आय में 8.2 परसेंट वृद्धि हुई है। स्पीकर सर, यह सितम्बर, 1995 का नोटीफिकेशन है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता है कि अगर सरकार की आय बढ़ी है तो फिर 4 सितम्बर, 1995 को इस नोटीफिकेशन की क्या जरूरत थी कि हरियाणा में सैट्रल सेल्ज टैक्स अगर किसी की तरफ बकाया है वह उसको अन् करे, इस नोटिफिकेशन को जारी करने की क्या जरूरत थी (विधन)

श्री लछमन दास अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात कहीं से शुरू की और पहुंच गये कहीं और। (विधन) ये शुरू में एक्साइज एण्ड टैक्सेशन की बात कर रहे थे कि कितना बढ़ा है। हमने बताया कि यह 1990-91 की तुलना में साढ़े सात परसेंट बढ़ा है, बाद

में ये सेल्ज टैक्स की बात करने लगे, इनका यह सवाल रैलेवैट नहीं है।
(विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल हरियाणा के हितों तथा जनता के हितों से जुड़ा हुआ है। एक्सार्ज एण्ड टैक्सेशन का महकमा काफी अधिक और रुपया अदा कर सकता है लेकिन जानबूझ कर सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो 4 सितम्बर की नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसकी क्या आवश्यकता थी?

श्री लछमन दास अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहूंगा कि 89 करोड़, 64 लाख, 40 हजार रुपया एक्सार्ज से आया है। (विधन)

Number of Schools, Head Masters/Prinerpals

***1210 Shri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the blockwise number of Middle. High and 10+2 Schools in the districts of Faridabad and Gurgaon separately; and

(b) the number of posts of Principals/Head Masters, lying vacant in the schools as referred to in a part (a) above at present together with the steps taken or proposed to be taken to fill up the vacant posts ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) (a) & (b)

Information is laid on the table of the House.

Information

(a) Block-wise number of Government Middle, High and 10+2 Schools in Districts of Faridabad and Gurgaon.

Name of the District.	Name of the Block	Number of Schools		
		Middle	High	10+2 level
Faridabad	Faridabad	12	27	11
	Ballabgarh	21	19	7
	Palwal	9	26	7
	Hodle	13	22	4
	Hathin	11	12	8
	Total	66	106	37
Gurgaon	Gurgaon	11	17	6
	Faru khna gar	9	9	3
	Sohna	11	15	3
	Manesar	3	13	2
	Pataudi	12	10	3
	Nuh	18	14	1

	Taoru	7	8	2
	Ferozpur Jhirka	9	9	2
	Punhana	8	11	5
	Nagina	11	8	2
	Total	99	114	29

(b) The number of posts of Principals/Headmasters lying vacant in the schools as referred to in para (a) above at present.

Name of Districts	Name of Block	Number of vacant posts		
		Middle Schools	High Schools	10+2 Schools
Faridabad	Faridabad	4	—	4
	Ballabgarh	14	4	1
	Palwal	9	8	3
	Hodel	8	11	1
	Hathin	10	6	7
	Total	45	29	16
Gurgaon	Gurgaon	—	—	2

	Farukh Nagar	1	1	1
	Sohna	1	2	2
	Manesar	—	1	1
	Pataudi	3	4	1
	Nuh	17	12	1
	Taoru	7	8	—
	Ferozpur Jhirka	9	7	2
	Punhana	6	11	2
	Nagina	11	6	2
	Total	55	52	14

Steps taken or proposed to be taken to fill up the vacant posts

1. Requisition to fill direct quota posts of Headmasters/ Headmistresses of High Schools and Principals of 10+2 schools has been sent to Haryana Public Service Commission.

2. Promotion cases are being processed to fill up promotion quota posts of Headmasters/Headmistresses of Middle Schools and High Schools and Principals of 10+2 schools.

श्री अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल शिक्षा. जैसे अहम मसले से ताल्लुक रखता है। हैडमास्टरज और मास्टरज की शहरों में तो कोई खास कमी नहीं है लेकिन देहातो में पोस्टस खाली पड़ी हुई हैं। फरीदाबाद के अरन्दर शहर में तो हैडमास्टरज और मास्टरज की जगहें

खाली नहीं है, इसी प्रकार से गुड़गांव शहर में भी बहुत कम पोस्टस खाली हैं लेकिन मेवात के ऐरिया में कहीं भी हैडमास्टर की पोस्ट भरी हुई नहीं है। हथीन के मिडल स्कूलों में 11 पोस्टों में से 10 खाली है, हाई स्कूलों में 12 में से 6 पोस्ट्स खाली हैं और 10 जमा 2 स्कूलों में 8 पोस्ट्स में से 7 पोस्ट्स खाली हैं। इसी प्रकार से नूह, नगीना, तावडू, फिरोजपुर सिरका पुन्हाना खण्डों के मिडल स्कूलों में 53 से 50 पोस्ट्स खाली हैं, हाई स्कूलों में 50 पोस्टों में से 44 खाली हैं और 10 जमा दो के स्कूलों में 12 पोस्टों में से 7 पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आप खुद देखिए कि देहात में जो स्कूलज हैं, उनमें पोस्टें बहुत ज्यादा खाली पड़ी हुई हैं। आप स्वयं जानते हैं कि इन पोस्टों के खाली रहने से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ज्या कैरियर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। इससे नस्ल की नस्ल ही खराब हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या जल्दी से जल्दी इन स्कूलों में हैडमास्टरज लगाने की कोशिश करेंगे?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल है कि आज देहातों में कम मुख्य अध्यापक लगे हुए हैं और शहरों में पूरे हैं। यह बात तो इनकी ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी यह सिफारिश करते हैं कि फलाने फलोने को शहर में लगा दो। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा हुआ है कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भरे। अध्यक्ष महोदय मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो सीधी भर्ती वाले पद

है, वे पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजते ही भर दिए जाएंगे और, दूसरे जो पद रह जाएंगे उनको भी हम शीघ्र ही भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के
लिखित उत्तर

**Providing of Jobs to Scheduled Castes and Backward Classes as
per reservation policy.**

***1222. Shri Om Parkash Jindal :** Will the Minister of State for Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes be pleased to state whether the recruitment of the ,persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes has been made according to. their. percentage of reservation in the Government jobs, by the State-Government during the last four years, if not, the reasons there of ?

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री, (श्रीमती सन्तोष चौहान सारवान): पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार के विभागों द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गी के लिये निर्धारित आरक्षण के अनुसार भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र भेजे गये हैं और तदानुसार भर्ती की गई है। कुछ मामलों में कहीं-कहीं थोड़ी कमी पिछले बैकलाग तथा योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण है। सरकार इसको पूर्ण करने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है और समय समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाये गये हैं तथा रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने

वाले अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये छः प्रशिक्षण केन्द्र विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं।

Amount received from World Bank for Desilting of Canals

***1223 Shri Om Parkash Beri :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state that the Circlewise and divisionwise details of the amount of the expenditure incurred on the maintenance and desilting of Canals, Minors and Drains etc. in the State out of the loan received from the World Bank during the period from 1-4-95 till todate ?

Irrigation Minister (Sh. Jagdish Nehra) : The circle-wise details of the amount of expenditure incurred on the maintenance and desilting of Canals, Minors and Drains, etc. in the State against World Bank Aided Water Resources Consolidation Project for the period 1-4-95 till to-date are enclosed in the attached statement.

STATEMENT

Statement of Expenditure incurred on the maintenance and Desilting of Canals, Minors and D rains from I-4.95 to-date.

Sr. No.	Name of Circle	Expenditure on maintenance and Desilting of Canals, Minors and D rains. Rs. lacs
------------	----------------	---

1	2	3
1.	Bhakra Wa ter Services Circle, Sirsa	63.69
2.	Bhakra Water Services Circle-I, H is a r	74.15
3.	Bhakra Water Services Circle-II Hisar	49.95
4.	Bhakra Water Services Circle, Kaithal	52.44
5.	S. Y.L . Water Services Circle, Ambala	25.50
6.	Yamuna Water Services Circle, Yamuna Nagar	4.02
7	Yamuna Water Services Circle,Karnal	64.47
8	Yamuna Water Services Circle, Jind	16.53
9.	Yamuna Water Services Circle Rohtak	37.71
10.	Yamuna Water Services Circle, Delhi	30.51
11.	Yamuna Water Services Circle. Faridabad	32.40
12.	Yamna Water Services Circle, Bhiwani	22.73
		473.66

	(A)-	
13.	Construction Circle, Kaithal	17.37
14.	Construction Circle, Kurukshetra	27.79
15.	Construction Circle, Karnal	
16.	Construction Circle, Panipat	135.83
17.	Construction Circle, Sonapat	48.38
18.	Construction Circle Gurgaon	117.50
19.	Construction Circle, Rohtak	19.18
	(B) -	366 .0 5
	Grand Total (A +B)	839.71

Supply of electricity to tubewells on concessional rates

* **1229. Shri Zile Singh** : Will the Minister for Power be pleased to state whether electricity is being supplied to the tubewells on concessional rates under the deep water scheme in the State, if so, the criteria fixed for the purpose ?

Power Minister (Sh. Verender Singh) : Yes Sir, Concessional tariff for supply of power to agricultural tubewells is applicable to those parts of the State where subsoil water is deep and scanty.

Misappropriation of funds

***1191. Dr. Ram Parkash :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any case of misappropriation of funds in the construction/repair of roads in Kurukshetra District against the officers/officials of Haryana State Agricultural Marketing Board has come to the notice of the Government during the period from 1990 to 1993 ; and

(b) if so the action, if any taken, against the officers/officials involved in the case as referred to in part (a) above.

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh) :

(a) Yes Sir, a case of misappropriation of funds in the construction/repair of roads in Kurukshetra District relating to Haryana State Agricultural Marketing Board came to the notice of the Government during the years 1990-93.

(b) The matter was got investigated by the Flying Squad of the Haryana State Agricultural Marketing Board and besides being placed under suspension, the concerned officers/officials were charge sheeted under rule 7 of the Punishment and Appeal Rules, 1987 for major penalty. The proceedings are in progress.

Separately, surcharge notices for recovery of loss were issued under section 29 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 against the erring officials.

Government got the matter investigated also by the State Vigilance Bureau and an F.I.R. No. 1 dated 02-02-93 was registered at Police Station, State Vigilance Bureau, Karnal. The case is now pending hearing in the Court of Chief Judicial Magistrate,

Kurukshetra.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Taking Over the Hospital of Vrrlage Thol

257. Dr. Ram Parkash : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the Hospital/Health Centre constructed by the Villagers of 'Thol', district Kurukshetra ;

(b) if so, the steps, if any taken c r proposed to **be** taken in this regard ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मन्त्री (बहन करतार देवी):

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Opening of Veterinary Hospitals

258. Dr. Ram Parkash : Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Veterinary Hospitals in any villages of district Kurukshetra, if so the names of the villages where said hospitals are likely to be opened.

Animal Husbandry Minister (Shri Ram Pal Singh Kanwar) : No Sir, there is no proposal under consideration of the Government to open Vety. Hospital in any villages of district Kurukshetra.

Construction of Roads in District Kurukshetra

259. Dr. Ram Parkash : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in district Kurukshetra :-

1. Badarpur to Bani ;
2. Jainpur to Brahan ; 3 Gharaula to Bhalri ;
4. Samalkha Gurdwara to S.K. road ;
5. Bhoot Majra to Murad Nagar ;
6. Main road between Mandi and School in Pipli ;
7. Jyotisar to Dhand road ;
8. Salarpur to Fattupur ;
9. Se K. road Dera Asha Singh Bii-Shonti ; and
10. Dayalpur to Alampur.

(b) if so, the time by which the construction work of the said roads is likely to be started/completed ?

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh) : a)&(b) Presently there is no proposal under consideration of the Board for the construction of above roads except the following :—

(i) Salarpur to Fattupur : Work on this road is in progress and is likely to be completed by 31-3-96.

(ii) Dayalpur to Alampur : Work on this road is likely to be started by November, 1995 and it is expected to be completed by March, 1996.

Construction of Houses under Indira Awas Yojana

260. Dr. Ram Parkash : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the districtwise number of houses constructed in rural areas under the Indira Awas Yojana during the period from 1991 to date in the State ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (राव बंसी सिंह) विवरण अनुबन्धमें दिया गया है।

अनुबन्ध

क्र० सं	जिले का नाम	निर्माण किये गये मकानों की संख्या
1.	अम्बाला	458
2.	भिवानी	558
3.	फरीदाबाद	517
4.	गुड़गांव	293
5.	हिसार	1276

6.	जीन्द	469
7.	करनाल	348
8.	कुरुक्षेत्र	286
9.	कैथल	441
10.	नारनौल	183
11.	पानीपत	305
12.	रोहतक	951
13	रिवाड़ी	216
14.	सिरसा	422
15	सोनीपत	297
16.	यमुनानगर	274
		7294

Installation of Anti-Pollution Devices

266 Prof . Chhattar Singh Chauhan : Will the Minister for Environment be pleased to state the names and addresses of the owners of stone crushers in the State who have not installed anti-pollution devices so far; together with the details of action taken in

this regard?

Minister of State for Forests (Rao Dharam Pal) : Names and addresses of stone crushers alongwith action taken against those which have not installed any pollution control devices so far, are given in Annexure .

ANNEXURE

**Name of Stone Crushers in the State which have not rnstalled
Air Pollutron Control-Measures**

Sr. No.	Name of Stone Crusher	Action Taken
1	2	3
1.	M/s. Shri Markanday Stone Crusher Vill. Dera, Tehsil Naraingarh	Closure order issued through D.C. Ambala.
2.	M/s. Yamuna Stone Crusher, Surajpur	Electric supply disconnected, but restored upto 30-11-95. on the basis of written undertaking to shift the crusher by that dead-line.
3.	M/s. Pehowa Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
4.	M/s Chandimandir Stone Crusher, Chandimandir.	—do—

5.	M/s. Kaushalya Stone Crusher, Chandimandir. .	—do—
6.	M/s. Kohinoor Stone Crusher, Chandimandir. .	—do—
7.	M/s. Supreme Stone Crusher, Village Kiratpur (Kalka).	—do—
8.	M/s. Janta Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
9.	M/s. Kaithal Stone Crusher, Surajpur	—do—
10.	M/s. Shree Krishna Construction Co., Surajpur.	—do—
11.	M/s. Anoop Stone Crusher, Chandimandir	—do—
12.	M/s. Shri Krishan Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
13.	M/s. A.K. Stone Crusher, Surajpur	—do—
14.	M/s. Lahori Lal and Co., Chandimandir.	—do—
15.	M/s. Kakar Stone Crusher, Surajpur.	—do—
16.	M/s. Bhagat Bhai Stone Crusher, Chandimandir.	—do—

17.	M/s. Sandeep Stone Crusher, Surajpur.	—do—
18.	M/s. Rampur Souri Stone Crusher, Surajpur.	—do—
19.	M/s. Krishna Stone Crusher. Chandimandir	—do—
20.	M/s. Shakti Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
21.	M/s. Durga Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
22.	M/s. Sita Ram Stone Crusher, Chandimandir.	—do—
23.	M/s. Ambika Stone Crusher, Panchkula.	Electric supply disconnected and the unit directed to shift from the existing site.
24.	M/s. Malwa Stone Crusher, Panchkula.	—do—
25.	M/s. Sarswati Stone Crusher, Pane hku la.	—do—
26.	M/s. Friends Stone Crusher, Panchkula.	—do—
27.	M/s. Capital Stone Crusher, Panchkula.	—do—

28.	M/s. Rama Stone Crusher, Panchkula .	—do—
29.	M/s. Gulati Stone Crusher, Panchkula.	—do—
30.	M/s. Haryana United Stone Crusher, Panchkula.	—do—
31.	M/s. Guru Nanak Stone Crusher, Panchkula.	—do—
32.	M/s. Dhillon Stone Crusher, Panchkula.	—do—
33.	M/s' Gupta Stone Crusher, Panchkula.	—do—
34.	M/s. Ghaghar Stone Crusher, Panchkula.	—do—
35.	M/s. Guru Tag Bhadur Stone Crusher, Panchkula.	—do—
36.	M/s. Rekhi Stone Crusher, Panchkula.	—do—
37.	M/s. New Shivalik Stone Crusher, Panchkula.	—do—
38.	M/s. New Anil Stone Crusher, Devi Nagar Panchkula.	Electric supply disconnected and unit directed to shift from the existing site.

39.	M/s. Raman Stone Crusher, Panchkula.	—do—
40.	M/s. Jai Bharat Stone Crusher, Panchkula.	—do—
41.	M/s. Garg Stone Crusher Co. Plot No. 67-D, Mohabatabad Zone, Fbd.	Closure order issued.
42.	M/s. New Sarswati Stone Crusher Co., Plot No 67, Mohabtabad Zone, Faridabad.	—do—
43.	M/s. Balaji Stone Crusher Co., Plot No. 83, Mohabtabad Zone, Faridabad.	—do—
44.	M/s. Bhagwati Stone Crusher Co. Plot No. 85, Mohabtabad Zone, Fbd.	—do—
45.	M/s. Krishna Stone Crusher Co., Plot No. 103, Mohabtabad Zone, Fbd.	—do—
46.	M/s-. Shiv Enterprises, Plot No. 81, Mohabtabad Zone, Faridabad.	Disconnection of electric supply directed.
47.	M/s. Darshan Lal Ahuja and Sons, Plot No. 41 Pali Zone, Faridabad.	Showcause notice issued regarding instal- lation of A.P.C.M.

48.	M/s. Gokal Chand Hari Chand, Plot No, 56, Pali Zone, Faridabad.	Non-applicant-show cause notice issued for applying for consent and regarding instal- lation of A.P.C.M.
49.	M/s Gurbax Singh and Sons, Plot No. 56E, Pali Zone, Faridabad.	Electric supply disconnected.
50.	M/s. Nav Nirman Stone Crushing Co., Plot No. 61E, Mohabtabad Zone, Faridabad.	Non-applicant-Show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
51.	M/s. Shri Ganesh Stone Crusher Co., Plot No, 74A, Mohabtabad Zone, Faridabad.	Non applicant-show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
52.	M/s. Chaudhry Stone Crusher Co., Plot No. 79, Mohabatabad Zone. Faridabad.	Showcause notice issued regarding installation of APCM.
53.	M/s. Adhla kha Stone Crusher Co., Plot No. 90, Mohabtabad Zone, Farida bad.	—do—
54.	M/s. Nirankari Stone Crushing Co., Plot No. 112, Mohabtabad	Non-applicant-show cause notice issued for

	Zone, Fbd.	applying for consent and regarding installation of APCM.
55.	M/s. Shree Geeta Stone Crusher Co ., Naurangpur Zone, Distt. Gurgaon.	Electric supply disconnected, but restored on the basis of written undertaking to installation of APCM.
56.	M/s. Blue Grit Udyog, Naurangpur Zone, Distt. Gurgaon.	Non applicant-show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
57.	M/s. Dagar Grit Udyog, Naurangpur, Gurgaon.	—do—
58.	M/s. Dharam Stone Crusher Co., Naurangpur, Gurgaon.	Electric supply disconnected.
59.	M/s Bharat Stone Crushing Co., Naurangpur. Distt. Gurgaon.	Showcause notice issued regarding installation of APCM.
60.	M/s. Rathi Stone Crushing Co., Naurangpur, Distt. Gurgaon.	Electric supply disconnected.

61.	M/s. Arawli Stone Crusher Co . Naurangpur, Zone, Gurgaon.	Electric supply disconnected, but restored on the basis of written undertaking regarding installation of APCM.
62.	M/s. New Maman Stone Crusher Co., Pur Zone, Gurgaor.	Showcause Notice issued regarding installation of APCM.
63.	M/s. New Sidhu Stone Crusher, Indri Zone, Gurgaon.	Closure order issued.
64.	M/s Mansa Devi Stone Crusher Co., Indri Zone, Gurgaon.	Non applicant. Show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
65.	M/s. Maa Durga Stone Crusher Co., Indri Zone, Gurgaon.	—do—
66.	M/s. Universal Stone Crusher Co.. Indri Zone, Gurgaon.	—do—
67.	M/s. Bharat Grit Udyog, Indri Zone, Gurgaon.	—do—
68.	M/s. New Delhi Stone Crusher. Indri Zone, Gurgaon.	—do—
69.	M/s. Dahiya Grit Udyog, Indri	—do—

	Zone, Gurgaon	
70,	M/s. H. M. Stone Crusher Co., Indri Zone, Gurgaon.	—do—
71.	M/s. Super Star Stone Crusher Co.. Indri Zone, Gurgaon.	—do—
72.	M/s. Upkar Stone Crusher Co., Rewasan Zone, Gurgaon.	—do—
73.	M/s. Ganga Stone Crusher Co., Rewasan Zone, Gurgaon.	—do—
74.	M/s. Chaudhry Stone Cruster Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
75.	M/s. Suman Stone Crushing Co., Rarsina Zone, Gurgaon.	—do—
76.	M/s. Hanuman Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
77.	M/s. Ganesh Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—
78.	M/s. New India Stone Crusher Co., Village Atta, Sohana, Gurgaon.	—do—
79.	M/s. Sheoram Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaon.	—do—

80.	M/s . Vikas Stone Crusher Co., Village Shikohpur, Gurgaon.	—do—
81.	M/s. Vishal Stone Crushing Co., Naurangpur.	Non-applicant. Show cause. Notice issued for applying for consent and regarding installation for APCM.
82.	M/s. Mahavir Stone Crushing Co., Naurangpur.	—do—
83.	M/s. Pooja Stone Crusher Co ., Naurangpur.	—do—
84.	M/s. Super Star Stone Crushing Co., Naurangpur.	—do—
85.	M/s. Fair Deal Stone Crushing Co., Re wasan.	—do—
86.	M/s Shiv Shankar Stone Crushing Co., Rewasan.	—do—
87.	M/s. Maa Shakti Stone Crushing Co., Rewasan.	—do—
83	M/s. Dahiya Stone Crushing Co., Village Indri.	—do—
89.	M/s. Delhr Stone Crushing Co., Village Indri.	—do—

90.	M/s. Ackta Stone Crusher Co., Raisina Zone, Gurgaone	—do—
91.	M/s. Marter Stone Crusher Co., Narnaul.	Electric supply already disconnected.
92.	M/s Bajrang Stone Crusher Co., Narnaul .	—do—
93.	M/s. Deepak Stone Crusher Co., Narnaul.	—do—
94.	M/s. Ambika Stone Crusher Co., Khanak.	Showcause notice issued for shifting.
95.	M/s. Durga Stone Crusher, Khanak.	—do—
96.	M/s. Govt. Stone Crusher, Khanak.	—do—
97.	M/s. Mahan Stone Crusher, Kapoori.	Showcause notice issued regarding instal- lation of APCM.
98.	M/s. Nalva Stone Crushers, Khanak.	Showcause notice issued for shifting.
99.	M/s. Nagpal Stone Cusher, Khanak.	—do—
100.	M/s. National Stone Crushers, Khanak.	—do—

101.	M/s. Punjab Stone Crushers, Khanak.	—do—
102.	M/s. Par bhat Stone Crusher, Khanak.	—do—
103.	M/s. Rajesh Stone Crusher, Khanak.	—do—
104.	M/s. Subhash Stone Crusher, Khanak.	—do—
105.	M/s. Sur bhi Stone Crushers, Khanak.	—do—
106.	M/s. Verma Stone Crushers, Khan ak .	—do—
107.	M/s. Vishwakarma Stone Crashers, Khanak .	—do—
108.	M/s. Haryana Stone Crushers, Tiwana .	—do—
109.	M/s. Ganga Jamuna Stone Crushers, Khanak.	Non applicant, show cause notice issued for applying for consent and regarding installation of APCM.
110	M/s. Raj Stone Crushers, Khanak.	—do-
111.	M/s. Krishna Stone Crushers, Nagina .	—do-

112.	M/s. Shiv Bhola Stone Crusher, Khanak.	Showcause notice issued regarding installation of APCM.
113.	M/s. Hisar Stone Crusher, Khanak.	Showcause notice issued for shifting.
114.	M/s. Sat Guru Stone Crusher, Khanak.	Showcause notice issued regarding installation of APCM.
115.	M/s. Anurag Stone Crusher, Khanak.	—do—
116.	M/s. Shiv Bhola Stone Crusher, Vill. Kheri Balla, Bhiwani,	—do—
117.	M/s. Shyam Stone Crushing Co.. Vill. Doiwala, Yamuna Nagar .	Electric supply disconnected .
118.	M/s. Lakshmi Stone Crushers, Vill. Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—
119.	M/s. walla Stone Crusher, Vill. Devdhar, Yamuna Nagar.	ShowCause Notice issued regarding installation of APCM.
120.	M/s. Satguru Stone Crusher, Mandal Vill. Doiwala, Yamuna Nagar.	Prosecution launched Case pending for hearing in Court of law.

121.	M/s. Continental Construction Co , Vill. Faizpur Near Tajewala, Yamuna Nagar.	ShowCause Notice regarding Installation of APCM issued,
122.	M/s. Sarswati Stone Crusher, Vill. Doiwala, Yamuna Nagar.	Prosecution launched case pending for hearing in Court of law.
123.	M/s. Garg Stone Crusher, Gulabgarh Yamuna Nagar.	—do—
124.	M/s. Shiwalik Stone Crusher, Gulabgarh, Yamuna Nagar.	Prosecution launched- case pending for hearing in Court of law.
125.	M/s. Paras Stone Crusher, Chuharpur Yamuna Nagar.	Showcause notice issued regarding instal- lation of APCM.
126.	M/s. Nirmal Honey Stone Crusher, Vill. Dorwala., Yamuna Nagar.	—do—
127.	M/s. Ganga Gram Udyog, Village Balla Majara, Yamuna Nagar.	—do—
128.	M/s. Universal Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar .	—do—
129.	M/s. Friends Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—

130.	M/s. Geeta Samiti Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—
131.	M/s. Nanak Stone Crusher, Doiwala, Yamuna Nagar.	—do—
132.	M/s. Sai Stone Crusher. Village Balla Majra. Yamuna Nagar.	Showcause notice issued regarding installation of APCM.
133.	M/s. Chaudhry Brothers Stone Crusher, Balla Majra, Yamuna Nagar.	—do—
134.	M/s. Haryana Grit Udyog, Balla Majra, Yamuna Nagar.	—do—
135.	M/s. Heera Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	Electric supply dis connected.
136.	M/s. Roop Kamal Stone Crusher, Village Doiwala, Yamuna Nagar.	Showcause notice issued regarding instal- lation of APCM.
137.	M/s. Durga Stone Crusher, Chuharpur, Yamuna Nagar.	Prosecution launched case pending for hearing in Court of law.

Expenditure incurred on the Council of Ministers

267 Prof. Chhattar Singh Chauhan : Will the Chief

Minister be pleased to state the monthwise total amount of expenditure incurred on account of telephone of the Chief Minister, each of the Minister and Minister of State installed at their residence, office and at Delhi during the period from July, 1991 to July, 1995 ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): दूरभाष किराए, स्थानीय काल्ज तथा ट्रक काल्ज के खर्चों के दिल दूर-संचार विभाग से द्विमासिक प्राप्त होते हैं। इस लिए प्रश्न के सम्बन्ध में द्विमासिक के आधार पर सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

Amount spent for Development Works

268 Prof. Chhattar Singh Chauhan : Will the Minister for Finance be pleased to state the details of the amount of Rs. 20 Lacs provided to each M.L.Ae in a financial year for the Development schemes of his area (through DeC. concerned) spent in each constituency of the State during the year 1994-95, 1995-96 ?

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : The statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

**Statement showing constituency wise details of funds released and utilised under MLA's
toe ala rea development scheme.**

(Rs. in Lacs)

Sr.	Noe Name of District	Name of Constituency		1994-95			1995-96		Remarks
			Funds released by the Govt.	Funds released by D.C's as per suggestions of MLA's	Funds Utilised (%age)	Funds released by the Govt	Funds released by D.C's as per suggestio ns of MLA's	Funds Utilised (%age)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AMBALA	Kalka	20.00	20.00	3.73 (1 8.6)	40.00	1.62		

		Naraingarh	20.00	20.00	10.58 (52.9)	40.00	-	-	
		Mulana	20.00	20.00	12.70 (63.5)	40.00	-	-	
		Ambala Cantt	20.00	20.00	5.21 (26.0)	40.00	-	-	
		Ambala City	20.00	18.00	11.26 (62.5)	40.00	-	-	
		Naggal	20.00	20.00	12.15 (60.7)	40.00	-		
		Total	120.00	118.00	55.63 (47.1)	240.00	1.62	-	
	YAMUNA NAGAR	Chhachhrauli	20.00	20.00	16.77 (83.8)	40.00		-	

		Jagadhri	20.00	20.00	18.13 (90.6)	40.00	-	-	
		Radaur	20.00	20.00	12.16 (60.8)	40.00	1.00	-	
		Yamunanagar	20.00	20.00	16.54 (82.7)	40.00	0.70	-	
		Sadhaura	20.00	20.00	16.61 (83.1)	40.00	2.00		
		Total	100.00	100.00	80.21(80.2)	200.00	3.70		
3.	KURUKSHETRA	Shahbad	20.00	20.00	16.06 (80.3)	40.00	1.33	-	
		Thanesar	20.00	20.00	10.39 (52.0)	40.00	-	-	

		Pehowa	20.00	17.55	9.92 (56.5)	40.00	-	-	
		Total	60.00	57.55	36.37(63.2)	120.00	1.33	-	
4	KAITHAL	Kalayath	20.00	20.00	5.78 (28.9)	40.00	-	-	
		Kaithal	20.00	20.00	15.52 (77.6)	40.00	-	-	
		Guhla	20.00	20.00	14.58 (72.9)	40.00	-	-	
		Pai	20.00	29.00	13.08 (65.4)	40.00	-	-	
		Pundri	20.00	20.00	12.58 (62.9)	40.00	9.00	-	

		Rajound	20 00	20.00	4 18 (20 9)	40 00	-	-	
		Total	120 00	120 00	65.72(54.8)	240.00	9.00	-	
	KARNAL	Indri	20 00	20.00	13.38 (66 .9)	40.00	19.30	-	
		Nilokheri	20.00	20.00	13.80 (69 .00)	40.00	14e75	-	
		Karnal	20.00	19.56	14.86 (76.0)	40 00	17.04	0.30 (1 .7)	
		Jund la	20e00	20 00	15.05 (75 e2)	40 00	19.50	-	
		Gharaunda	20.00	20.00	13e27 (66.3)	40 00	-	-	

		Assandh	20.00	20.00	11.70 (58.5)	40.00	20.00	3.20 (16.0)	
		Total	120.00	119.56	82.06(68.6)	240.00	90.59	3.50(3.9)	
	PANIPAT	Naultha	20.00	*	-	40.00	1.30	-	*Recommendations from MLA not received.
		Panip at	20.00	20.00	3.52 (17.6)	40.00	0.40	-	
		Samalka	20.00	20.00	9.62 (48.1)	40.00	7.22	0.15 (2.0)	
		Total	60.00	40.00	13.14(32.8)	120.00	8.92	0.15(1.7)	
	SONIPAT	Kailana	20.00	20.00	17.69 (88.5)	40.00	20.00	2.50 (12.5)	

		So nip at	20.00	20.00	1.65 (08.2)	40 00	12.25	2.75 (22.4)	
		Rai	20.00	*	-	40 00	20e00	4.50 (22 5)	*Recome ndations from
		Rohat	20.00	20 00	13.64 (68.2)	40.00	19.00	3e10 (16.3)	MLA not received.
		Barod a	20.00		-	40.00	20e00	1.00 (5.0)	
		Goh a na	20.00	20.00	7 73 (38-6)	40.00	14.41	2.05 (14.2)	
		Total	120.00	80.00	40 .71(50 .9)	240.00	105.66	15.90(15 .1)	
8.	ROHTAK	Hassangarh	20.00	14 06	0 75 (5 .3)	40.00	-	-	

		Kilo i	20 00	20e00	11.58 458 .0)	40.00	5.31	-	
		Rohtak	20.00	20.00	13.75 (68 7)	40.00	16.57	-	
		Meham	20.00	20 00	7.20 (36.0)	40.00	-	-	*Recomm endation s from
		Kalanaur	20.00	19.95	6.59 (33.0)	40.00	-	-	MLA not received and amount spent under D /Fig.
		Beni	20.00	19.83	3.03 (15.2)	40e00	-	-	
		Salhawas	20.00	1.50*	-	40 00	-	-	

		Jhajjar	20.00	8.07	0.01 (0.1)	40.00	-	-	
		Badli	20.00	16.50	0.26 (1.5)	40.00	-	-	
		Bahadurgarh	20.00	19.84	13.38 (67.4)	40.00	-	-	
		Total	200.00	159.75	56 .55(35.4)	400.00	21.88		
	FARIDABAD	ARIDABAD	20.00	20.00	3.34 (16.7)	40.00	20e00	-	
		Mewla Maharajpur	20.00	20.00	14.38 (72.0)	40.00	20.00	-	
		Ballabhgarh	20.00	20.00	15.55 (77.7)	40.00	20.00	0.75 (3.7)	

		Palwal	20.00	20.00	15.10 (75.5)	40.00	20.00	-	
		Hassanpur	20.00	20.00	11.09 (55.4)	40.00	20.00	-	
		Hathin	20.00	20.00	7.53 (37.6)	40.00	-	-	
		Total	120.00	120.00	66.99(55.8)	240.00	100.00	0.75(0.75)	
	GURGAON	Ferojpur Mirka	20.00	20.00	13.25 (66.2)	40.00	-	-	
		Nuh	20.00	20.00	13.76 (68.8)	40.00	-	-	
		Taoru	20.00	20.00	14.06 (70.3)	40.00	-	-	

		Sohna	20.00	20.00	16.47 (82 .3)	40.00	13.57	-	
		Gurgaon	20.00	20.00	16.65 (83.2)	40.00	11.59	-	
		Pataudi	20.00	20.00	18.10 (90.5)	40.00	-	-	
		Total	120.00	120.00	92.29(76.9)	240.00	25.16	-	
11 .	REWARI	Jatusana	20e00	20.00	7.58 (37 .9)	40.00	13.85	-	
		Bawal	20.00	20.00	3.30 (16 .5)	40.00	-	-	
		Rewarie	20.00	20.00	6.63 (33.2)	40.00	17.75	-	

		Total	60.00	60.00	17.51(29.2)	120.00	31 .60	-	
	MAHENDERGARH	Mahendergarh	20.00	1.50*	0.26 (17.3)	40.00	6.25	0.25 (4.0)	*Recommen- dations from MLA not
		Ateli	20.00	19.59	13.95 (71.2)	40 . 00	5.17	-	received and amount spent under D/Plg .
		Narnaul	20.00	19.87	7.88 (39.7)	40 00	1.30	-	
		Total	60.00	40.96	22.09(53.9)	120.00	12.72	0.25(2.0)	
	BHIWANI	Badhra	20 00	19.71	5.27 (26.7)	40 00	-	-	

		Dad ri	20e00	20 00	235 (81.7)	40.00	-	-	
		Mundhal Khurd	20.00	20.00	6.98 (34.9)	40.00	-	-	
		Bhiwani	20.00	19.82	8.61 (43.4)	40.00	-	-	
		Tosham	20.00	20.00	2 75 (13 .7)	40.00	-	-	
		Loh aru	20.00	19.66	8.29 (42.1)	40.00	-	-	
		Bawani Khera	20.00	18.10	5.48 (30.2)	40.00	-	-	
		Total	140.00	137,29	40.13(29.2)	280.00	-	-	

	JIND	Narwana	20.00	*	-	40.00	19.83	0.19 (0.9)	
		Uchana Kalan	20.00	20.00	11.84 (59.2)	40.00	19.95	-	*Recommendations from
		Jind	20.00	20.00	15.44 (77.2)	40.00	14.75	2.84 (19.3)	MLA not received.
		Juliana	20.00	*	-	40.00	12.48	-	
		Safidon	20.00	18.86	11.04 (58.5)	40.00	19.64	0.34 (1.7)	
		Total	100.00	58.86	38.32(65.1)	200.00	86.65	3.37(3.9)	
	HISAR	Barwala	20.00	15.70	3 (883.08)	40.00	20.00	-	
		Narnaund	20.00	17.00	13.18	40.00	0.00	-	

					(77.5)				
		Hansi	20.00	17.50	11.12 (63.5)	40.00	20.00	-	
		Bhattu Kalan	20.00	1.90*	1.90 (100.0)	40.00	20.00	-	*Recommendations of MLA not received and amount spent under D/Plg.
		Hisar	20.00	13.10	7.73 (59.0)	40.00	16.20	-	
		Ghirai	20.00	11.15	8.27 (74.2)	40.00	20.00	-	
		Tohana	20.00	19.45	7.38 (37.9)	40.00	20.00	-	
		Ratia	20.00	16.10	11.96 (74.3)	40.00	20.00	-	

		Fatehab ad	20.00	17.00	9.53 (56.0)	40.00	20.00	-	
		Adampur	20.00	20.00	20.00 (100.00)	40.00	0.00	-	
		Total	200.00	148.90	104.90(70.4)	400.00	156.20	-	
	SIRSA	Darba Kalan	20.00	*	-	40.00		-	*Recommendations from MLA not received.
		Ellenabad	20.00	20.00	11.15 (55.7)	40.00	18.22	1.33 (7.2)	
		Sirsa	20.00	20.00	15.85 (79.2)	40.00	2.00	-	
		Rori	20.00	20.00	13.02 (65.1)	40.00	-	-	
		Dabwali	20.00	20.00	10.27	40.00	8.50	-	

					(51.3)				
		Total	100.00	80.00	50.29(62. 8)	200.00	28 72	1.33 (4.63)	

Expenditure incurred on electricity bills of S.P Faridabad

271. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the monthwise expenditure incurred on account of electricity bills of residence/camp office of S.P. Faridabad during the period from July, 1994 to July, 1995 separately ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): पुलिस अधीक्षक फरीदाबाद के निवास स्थान/ कैम्प कार्यालय पर जुलाई, 1994 से जुलाई, 1995 तक (मास अनुसार) बिजली के बिलों का खर्चा निम्न प्रकार है:—

समय अवधि	खर्च
6 / 94 और 7 / 94	3450-00 रूपये
8 / 94 से 7 / 94	10882-00 रूपये
12 / 94 से 1 / 95	6362-00 रूपये
2 / 95 से 3 / 95	6155-00 रूपये
4 / 95 से 5 / 95	6124-00 रूपये
6 / 95 से 7 / 95	7588-00 रूपये
	40561-00 रूपये

Recruitment of Constables in Haryana Police Department

272. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any recruitment of Constables in Police Department has been made in the State during the period from August, 1991 to date; if so, the names and addresses of the persons so recruited ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वांछित सूचना हरियाणा विधान सभा पटल पर रखी जाती है। पुलिस विभाग के भिन्न भिन्न यूनिटों द्वारा भर्ती किये गये जवानों के नाम पते आदि के विवरण को उपलब्ध करवाने में जो परिश्रम एवं समय लगेगा उसके अनुपात में मांगी गई सूचना से लाभ नहीं होगा।

विवरण

पुलिस विभाग में अगस्त 1991 से आज तक की गई भर्ती के बारे में सूचना

क्र० सं०	जिला / यूनिट	वर्ष 1991	वर्ष 1992	वर्ष 1993	वर्ष 1994	वर्ष 1995	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अम्बाला	-	164	12	16	13	205
2.	कुरुक्षेत्र	-	59	1	12	24	96

3.	कैथल	2	80	2	10	15	109
4.	यमुनानगर	2	36	2	6	9	55
5.	सोनीपत	3	36	5	14	20	78
6.	पानीपत	-	64	2	2	15	83
7.	करनाल	3	102	4	9	11	129
8.	रोहतक	2	38	6	15	16	77
9.	गूडगावां	3	15	5	10	26	59
10.	रिवाड़ी	-	33	-	4	11	48
11.	नारनौल	-	67	-	11	14	92
12.	फरीदाबाद	-	31	4	12	20	67
13.	हिसार	3	327	3	18	20	371
14.	सिरसा	3	133	3	15	23	177
15.	भिवानी	-	38	7	7	23	74
16.	जीन्द	3	95	2	9	9	118
17.	पंचकुला	-	-	-	-	-	-

18.	रेलवेज	4	54	2	2	6	68
19.	दूरसंचार	2	63	3	5	3	76
20.	कमाण्डो करनाल				5	8	13
21.	कमाण्डो हिसार	-	364	5	2	3	374
22.	प्रथम वाहिनी	272	84	3	10	-	369
20.	द्वितीय वाहिनी	366	124	10	-	360	860
24.	तृतीय वाहिनी	358	85	1	-	138	582
25.	चतुर्थ वाहिनी	613	139	7	13	230	1002
26.	पंचम वाहिनी	30	246	29	7	225	537
	कुल योग:	1669	2477	117	214	1242	5719

Development of Colonies

**273. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief
Minister be pleased to state—**

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to allow the farmers/land owners to develop residential/ Commercial Colonies on their own land in the State ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal) :

(a) No, Sir. It is, however, pointed out that a land owner can convert his land into a colony in urban areas and controlled areas in accordance with the provisions of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act 1975 and the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963.

(b) Does not arise

Number of Schools Upgraded

274. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Education be pleased to state the number of schools, if any, upgraded in district Faridabad during the year 1994-95, togetherwith the names thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना): वर्ष 1994- 95 में जिला फरीदाबाद में स्तरोन्नत किये गये 12 स्कूलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

प्राथमिक से माध्यमिक		माध्यमिक से उच्च		उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक	
1.	बरोली (कन्या)	1.	मुजेसर	1.	बल्लबगढ़ (कन्या)
2.	सरूरपुर	2.	बरोली		
3	पी०एस० लखनाका	3	भुआपुर		
4	थूमसरा	4.	फतेहपुर तेगा		
5.	मांगर	5	छांयसा		
		6.	हुरीथल		

Augmentation of Water Supply of village Thua

269. Shri Ram Kumar Katwal : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the water supply of village Thua of District Kaithal, if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): गांव थुआ, जीन्द जिले में पड़ता है न कि कैथल जिले में। इस गांव में पेयजल सुधार के लिये एक अनुमान स्वीकृत किया जा चुका है

और कार्य प्रगति पर है। वह कार्य 31-3-97 तक पूर्ण होने की संभावना है।

Construction of Retaining Walls

270. Shri Ram Kumar Katwal : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the retaining walls on the ponds located on the sides of the roads at village Alewa, Katwal, Naguran. Diluwala, Popra and Rajaund of Districts Jind/ Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the retaining walls as referred to in para (a) above are likely to be constructed ?

लोकनिर्माण (बी० एण्ड आर०) मन्त्री (चौधरी अमर सिंह):

(क) गोदें राजौंद कैथल-राजौंद-असंधा सड़क पर रु० 54,500/- की लागत से रिटेनिंग वाल का निर्माण करने का प्रस्ताव था परन्तु इस रिटेनिंग वाम का निर्माण ब्लाक डिवैलपमेंट एण्ड पंचायत अधिकारी, राजौंद हारा किया गया है। इस समय गांव अलेवा, कटवाल, नगूरा, दिलुवाला और पोपड़ा में सडकों पर तालाबों के साथ रिटेनिंग वान्ज का निर्माण करने, का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Strength of Students/JBT Teachers in Schools

275. Shri Azmat Khan : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of students admitted in the schools of Nuh, Nagina, Ferozepur Jhirka, Punhana, Taoru and Hathin blocks during the current academic year upto 15th May, 1995: and

(b) the number of sanctioned posts of JBT teachers in the schools as referred to in part (a) above together with the number of posts lying vacant therein at present ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूलचन्द मुलाना): (क) मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है

क्रंमाक	ब्लाक	दाखिल किये गये बच्चों की संख्या		
		कक्षा 1 - 5	कक्षा 6- 12	कुल
1.	हथीन	2890	3699	6599
2	नूह	1521	2313	3834
3.	पुन्हाना	1173	1949	3122

4.	फिरोजपुर सिरका	12 85	1178	2463
5.	नगीना	704	1056	1760
6.	तावडू	1552	2293	3845

(ख) मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है:---

क्रमांक	ब्लाक	जे. बी. टी. के स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	हथीन	413	65
2	नूह	142	22
3.	पुन्हाना	182	65
4.	फिरोजपुर सिरका	132	52
5.	नगीना	124	25
6.	तावडू	204	36

Outstanding Amount of Electricity Bills

276. Ch. Om Parkash Beri : Will the Minister for

power be pleased to state—

(a) the total amount of arrears on account of electricity bills outstanding against various Government Departments/Boards/ Corporations, industries and Agriculture Sector separately as on 30-6-95; and

(b) the steps taken if any, or proposed to be taken to recover the outstanding amount as referred to in part (a) above.

Power Minister (Sh. Verender Singh) :

(a) The amount of arrears on account of electricity bills ending 30-6-95 category wise were as follows :

Industries	= Rs. 5912.08 lakhs
Agriculture	= Rs. 3709.64 lakhs
Irrigation Deptt .	= Rse 3567.73 lakhs
IISMITC	= Rs. 630.89 lakhs
Public Health	= Rse 294.41 lakhs
Municipal Committees	= Rs. 86.15 lakhs
Panchayats	= Rs. 108.95 lakhs

(b) Following steps are being taken to recover the outstanding amounts :—

(i) A special campaign has been launched to disconnect defaulting consumers and to effect recovery of outstanding bills. Progress on this account is monitored at

headquarter level every week.

(ii) The progress of recovery of defaulting amount is monitored at highest level.

(iii) Due to vigorous follow up with the State Government, the Board has received Rs. 373.13 crores out of a total claim of Rs. 412 .53 crores outstanding against Irrigation Deptt., HSMITC, Public Health and Municipal Committees. Besides, Sub Divisional Officers have been authorised to disconnect the supply of defaulting Government/ Semi-Government departments to effect the recovery of energy bills promptly.

(iv) Divisionwise targets for revenue assessed and realised have been fixed and are being monitored to avoid accumulation of arrears.

(v) To settle disputed cases, Negotiation Committees have been activated at Headquarter/Zonal/Circle level. Superintending Engineers (OP) have been delegated powers to decide disputed cases to mop up recovery.

(vi) As an incentive, Chief Engineers (Operation) have been allowed 1% of the amount recovered as penalty towards theft of electricity and recovery of defaulting amount to be spent on services concerned viz. hrring of vehicles etc. as well as for cash awards.

Recruitment of Constables

277. Ch. Om Parkash Beni : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of candidates recruited as constables, drivers etc. in various wings of the Police

Department from 1-5-95 till to date together with the names and addresses thereof ?

Chief Minister (Ch Bhajan Lal) : The information regarding unitwise recruitment of constables as placed on the table of the House

The time and labour involved in collecting names and addresses of the persons recruited as Constables in various wings of Haryana Police will not be commensurate with any possible benefit sought to be derived.

Information regarding recruitment of constables in different wings of Haryana Police during the period from 01-05-95 to date

S No.	Distt/ Unit	Total recruitment
1.	Panchkula	-
2.	Ambala	7
3.	Kurukshetra	22
4.	Kaithal	13
5.	Yamunanagar	8
6.	Panipat	15
7	Karn al	9
8.	Sonepat	20

9.	Rohtak	15
10.	Gurgaon	21
11.	Rewari	11
12.	Narnaul	9
13.	Faridabad	20
14.	Hisar	20
15.	Bhiwani	20
16.	Sirsa	23
17.	Jind	9
18.	Telecom	2
19.	Commando/KNL	8
	Commando/HSR	-
	Railways	6
	1st Bn HAP	-
	2nd Bn. HAP	360
	3rd Bn. HAP	136
	4th Bn. HAP	230
	5th Bn HAP	224
	Total	1208

अध्यक्ष द्वारा आबजर्वेशन—

15.00

राज्य में आई बाढ़ पर बहस होने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hona'ble Members, there have been heavy floods in the State and I have received different adjournment motions, calling attention motions and also motion under Rule 84 from different members and from different parties I have clubbed them all together. This was also discussed in the Business Advisory Committee, in which the leader of the House as well as leaders of Janata Party and Haryana Vikas Party were also present and after discussion it was decided that there should be discussion on floods for two days Hence, after clubbing a together, I allow that there shall be discussion for two days, its., for today and tomorrow also First of all, the business of the Government, which has already been listed, shall be transacted.

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में यह फैसला लिया गया था कि बाढ़ पर दो दिन डिस्कशन होगीं लेकिन उस फैसले को आज चार दिन हो गए हैं और उस वक्त सरकार को भी उम्मीद थी कि इन दिनों में पानी कुछ उतर जाएगा और स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आज उससे भी बदतर हालात हो गए हैं। आज पानी और भी कई नए एरियाज में घुस गया है, स्थिति और भी खराब हो गई है।

आप बहस दो दिन की बजाए चार दिन कर दें। आज शायद ही कोई ऐसा एरिया है जहां पर पानी न भरा है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हर सदस्य बोलना चाहेगा। एजण्डे पर जो सरकार बिजनैस है, हम उसको पास करने को तैयार है लेकिन आप बाढ़ पर डिस्कशन दो दिन की बजाए चार दिन कर दे।

श्री अध्यक्ष: आप रिपीट न करे।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात पर पौर करें।

प्रो० राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक फर्माया है कि बिजनेस ऐडबाईजरी कमेटी में हमारे, विपक्ष के नेता और सरकार के बीच में यह अन्डर स्टैन्डींग हुई थी कि दो दिन बाद पर बहस होगी। लेकिन आज हालात शराब हो गए हैं इसलिए वो दिन का समय बाढ़ पर चर्चा के लिए कम है। प्रो० सम्पत सिर जी ने भी यही कहा है कि यह समय कम है। सर जिस तरह से प्रदेश में बाढ़ आयी है, उसके हिसाब से अमर चर्चा करने लगे तो बहुत समय चाहिए क्योंकि एक गांव की चर्चा करने में ही घंटों लग जाते हैं। इसलिए सर, इस समय को माप बढ़ाए और कोई जल्दी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हमने एडनर्नमेंट मोशन दिए हुए हैं इसलिए इस महान सदन का प्रौसिजर तो यही है कि क्वेश्चन ओवर के तुरन्त बाद पहले यह मोशन लिया जाता है। सर, सरकार का जो बिजनैस है वह तो

रस्मी है। जब हम सभी बाढ़ पर चर्चा कर लेगे, उसके बाद जैसा विपक्ष के नेता ने कहा है कि 15 मिनट में सरकार का यह बिजनैस हम पास करवा देंगे। परन्तु सर, बाढ़ पर चर्चा पूरे विस्तार से होनी चाहिए। यह किसी के रहमोकरम की बात नहीं है और इससे सरकार को भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। बाढ़ के कारण लोगों को दुख दर्द झेलने पड़े हैं, उसकी चर्चा तो कम से कम इस महान सदन में होनी ही चाहिए और उसके लिए खुला समय रखा जाना चाहिए। तथा कोई भी समय सीमा नहीं होनी चाहिए, चाहे रात के 12 बजे तक चर्चा चले। जब तक सदस्य चर्चा करना चाहे, वह होनी चाहिए। ऐसी प्रथा भी आपको डालनी चाहिए कि रात के 12 बजे तक चर्चा चले। मैंने भी और दूसरे अन्य सदस्यों ने भी बाढ़ के बारे में एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, उनको आपको पहले टेक-अप करना चाहिए, यही मेरी हम्बल सबमिशन है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सारे सदन को बसाया कि बी० ए० सी० में इस बारे में डिटेल् से डिसकशन हो गयी थी और चौधरी बंसी लाल जी ने बाढ़ पर चर्चा करवाने के लिए दो दिन का समय रखने की बात कही थी। उस समय सम्पत सिंह जी ने तो एक दिन के लिए भी नहीं बोला था। ये स्वयं यहां हाउस में बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये बता दे। (शोर) आप अखबार वालों की तरफ क्या देख रहे हैं? आपने तो उस दिन बाढ़ पर चर्चा करवाने के समा के बारे में निक तक भी नहीं तिया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे अचम्भा

तो इस बात का है कि ये तो आज इस्तीफा देने ना ले थे लेकिन यें तो यहां पर बैठे हैं। क्या इन पर प्रदेश की जनता और अखबार वाले विश्वास करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इनको तो पता था कि अभी एक और सैशन होना है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने पहले भी एक बार इस्तीफा दिया था लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी ये एम० एल० ए० शिप की सारी सुविधाएं लेते रहे। हमें तो इनकी बातों पर रहम आता है। बी० ए० सी० की मीटिंग में चोधरी बंसी लाल जी ने बाद पर चर्चा के लिए लिए दो दिन के समय का प्रस्ताव किया था आर हमने एक सैकेन्ड भी नहीं लगायी तथा कहा कि ठीक है प्रदेश में बहुत भयंकर बाढ़ आयी हुई है, इसलिए इन्होंने जो दो दिन की बात कही थी, उसको हमने मान लिया था आप पहले बाढ़ पर डिसकशन कर लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, अभी मुख्य मती जी ने इस्तीफा देने की बात कही है। इसमें कोई दो राय नहीं है और हम आज भी अपने स्टैंड पर दृढ़ हैं। हमने कहा था कि अगर 23 तारीख तक सरकार ने यमुना ऐकोर्ड को कैंसिल नहीं किया तो हम उसके बाद इस्तीफे दे देंगे। लेकिन इस बीच यमुना के पानी को भी और इस सरकार को भी यह बाढ़ ले डूबी। इसलिए अगर हम ऐसी परिस्थितियों में इस्तीफे देकर जाते हैं तो हरियाणा के लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। स्पीकर सर, आज कुदरत और सरकार दोनों मिलकर हरियाणा के लोगो को मार रहे हैं इसलिए

हम इनकी पूरी खिचाई करेंगे, लेकिन हमारा इस्तीफे देने का वह स्टैंड आज भी वही है और वह काम भी हम करेंगे,। स्पीकर सर, आज हालात ऐसे पैदा हो गथे हैं कि इस बाढ़ ने हरियाणा के लोगों को पूरी तरह से डूबो दिया है। सर, जहां तक पहले इस्तीफे देने की बात थी, अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो फिर पेंशन मिलती है और अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो सैलरी मिलती है। इन दोनों में एक लेने के लिए एम०एल०ए० एनटाइटलड होता है। हर मैम्बर उस समय भी किसी न किसी कमेटी का मैम्बर था लेकिन उस समय हमने कोई भी टी०ए०/डी०ए० नहीं लिया था। जब पेंशन नहीं थी तो सैलरी लेनी पड़ती है, दोमों में एक तो लेनी पड़ती है सर, उस समय यही बात थी। हम इन को ऐसे ही नहीं चलने देगे, जब हरियाणा प्रदेश के इंटरस्ट पर वे चोट मारेंगे तो उस समय हम हर वक्त तैयार रहेंगे लेकिन बाढ़ के मामले में हम पहले इनकी कुर्बानी लेगे।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में यह भी तय हुआ था कि जिन-जिन सदस्यों की कंस्टीच्यूएन्सी में बाढ़ आई है, उन सबको बोलने के लिए रीजनेबल टाईम दिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, आप टाईम तय कर दीजिए। तकरीबन सभी मैम्बरों के हल्के में वाड आई है, दो दिन

में जितना बोलना चाहते हैं उतना टाइम बांट दीजिए। इस साइड में और उस साइड में सबको बराबर बोलने का आइ प्रकार है।

श्रीमती चद्रावती: स्पीकर सर, मेरे हल्के में तो बाद आई ही है, मेरे घर में भी बाढ़ है।

चौधरी बंसी लाल: आपकी पार्टी के लोगों को बोलने का पूरा अधिकार है लेकिन में समझता हूँ कि हम लोगों को बोलने का ज्यादा अधिकार है, आप लोगों को तो आराम से हमारी बातें सुननी चाहिए। कोई मैम्बर कम बोलेगा, कोई ज्यादा बोलेगा, और रात के 12 बजे तक अगर हाउस बैठे तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। टाइम के झगड़े में मुख्य मती जी क्यों पड़ते हैं?

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, मैंने आपकी सेवा में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं।

श्री अध्यक्ष: उनके बारे में आप बाद में पूछिए, अब सिर्फ यही सब्जेक्ट है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: स्पीकर सर, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में 26 और 27 सितम्बर यानी दो दिन वादु पर चर्चा के लिए मुकर्रर हुए थे। किसी भी विधान सभा का अधिवेशन औपचारिकता निभाने के लिए नहीं होता। इसमें प्रौब्लम डिसकस करनी होती हैं। पूरी स्टेट में बुरी तरह से फ्लड आया हुआ है, हमारे रोहतक जिले के 6 हल्के तो पूरी तरह से

बाढ़ के अन्दर है। यहां पर आम तौर पर टाईम उन लोगों को मिलता है जो पौलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं। हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं.....। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आपको भी बोलने का टाईम दिया जाएगा।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: स्पीकर सर, मेरी सबमीशन है कि बाढ़ पर चर्चा के लिए कम से कम चार दिन का समय रखे ताकि हर हल्के के लोग अपनी अपनी बात कह सकें और अपने सुझाव दे सकें कि किस तरीके से फ्लड पर कंट्रोल किया जा सकता है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। दो दिन में इस सेशन को खत्म करने की बात क्यों की जा रही है?

ध्यानाकर्षण सूचनाए

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में 20 तारीख को दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे हैं। एक तो पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो जी० टी० रोड और शडचूल रोड है, उनके निकट बने मकानों के बारे है। (विधन)

श्री अध्यक्ष: यह अंडर कंसीड्रेशन हैं।

डा० राम प्रकाश: दूसरा जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है वह है कुरुक्षेत्र से एक यात्रियों की बस हरिद्वार नेपाल जा रही थी जिसमें 55 आदमी डूबकर मर गये। (विधन)

श्री अध्यक्ष: यह भी अंडर कंसीड्रेशन है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर सर, मेरा भी काल अटैन्शन मोशन बाढ के०पर है। मेरे दादरी हल्के में बाढ आई है और मेंरे घर मे भी बाढ है, आन तक पानी खड़ा है।

श्री अध्यक्ष: आपको टाईम मिलेगा, आप उस वक्त बोलिए।

श्री अतर सिंह: अध्यक्ष महोदय, कादमा कांड से सम्बन्धित मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: यह सरकार की कमैन्टस के लिये भेजा हुआ है। जब वहां से जवाब आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा।

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह व मैंने भी कादमी कांड के सम्बन्ध में एक काल अटैन्शन मोशन दिया था। (शोर)

श्री अध्यक्ष: सरकार से जब इस का जवाब आ जाएगा तो आपको सूचित कर दिय जाएगा।

प्रो० छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में मेरा एक काल अटैन्शन मोशन था। वहां पर आठ आठ फुट बाढ का पानी भरा पड़ा है जिस के कारण आस पास के गांव में बड़ा भारी तनाव इस सरकार से पैदा कर रखा है। इम बारे में स्थिति बता दीजियेगा कि इसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष: कब दिया था आपने यह कात अटैन्शन मोशन?

प्रो० छतर सिंह चौहान: आज दिया था, जी।

Mr. Speaker : Please take your seat. How can I reply it While sitting here in the House ?

घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष

(1) पैनल आफ चेयरमैन

Mr. Speaker : Hon'ble Members under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairmen :—

1. Smt. Chandravati.
2. Shri Mani Ram Keharwalat
3. Shri Dhir Pal Singh.
4. Prof. Chhattar Singh Chauhan

(2) कमेटी आन पैटीशंज

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

1. Shri Sumer Chand Bhatt Ex-officio

Deputy Speaker.

Chairman

2. Shri Brij Anand, M.L.At

Member

3. Shri Mani Ram Keharwala, M.L.At

Member

4. Prof. Chattar Singh Chauhan, M.L.A.

Member

5. Shri Jai Pal Singh, M.L.At Member

(ख) सचिव द्वारा—

*राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गये बिलों
सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now the Secretary will make
announcement.

सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने
वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 1995 में
हुए बजट सत्र में पारित किये थे तथा जिन पर राष्ट्रपति /
राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सदन की मेज पर रखता
हूँ:—

Statement

1. The Haryana Legislative Assembly (Allowances

and Pension of Members) Amendment Bill, 1995.

2. The Haryana Municipal Corporation
(Amendment) Bill 1995.

3. The Haryana Municipal (Amendment) Bill,
1995.

4. Pandit Bhagwat Dayal Sharma Medical College,
Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill,
1995.

*5. The Punjab Bhudan Yagna (Haryana
Amendment) Bill. 1995.

6. The Haryana General Sales Tax (Amendment)
Bill, 1995.

*7. The Punjab Scheduled Roads and Controlled
Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana
Amendment) Bill, 1995.

8. The Haryana Co-operative Societies
(Amendment) Bill, 1995.

9. The Punjab Pre-emption (Haryana Amendment)
Bill, 1995.

10. The Haryana Appropriation (No.1) Bill, 1995.

11. The Haryana Appropriation (No.2) Bill, 1995.

12. The Haryana Tax on Luxuries (Repeal) Bill.
1995.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advrsory Committee :-

"The Committee met at 10.00 A.M. on Friday the 22nd September, 1995 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Friday, the 22nd September, 1995 and on Tuesday, the 26th September, 1995 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Wednesday, the 27th September, 1995 and Thursday, the 28th September, 1995 at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M.

The Committee also recommends that on Friday, the 29th September, 1995, Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day without question being put.

The Committee after some discussion further recommends that the business on 22nd September, 1995 and from 26th September, 1995 to 29th September, 1995, be transacted by the Saba as follows :—

Friday, the 22nd September, 1995 (2.00 P.M.)		Obituary References.
Saturday, the 23rd September.		Off day

1995		
Sunday, the 24th September, 1995		Holiday
Monday, the 25th September, 1995		Holiday
Tuesday, the 26th September. 1995	1.	Questions Hour.
2.00 p.m .)	2,	Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
		Papers to be laid on the Table of the House.
		Presentation of excess demands over grants and appropriations for the year 1989-90.
		Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
		Any other Business.

Wednesday, the 27th September, 1995	1.	Questions Hour.
(9.30 a.m.)		Motion under Rule 30.
	3.	Any other Business
Thursday, the 28th September, 1995 (9.30 A.M.)		Questions Hour, Discussion and voting on the excess demands over grants and appropriations for the year 1989-90.
		Legislative Business.
Friday, the 29th September, 1995	1 .	Questions hour.
(9.30 a.m.)	2.	Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting.
	3.	Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-diet
	4	Appropriations Bill in respect of excess demands over grants and appropriations for the year 1989-90.
		Legislative Business.

		Any other Business."
--	--	----------------------

Now, the Irrigation Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee,

The motion was carried

सदन की मेज पूर रखे गये / पुनः रखे गये कांगज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the table on the House.

Irrigation Minister : Sir I beg to lay on the Table-

1. The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 4 of

1995).

2. The Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 5 of 1995).

3. The Haryana Service of Engineers. Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) Respectively Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance Not 6 of 1995).

4. The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance Not 7 of 1995).

5. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance Not 8 of 1995).

6. The Punjab Courts (Haryana Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 9 of 1995).

7. The General Administration Department (General Services) Notification Not G S R. 38/Const./Art. 320/Amd. (3)/95, dated the 18th April, 1995 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1995 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

8. The General Administration Department Notification No.G.S.R. 56/Const./Art. 320/Amd.(1)/95 dated the 28th July, 1995 regarding the Amendment in Haryana Government, General Administration Department notification No. G. S. R.1. Const /Art. 320/Amd. (4)/95, dated the 4th January. 1995 as required under Article 320 (5) of the

Constitution of India.

9 The General Administration Department Notification No. G.S.R.57/Const./Art.320/Amd. (2)/95, dated the 28th July, 1995 regarding the Amendment in the Haryana Government, General Administration Department, notification Not G.S.R.2/Const./Art. 320/Amd. (5)/95, dated the 4th January 1995 as required under Article 320(5) of the Constitution of India

10. The General Administration Department Notification No. G S.R.58/Const./Art' 320/Amd' (4)/95, dated the 28th July, 1995 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1995 as required under Article 320(5) of the Constitution of India

11. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 39/H.A.20/73/S.64/95, dated the 21st April, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

12. The Excise and Taxation Department Notification Not G S.R.47/H.A.20/73/S64/95. dated the 9th June, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973'

13. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 48/HA20/73/S.64/95, dated the 14th June, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64(3) of

the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

14. The Grant Utilisation Certificate and Audit Report for the year 1991-92 of the Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

15. The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1991-92 as required under Section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

16. The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 1991-92 as required under Section 19A (3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Condition of Service) Act, 1971.

17. The 27th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1993-94 as required under section 69 (5) (a) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

18. The Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1995-96 and revised Estimates for the year 1994-95 as required under Section 61(3) of the Electricity (Supply) Act, 1948,

19. The 27th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1993-94 as required under Section 619-A(3) Companies Act, 1956

20. The Report on the Accounts of Haryana

Financial Corporation for the year ended 31st March, 1993 as required under Section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

21. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1991-92 as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

22. The 21st Annual Report of the Haryana Tanneries Limited for the year 1992-93 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

23. The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the years 1983-84 to 1989-90 as required under Section 19A (3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

24. The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1993-94 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

25. The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1993-94 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

26. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1994 No. 3 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

वर्ष 1989- 90 के लिये अनुदानों तथा वि-नि-योजन?एं से
अधिक मांगे प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the excess demands over grants and Appropriations for the year 1989-90.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to present the excess demands over Grants and Appropriations for the year 1989-90.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा
अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(1) श्री सम्पत सिंह, एम०एल०ए० तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now, Shri Sher Singh, M.L.A., Chairman, Committee of Privileges will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A., against Shri Sampat Singh, M.L.A. and Leader of Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various newspapers on 4th March, 1993 and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Shri Sher Singh (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the

question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A. against Shri Sampat Singh, M.L.A. and Leader of Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various "newspapers on 4th March, 1993.

Sir, **I** also beg to move—

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session

Mr Speaker : Question is -

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried

(2) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Sher Singh M L A. Chairman Committee of Privileges will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan, M L A., against Shri Karan Singh Dalal M L.A for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas,

Shakrulla Khan, Mahender Partap Singh, Raj Kumar, Dharambir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala. and Chhattarpal Singh etc in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March, 1993 and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Shri Sher Singh (Chairman Committee of Privileges)
: Sir. I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan M L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M L.A. for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties in the presence of Sarvshri Mohd, Ilyas, Shakrulla Khan, Mal ender Partap Singh, Raj Kumar Dharambir Gauba . Joginder Singh. Mani Ram Keharwala and Chhattarpal Singh etc. in the lobby of the House at about 3 00 P.M on the 11th March 1993.

Sir, T also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of next Session

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final

Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried

(3) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल० ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Sher Singh, M.L.A. Chairman, Committee of Privileges will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. in respect of persisting to level false and baseless allegations against the Leader of the House on palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive then the factual position was already clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Shri Sher Singh (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I bag to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. in respect of persisting to level false and baseless allegations against the Leader of the House on palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was already clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried

(4) चौधरी ओम प्रकाश चोटाला, एम० एल० ए० के
विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Sher Singh M.L.A. Chairman, Committee of Privileges will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. for making false and wrong statement on the floor of the House on 14th September, 1994, that he was honorably acquitted in the case of seizure of watches by the Custom Authorities and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Shri Sher Singh (Chairman Committee of Privileges)
: Sir. I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jadish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Om Parkash Chautala M.L.A. for making false and wrong statement on the floor of the House on 14th September, 1994. that he was honorably acquitted on the case of seizure of Watches by Custom Authorities.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session

The motion was carried

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—

राज्य में आई बाढ सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, as announced earlier that various notices of adjournment motions, Calling Attention Motions and motions under Rule 84 have been reserved from various members which have been clubbed together and converted into Motion under rule 84, Now Shri Om Parkash Chautala may move his motion under rule 84 which has been given by him and other 26 M.L As.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य में हाल ही में उत्पन्न गंभीर स्थिति से हुए नुकसान पर तुरंत चर्चा की जाए।

Mr. Speaker . Motion moved -

That the serious situation that has arisen on account of recent floods in the State and the substantial damage caused by it, be discussed.'

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में भयंकर बाढ़ से बहुत अधिक नुकसान हुआ है जिसकी वजह से सारे प्रदेश का सारा सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया और आवागमन के सारे रास्ते अब भी रुके पड़े हैं। गावों में अभी तक गढ़ का पानी खड़ा है फसले बर्बाद हो गईं और यह भी उम्मीद नहीं है कि रबी की फसल की बुआई हो सकेगी या नहीं। सरकारी आकड़ों के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के 16 के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 2840 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 20 लाख 35 हजार 68 एकड़ रकबा बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है जिसमें से 16 लाख 55 हजार 88 एकड़

में फसल बर्बाद हुई। 28 लाख 87 हजार 657 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 2 लाख 21 हजार 578 घर डैमेज हुए हैं। 3157 पशु मरे दिखाए गए हैं और 168 आदमियों की जाने गई हैं। सरकार ने 321 रिलीफ कैम्प खोले जिनमें 1 लाख 36 हजार 402 लोगों को राहत प्रदान की गई। अगर सरकार के आकड़े भी सही मान लिए जाएं तो बाढ़ की स्थिति राहत बहुत गम्भीर है और प्रकृति की तरफ से जो नुकसान हुआ, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई पग समय पर नहीं उठाए गए जिनकी वजह से लोगों को राहत प्रदान की गई हो। आज ऐसी स्थिति हो गई जैसे प्रशासन नाम की कोई चीज काम ही नहीं कर रही हो। इस भीषण बाढ़ से लोग खुद प्रकृति के रहमोकरम पर हे। जो लोग बाढ़ से बचे हुए थे और जो धनी लोग थे, उन्होंने आगे बढ़ कर दिल खोल कर बाढ़ से धिरे लोगों की मदद की। प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाये जाने जाहिए थे नहीं उठाये गए। जो लोग अपने स्तर पर लोगों को बाढ़ के दिनों में राहत पहुंचा रहे थे उसी राहत को सरकारी आकड़ों में दिखाकर बिल वसूल कर रहे हैं। सरकारी आकड़ों के मुताबिक 6 हैलीकापटर थे जिनमें 3 हैलीकापटर खाद्य सामग्री के लिए इस्तेमाल होते थे। सरकारी आकड़ों के मुताबिक 9 लाख खाने के पैकेट गिराए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात का स्वयं पता करवा लें कि 3 हैलीकापटर इतनी उड़ान भर कर क्या इतने पैकेट गिराने में समर्थ है यानि उनके द्वारा इतने पैकेट गिराना संभव हैं? अब सरकारी आकड़ों के मुताबिक जो दिखाया गया है उसमें स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता

को भी शामिल करके दिखाया जा रहा है इन पैकेटों से जाहिर है कि प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर सहायता दी है। इस बात ने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि सरकार जो मदद पीड़ितों को दे रही है वह सरकार नहीं दे सकती. बल्कि वह स्वयं सेवी संस्थाओं से वसूल की गई है। जिन लोगों ने खाद्य सामग्री पोलिथीन पैकेट्स में बन्द करके पीड़ित लोगों को पहुंचाने के लिए दी थी, मजबूरन उन्होंने पैकेट्स में अपने-2 नाम की पर्चियां डालना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा पहुंचाई गई मदद में ऐसे पैकेट्स पकड़े गए जिनमें पर्चियां थीं। अध्यक्ष महोदय, कैसे इस बात को माना जाये कि प्रदेश की सरकार ने पीड़ित लोगों की मदद की है। सरकार का दावा है कि सरकार ने दिल खोलकर मदद की है,। सरकारी आकड़ों के मुताबिक 28 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से घिर गए थे और 1,36,402 लोगों को मदद दी गई। इससे जाहिर होता है कि सरकार 5परसैंट लोगों को भी राहत प्रदान करने में असमर्थ रही है। अध्यक्ष महोदय, यह जो विनाश लीला हुई है, मैं तो यह मान कर चल सकता हूं कि वर्षा ज्यादा होने की वजह से हुई होगी लेकिन ज्यादा दोषी सरकार है, इस न-अहल सरकार की बजर से गफलत रही है, जिसका नतीजा यह बाढ़ थी। सरकार की सारी जगह ड्रेनें खुदी हुई है लेकिन सरकार ने इनकी खुदाई के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। ड्रेनो में किसी प्रकार की डी-बैडिंग नहीं की गई, झाड़ू -झंखाड कीकर, पटेरा आदि ड्रेनों में ज्यों के त्यों खड़े रहे और उनकी सफाई नहीं की गई। इन ड्रेनों की डी-सिल्टिंग

नहीं की गई जिसके कारण वे मिट्टी से भरी हुई थी और बाढ़ का पानी लेने में असमर्थ थीं। डिविजन ड्रेन नं० 8 जिसकी कैपेसिटी 8 क्यूसिक है, उसमें जब बाढ़ का पानी आया तो वह पाली नहीं खींच पाई क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4 क्यूसिक रह गई थी। पानी की खिंचाई न होने के कारण जितनी भी ड्रेन थी, सारी की सारी टूट गई। इस ड्रेन की न डी-बैंडिंग हुई और न ही डी-सिल्टिंग हुई सरकार ने नहरों और ड्रेनज के किनारों को मजबूत करने का कोई काम नहीं किया, फर्जी बिल बनाने के उद्देश्य से भले ही ट्रैक्टरों के पीछे हैरो बांध कर, किनारों को फिराकर, उनको और पोला कर दिया गया। किनारे और नीचे हो गए जिसकी वजह से भीषण तबाही हुई।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल की गवर्नमेंट ने अपने वक्त में रिंग बांध बनाए थे। 1978 में भीषण बाढ़ से उभर कर वक्त की सरकार ने सबक सीखा और रिंग बांध बनाकर गांवों को बाढ़ से बचाने की पुरजोर कोशिश की। उस वक्त की चौधरी देवी लाल सरकार ने गांवों के चारों ओर रिंग बांध बनाकर उनको बाढ़ से बचाने का प्रबन्ध किया था लेकिन वर्तमान सरकार की तरफ से इन बांधों पर एक तसला मिट्टी का भी नहीं डाला गया, परिणामस्वरूप जगह जगह से बांध टूट गए जिसकी वजह से यह भीषण तबाही हुई है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में मसानी बैराज का जिक्र आया था। मौजूदा मुख्य मंत्री ने कहा था कि 40 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए। पूर्व मुख्य मंत्री भी संयोग से हाउस में बैठे हुए हैं,

उन्होंने भी कहा था कि 40 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया है और उस बैराज से कोई लाभ नहीं हुआ है। उन्हें याद होगा कि साहबी नदी से किस प्रकार तबाही हुई थी। अध्यक्ष महोदय। इसी से इस बात का पता चलता है कि मसानी बैराज की वजह से रिवाड़ी का इलाका बार से बच गया, रिवाड़ी जिले में बाढ़ नहीं आई। रिवाड़ी के विधायक तथा वहां के मन्त्री भी यहां पर बैठे हुए हैं, वे खुद बताएंगे कि कितना भारी नुकसान वहां पर हुआ होता। वहां पर दरवाजे रखे गए थे। अगर वे दरवाजे लगा दिए गए होते तो भारी तबाही से बचा जा सकता था क्योंकि यह पानी आगे न जाता और जो पानी इकट्ठा होता उससे जमीन री-चार्ज हो जाती। सरकार की सोच हरियाणा की जनता के हितों की ओर नहीं है, उनकी सोच तो इस तरफ है कि जितनी ज्यादा बारिश होगी, बाढ़ आएगी और बाटु के नाम पर जितना पैसा खाया जा सकता है खाया जाए लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मन्जूर था। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से इन्होंने तबाही और बर्बादी करने का काम किया है, इसके लिए यह सरकार दोषी है। सरकार को मुजरिमों को कटघरे में खड़े करके इस बात का स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि इतनी भारी तबाही कैसे हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बजट स्पीच में भी कहा था कि गुप्ता जी आपने बाढ़ से बचने के लिए एक नया पैसा भी बजट में नहीं रखा है। अगर कल को बाढ़ की स्थिति आएगी तो आप लोगों को कैसे उभार पाएंगे। जितना पैसा इन्होंने बाढ़ के लिए

रखा, वह तो तनख्वाह देने में ही खर्च हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार के पुराने आकड़े आपको बताता हूँ। आप स्वयं ही उससे अदाजा लगा लें कि इन्होंने कितनी कोताही करने की कोशिश की है। इन्होंने 1974-75 में बाढ़ के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपया रखा था, 1975-76 में 1 करोड़ 35 लाख रुपये और 1976-77 में 3 करोड़ 48 लाख रुपये रखे थे। अध्यक्ष महोदय, 1977-78 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस वक्त हमने 10 करोड़ 38 लाख रुपये बाढ़ के लिए खर्च किए थे, 1978-79 में 24 करोड़ 79 लाख रुपये तथा 1979-80 में 30 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च किए थे। उन 3 सालों में हमने लगभग 50 करोड़ से भी अधिक रुपये खर्च किए हैं। इनके सारे शासन काल में अब तक इतनी अधिक राशि खर्च नहीं की गई है। यह इस लिए है कि इन्हें लोगों के हितों से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। अब भी बाढ़ से घिरे लोगों की मदद की बजाए उनको प्रतिबिम्ब सिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आप व्यक्तिगत तौर पर भी सुनेंगे और अखबारों में भी खबरे छपी हैं। आज यहां पर मिनिस्टर आफ स्टेट श्री बतरा बैठे हुए हैं। इनके बारे में अखबार में छपा है कि इन्होंने अपनी कोठी बचाने के लिए उस ड्रेन नं० 8 को तोड़ दिया और उसको तोड़ने के लिए जिले के डिप्टी कमीशनर और डी०आई०जी० को स्वयं मौके पर ले कर गए थे। (विधन) अध्यक्ष महोदय, जब इनको समय दिया जाएगा तब ये बोल लें। इस तरह से बीच में इन्ट्रूट न करे। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि यह बात ठीक है। यह बात तो

अखबार में छपी है और इस की चर्चा आम है। मन्त्री जी को जब अवसर मिले तो वे स्वयं इसका स्पष्टीकरण दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं रोहतक शहर में गया था। आम आदमी की जुबान पर यह था कि हमें हमारे प्रतिनिधि इस बतरे ने मरवा दिया। अगर उसने यह ड्रेन न तुडवायी होती तो रोहतक शहर बच जाता। आज रोहतक शहर में कई जगहो पर पांच फुट से अधिक पानी खड़ा हुआ है। मुख्य मन्त्री जी आज से 15 दिन पइले भिवानी और रोहतक में गए थे और यह एलान करके आए थे कि 3 दिन में पानी निकाल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय या तो मुख्य मन्त्री की नियत ठीक नहीं है या ये इतने विफल हो चुके हैं कि इनके आर्डर को सरकारी मशीनरी मानने को तैयार नहीं है। आज दादरी शहर सड़ रहा है। आज भी दादरी शहर के पूरे हिस्से में 5-5 और 6-6 फुट पानी है। अध्यक्ष महोदय, गांवों की बात को छोड़ दें, आप हांसी, नरवाना और रोहतक की बात लीजिए। बहा पर कितना नुकसान हुआ होगा, इसका पता अभी नहीं लग सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं कल हरियाणा प्रदेश के रोहतक शहर की एक कपड़े की थोक मार्किट में गया था जिसकी एक-एक दुकान में कम से कम 1-1 करोड़ रुपये का माल पड़ा हुआ था। वहां के दुकानदार रो रहे थे और ऐसे हालात थे कि वे अपना गला-सड़ा माल स्वयं निकाल कर, अपने किराए से उसको बाहर फिंकवाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा, मैं एक अनाज मंडी में गया था। वहां पर व्यापारी कह रहे थे कि हमारा अनाज सड़ गया है। अध्यक्ष महोदय, उस अनाज में से जब व्यापारी कुछ अनाज सुखाकर किसी और

काम में लाने की कोशिश कर रह हैं तो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें कहते हैं कि आप स्प सारे सामान को बाहर फिकवाने का प्रबन्ध करे। अब भी यह सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि पानी निकलवाने वाली जगह पर सफाई का प्रबन्ध करे। वहां दवाईयां छिड़कवाएं ताकि बीमारियां न फैलें। आज गांवों के यह हालात हैं कि वहां पर 7-7 फुट पानी खड़ा है और लोगों के आने जाने के सारे साधन समाप्त हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज भी पांच गांवों में सात-सात फुट पानी खड़ा है। ऐसी हालत में जब यहां पर बिजली के खम्भे गिर गए तो लोगों ने जाकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि आप हमारे बिजली के खम्भे खड़े कर दीजिए और हमें बिजली दीजिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने साफ इन्कार कर दिया। लोगों ने स्वयं ही बिजली के खम्भे खड़े किए और फिर उनके पास जाकर कहा कि हमने अपनी जान हथेली पर रखकर वे खम्भे खड़े किए हैं, अब तो आप उनमें बिजली पहुंचा दीजिए। जब वे लोग पूर्ण रूप से अन्धेरे में थे, उनके पास शायद आटा तोंची जगह में होने की वजह से बच गया होगा, लेकिन उसको पकाने के लिए न तो उनके पास उपले ही थे, न सूखी लकड़ी थी और न ही बिजली मिलती थी। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुखदायी बात और क्या होगी कि दस-दस रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनको मिट्टी का तेल दिया गया है। किसी भी प्रकार की राहत उनको नहीं दी गयी। आज प्रदेश में

महामारी फैलने के आसार हैं क्योंकि पानी में मरे हुए पशु हैं, जंगली जानवर हैं और सारा गन्दा कूड़ा-करकट पानी में फैंका जा रहा है। बहुत सारी गन्दगी उस पानी में इक्ट्टी होकर आयी है। गांव में वाटर वर्क्स की डिग्गियों में गंदा पानी भर गया है। अध्यक्ष महोदय, ऐहें पानी को पीने के बाद क्या लोग बीमार नहीं होंगे? वहां पर अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनको छिपाने का काम किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो यह बता दें कि अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई प्रेस नोट इस बारे में क्यों नहीं जारी किया गया है कि फलां-फलां जगहों पर लोग हैजे में मर गए हैं, फलां जगह पर आन्त्र शोध फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहीं पर भी डी. डी टी का ले नहीं करवाया है, कहीं पर लाल दवाई कूओं या वाटर टेक्स की डिग्गियों में नहीं डलवायी है। सर, आदमी तो फिर भी पानी उबालकर पी लेगा लेकिन पशु बेचारे तो कहीं पानी पीएंगे। स्वयं सेवी संस्थाओं की तरफ से या समाजवादी जनता पार्टी की तरफ से वो जगह-जगह पर चिकित्सा कैम्पस लगवाए गये हैं, उनसे दवाईयां लेकर लोग तो अपना बचाव कर लेंगे लेकिन पशुओं की क्या हालत होगी, उनको तो गंदा पानी ही पीना पड़ेगा। जब पशु यह गंदा पानी पाएंगे तो वे मरेंगे। अध्यक्ष महोदय, पशुओं को कोई भी मेडिकल ऐड सरकार की तरफ से नहीं दी गयी है। मुख्य मन्त्री जी रोहतक गए थे और रोहतक में जो वैटेनरी के डिप्टी डायरेक्टर थे, वह मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए मुख्य मन्त्री जी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। मुख्य कली

जी तो केवल भिवानी और रोहतक में ही गए हैं। जब मुख्य मन्त्री का कहीं पर दौरा होता है तो बहुत से अधिकारी यही सोचते हैं कि मौके पर जरूर होना चाहिए लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं होते तो इसी से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों ने लोगों को कितनी राहत पहुंचाई होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रशासन तो पूर्ण रूप से फेल हो गया था। सर, लोग अगर मुसीबत में हों और उनको और अधिक मुसीबत में डालने का प्रयास किया जाग तो फिर क्या कहा जा सकता है? मैं एक बार पुनः यह कहना चाहूंगा कि अगर इस हाउस के सम्मानित सदस्य श्री सुभाष बतरा की तरफ से रोहतक में वह रेल की पटरी न कांटी जाती तो शायद रोहतक की यह दयनीय हालत न होती। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजस्व मन्त्री यश पर बैठे हैं, इन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए नेशनल हाईवे को काट दिया जिसकी वजह से यहां पर 15 गांव पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। इस वजह से कई गांवों में पानी फैल गया। अध्यक्ष महोदय, क्या जनता ने हमें इसीलिए चुनकर भेजा है कि हम अपने तक और अपने रिश्तेदारों तक ही सीमित रहें? क्या आज हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है कि हरियाणा प्रदेश को अपनी-अपनी तरह से बचाने का प्रयास करे? अध्यक्ष महोदय, प्रकृति का प्रकोप तो रहा ही है लेकिन मुसीबत के दिनों में दलगत राजनीति से चपर उठकर क्या हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम ऐसे समय में लोगों को और ज्यादा मुसीबत में डाल दें तो क्या हम मान्यता के साथ अन्याय नहीं करते हैं? क्या जनता आश्रय यह उम्मीद कर

सकती है कि इस सरकार की तरफ से हमें कोई भी राहत मिल पाएगी? अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जो मन्त्री हैं, के गांव में 24 तारीख को सात बजे आयशर ट्रैक्टर पर बैठकर गया था। उस समय उस ट्रैक्टर के बोनट तक पानी चल रहा था। यह हालत मैली के गांव की है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक दफा इटली गया था यहां गलियों में समुद्र का स्वच्छ पानी आता है, दुनिया भर के टूरिस्ट उसे देखने के लिए जाते हैं बोटिंग करते हैं, वही नजारा अब की बार हरियाणा प्रदेश के हर गांव में देखने को मिला। अध्यक्ष महोदय, आपके पड़ौसी हल्के में भी ऐसे हालात रहे, आप गए होंगे और देखा होगा। अब भी पाई क्षेत्र के बहुत से गांवों में पानी खड़ा है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा के गांव की गलियों में आज भी 5-6 फुट पानी है। फर्क इतना है कि वीनस का पानी स्वच्छ और साफ था और खडवाली गाय का पानी सड़ रहा है और उससे बीमारिया फैल रही है। गऊशाला में 60 गऊएं मर गई हैं। अध्यक्ष महोदय क्या हम सरकारी आकड़ों को मान सकते हैं, जबकि शहरों में रोज देखते हैं कि गऊएं सड़कों पर बैठी रहती हैं, कितने पशु मरे होंगे। रोहतक शहर में कितनी कारें लोगों की पानी में रह गईं कितने मकान गिरे हैं मगर सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। लेशमात्र भी कोई मदद नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों में क्या हम उम्मीद रखें कि हरियाणा प्रदेश में जिस किसान का घर बर्बाद हो गया, सामान बर्बाद हो गया वे सम्भल सकेंगे? अभी तो अध्यक्ष महोदय, गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा मच्छर काट लेंगे, लेकिन दो महीने के

बाद सर्दी आ जाएगी तो गरीब लोगो के मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे कैसे जी पाएंगे, कैसे सर्दी से अपने बच्चों को बचा पाएंगे? इन्होंने कैसे प्राण हथेली पर रखकर बच्चो को बचाने का प्रयास किया? अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी हाउस को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे सबके समान हैं। एक तरफ हरियाणा प्रदेश की यह हालत थी, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे, मां-बाप अपने बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे थे और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री पंचकूला के रैंड बिशप में, 13 सितम्बर को, अपने साहबजादे का जन्म दिवस मना रहे थे। उस दिन रैंड बिशप में दो हजार लोगों को दो बार खाना दिया गया, अच्छी शराब दी गई। मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है लेकिन यह सरकारी रिकार्ड में दर्ज है। अगर रैंड बिशप में 13 तारीख की रात के डिनर का बिल पे नहीं हुआ तो एक ज्यादाती और हुई है। सरकार को भी बहुत ज्यादा चूना लगाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के हालात में भी अगर लोग इस तरह की मौज मस्ती ले रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश की क्या हालत होगी? इस हालत में हम कग उम्मीद कर सकते हैं? जिस किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई हो, सामान पानी में बह गया हो उसको सहारा कौन देगा? मुझे भिवानी, दादरी, बरवाला हांसी और रोहतक में जानै का अवसर मिला है। जो लोग 1947 में इन्ही लोगों की गलतियों की वजह से इस देश में आए थे, उन्होंने अपने पांवों पर खड़े होकर अपने आप को ऐड-मस्ट किया था, उस वक्त अपने आप को बचाने का काम किया था, ऐस्टैब्लिश किया था और अब वे 1947 को

भूल गए थे। उस वक्त तो उनको यह तकलीफ थी कि गैरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था लेकिन हब की बार तो अपनों ने कर दिया। उनकी क्या हालत होगी मो दूसरी मर्तबा उजड़े हैं। सरकार कहती है कि 25 हजार रुपया उनको देंगे जिनका करोड़ों रुपये का सामान बर्बाद हो गया। अध्यक्ष महोदय, वे 25 हजार रुपये में कैसे खड़े हो पाएंगे? 1993 में बाढ़ साई थी तो हमने सरकार से कहा था कि उसे पहले से ही इसकी पेशबन्दी करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा न हो।

अध्यक्ष महोदय, जो सड़के टूट गई थी उनकी मुरम्मत के साथ-साथ सड़क के नीचे पुलियां बनानी चाहिये थीं, ड्रेनज की सफाई करनी चाहिये थी। हमने इनको कहा था कि नहरों के किनारे मजबूत करने चाहियें लेकिन सरकार ने इस तरफ देखा ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी कारों में बैठ कर रोज सड़कों पर चलते हैं और सड़कों पर इनको अपने ही लगाए हुए बोर्ड पढ़ने को मिलते हैं कि आगे गति-रोध है, संभल कर चलो। उसको पार करने के बाद अगर फिर भी कोई ठोकर खाता है तो आगे लिखा हो ना है कि हमने आपको पहले ही सूचित किया था।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा 1993 की इस भीषण बाढ़ लीला से सरकार को अवगत कराया था और सरकार को सुझाव भी दिये थे कि आपको ये ये काम करैना चाहियें वरना बाढ़ की स्थिति किसी समय अगर इस हालत को छू गई तो इस से पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मेरे उस सुझाव से इस

सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा और न ही कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, यह तो समझ कर बैठे थे कि अब तो तुम्हारे दिन नजदीक आए हैं। उस वक्त तो तीन साल की उम्मीद थी लेकिन अब तो बेचारे तीन महीने की उम्मीद में बैठे हैं। इसलिए इन्होंने यह समझा कि आखिरी समय में जितना लूट कर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज हालत क्या है। सरकार लोगों की मदद का ढोंग रचाती है। सरकार कहती है कि हमने लोगों की मदद बहुत की है। ये कहते हैं कि 32 ट्रक सब्जी के रोहतक में भेजे हैं अगर रनकी इस बात को सही मान लिया जाए तो आप ही बताएं कि 32 ट्रक सब्जी से नितने दिनों तक काम चलेगा? रोहतक में तो पिछली 26 तारीख को यह बाढ़ आ गई थी और आज 26 तारीख ही है। एक महीने से वहां के लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जो 32 ट्रक इन्होंने सब्जी के भेजे हैं, वह किस-किस को दे पाए होंगे। 30 ट्रक ये कहते हैं कि भिवानी में भेजे हैं। सरकारी आकड़ों के अनुसार रोहतक में 15000 लोग कैम्प में हैं, जहां सरकार रिलीफ दे रही है 32 ट्रकों की वास्तव में भिवानी के अन्दर 50,000 के करीब लोग कैम्प में हैं और केवल 30 ट्रक ही सब्जी के भेजे गये हैं। जीन्द में भी लगभग 50 हजार लोग कम्पों में हैं लेकिन वहां पर एक भी ट्रक नहीं भेजा गया। क्या सोच कर सरकार ने इस रिलीफ का निर्णय लिया है, हमारी समझ से वाह है। सरकार तो सब्जियों के ट्रक भेज रही है और दूसरी तरफ सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का क्या हाल है। वहां के (रोहतक के) डी० सी० ने इनको लिखकर भेजा है कि हमें सब्जी

नहीं चाहिये, केले और सेब चाहिए जो शराब के नाम पर पीटर स्काट मांगेंगे। वे तो सेब वगैरह लेना चाहते हैं, सब्जी नहीं लेंगे। आम आदमी तो 18 रुपये किलो आलू लेकर खाये और वे अधिकारी पीटर स्काट व सेब केले खाएं यह कितनी बुरी बात है। यह तो हाल है, इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का। सेब और केले खाकर मौज मस्ती करने वाले, लूटने वाले सरकारी अधिकारी इस प्रदेश को पूर्ण रूप से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जी मुंह में आए. बोलने चले जा रहे हैं, वह इनके लिए मुनासिब बात नहीं है। अफसरों के बारे में कह दिया कि पीटर स्काट, सेब-केले उनको चाहिये, व भी उनके बारे में कह दिया कि मौज मस्ती करने के जिये उनको यह-यह चाहिये, यह मुनासिब नहीं एं। जो रात दिन लगे रहे, 24 घे जिन अधिकारियों ने अपनी परवाह न करके बाढ़ से बचाव का काम किया हो, उनके बारे में ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल को यह मुनासिब नहीं है, ये शब्द हाउस की कार्यवाही में से निकाल दिए जाने चा हिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनसे कहिये कि जरा मर्यादा में रह कर ही बात कहे। कभी किसी के बारे में कुछ कह देना, यह कह देना कि लूट का माल खाकर के चले जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। आप बताएं कि बाढ़ से इस बात का क्या ताल्लुक है? यहां पर बाढ़ से हुए प्रकोप पर

चर्चा हो रही है और इनको पौना घण्टा बोलते हुए हो गया है अगर इसी तरह से सारे मैम्बर बोलते रहे तो डिस्कशन 10 दिनों तक भी खत्म नहीं होगी। (शोर) मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय, इतना अनुरोध है कि आप इनको मर्यादा में रहकर ही बोलने को कहे, नहीं तो हमें बीच में ही इनको टोकना पड़ेगा। पहले हमने इनको बीच में नहीं टोका। ये बोलते जाएं लेकिन मर्यादा में रह कर ही बोलें तो उचित रहेगा। सारे अफसरों को एक ही लाठी से हांकना, यह इनके लिए मुनासिब बात नहीं है। हरियाणा के सारे अधिकारियों पर हमें गर्व है, भरसा है कि इन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ राज्य के हित में काम किया है और कर रहे हैं। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मर्यादा में रहकर बोलने वाले की अगर मैं चर्चा करूं तो हाऊस इनके बारे में सुन नहीं सकेगा। (शोर) क्या अधिकार है इनको बीच में उठ कर बोलने का? क्या ये आगकी इजाजत से बोल रहे हैं? (शोर) मैं इस हाऊस का एक सम्मानित सदस्य हूं और ये केवल आपके हारा ही मुझ से बात कर सकते हैं, बीच में बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं है। (शोर)

चौधरी भजन लाल: न आपके हाथ न पैर, शानदार शकल सूरत, कम से कम बात तो हाऊस में सही कहनी चाहिए। कुछ मर्यादा में रह कर के बात करो तो ठीक रहे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: मेरे पास क्या है, क्या नहीं है लेकिन उस जगह पर अगली दफ नहीं आने दूंगा। (शोर)

चौधरी भजन लाल: यह आपके बस की बात नहीं, जनता का राज है (शोर) जिसे जनता चाहेगी वही आयेगा।

16.00 बजे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: यहां पर मेरा बाप रहा और मैं भी रहा लेकिन अगली दफा मैं ही फिर आऊंगा। उस जगह पर अगली दफा तेरे को नहीं जाने दूंगा। (शोर) अध्यक्ष महोदय,(शोर) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री को इस बात का ज्ञान नहीं और ये मुझे मर्यादा की बात कहते हैं? जो मैंने डिप्टी कमिशनर वाली बात कही, इनको शायद ज्ञान नहीं होगा कि वे उसके लिखित रूप में आदेश हैं। लिखित रूप में जो आदेश होते हैं, वह सरकार के रिकार्ड में होते हैं। इनको इन बातों का क्या पता है ? (शोर) एक मुख्य मन्त्री के कोई तौर तरीके हुआ करते हैं। (शोर) मैं आपके द्वारा सदन में कहना चाहता हूँ कि जिस किस्से को लेकर यह बात कही गई थी, उसी के तहत ट्रिज्म के एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया। (शोर)

चौधरी भजन लाल: (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: यह हाउस किसी के बाप की मलकीयत नहीं है। जो बात हम कहेंगे वह

सुननी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, यह बीच में क्यों टोंकने हं? (शोर)

श्री अध्यक्ष: वे यह कह सकते हैं कि आप ठीक ढंग से जो टोपिक है, उसी पर चर्चा करे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न का उत्तर आप से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने कोई अनरगल बात कहा है? मैं आप से ही पूछना चाहूँगा और किसी की बात को छोड़िये। क्या मैंने कोई ऐसी बात कही है? (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिए। ऐसा है कि आपने जो जनरलाइजेशन किया है, उस पर तो ये कह सकते हैं। ये लीडर आफ दी हाऊस हैं और ये मुझे भी कह सकते हैं कि आप इनको सीमित ही बोलने दें। उसी टोपिक पर बोलने दें जो चला हुआ है। इसलिए आप ठीक ढंग से सीमित ही बोलें और फलडज के बारे में बोलें। यह ठीक है कि बोलते हुए थोड़ी बहुत इधर-उधर की बात कही जाती है लेकिन आप जनरलाइज न करे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार द्वारा दिए हुए आकड़ों से ही बताया है। मैंने वह बात कही है जो इनके रिकार्ड में है।? (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई आकड़े किसी को नहीं दिए हैं, ये पता नहीं कहां से ले आए? (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी बदकिस्मती है कि हरियाणा में आज यह सरकार है जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं (शोर)

श्री अध्यक्ष: आपको बोलते हुए 35 मिनट हो गए हैं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात तो पहले ही चर्चा में आ गई थी कि इस पर खुल कर डिस्कशन होगी। यह मेरा या किसी एक दल विशेष का व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह हरियाणा के अस्तित्व का सवाल है, हरियाणा प्रदेश बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में स्थिति यह हो गई है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई उम्मीद इस सरकार से नहीं है कि यह सरकार उनको कोई राहत दे पाएगी। जिस दुकानदार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, उसके लिए सरकार घोषणा करती है कि 25 हजार रुपए देगी। जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, उसके लिए कहती है कि हम उसे एक हजार रुपया प्रति हैक्टेयर के हिसाब से और चार सौ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। जिनका पक्का मकान गिर गया, उसको दस हजार रुपए देने'। मापको पता है कि आज सीमेंट का थैला 150/- रुपए का है, लोहे का भाव 190/- रुपए, है ईटों का भाव 1200/- रुपए प्रति हजार है। आज कारीगर की मजदूरी 150/- रुपए है और मजदूर की मजदूरी 70- 80 रुपए है, तो उनका दस हजार रुपए से क्या बनेगा? अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने तो केवल घोषणा ही करनी

है, उसकी इम्पलीमेंटेशन तो दूसरी आने वाली सरकार करेगी इसलिए यह सरकार घोषणा में कंजूसी न करे। घोषणा में कंजूसी क्यों करते हैं? कम से कम आज जो लोग मुसीबत में हैं, उन्हें राहत मिले, उन्हें इस बात की तसल्ली हो कि उन्हें कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन उन्हें कुछ देने वाले कोई और ही होंगे अगर ऐसा है फिर आप उनको कुछ देने के बारे में घोषणा करने में कंजूसी क्यों करते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि इस सरकार ने 1993 के बाद पीड़ितों को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की थी। ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था उसका भी किसानों को एक नए पैसे का मुआवजा नहीं दिया। पिछली बाढ़ के कारण जो सड़के टूटी थीं, उनको मरम्मत करते वक्त यह नहीं देखा कि जो सड़के टूटी है, उनके नीचे से पुल बनाए जाएं ताकि नैचुरल पानी उनके नीचे से गुजर जाए। उसमें सरकार ने चाहे रुकावट डाली हो लेकिन अब की बार पानी सांप की तरह चला था। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे दरिया सूख गए हैं। घग्गर नदी में पानी नहीं है। टांगरी नदी में पानी नहीं है और मारकंडा नदी में पानी नहीं है लेकिन हरियाणा प्रदेश की सड़कों पर आज भी पानी कई जगहों पर डेढ़ डेढ़ फुट खड़ा है और वह बढ़ता जा रहा है आज भी कहते हैं कि बाढ़ के पानी से नरवाना को और खतरा होने जा रहा है। यह भी कहते हैं कि हांसी को भी खतरा होने जा रहा है। आज भी बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। किसी को यह तसल्ली नहीं है कि वह पानी कहीं निकल जाएगा। आज ये हालात हो गए हैं कि जहां कहीं किसी के हाथ

पड़े, कहीं ड्रेन काट दी, कहीं रेल की पटरी तोड़ दी और कहीं सड़क तोड़ दी। रोहतक के डी० सी० और डी० आई० जी० ने सुभाष बत्तरा के साथ जा कर ड्रेन नम्बर 8 को काट दिया। इन्होंने यह सोचा कि किसी तरह से रोहतक शहर को बचा लिया जाए। इन्होंने चिरावली गांव के पास ड्रेन नम्बर 8 में दो कट कर दिए। स्वयं कृष्ण मूर्ति हड्डा उन कटुस पर गए थे हम इनके गांव और रोहतक के बीच में दो कट देख कर आए हैं लेकिन फिर भी रोहतक शहर नहीं बच पाया। इसी तरह से ड्रेन नम्बर 6 को तुड़वा दिया जिसके कारण सांपला डूब गया। इन्होंने एस० डी० ओ० नरवाना से सिरसा मेजर-नहर को तुड़वा दिया और वह सारा इलाका डूबवा दिया। आज हालत यह है कि वह मामला सरकार के बेकाबू हो गया है। कोई भी सरकारी अधिकारी, किसी भी एम. एल. ए. के साथ जा करके नहर तोड़ दे, सड़क तोड़ दे, रेल की पटरी तोड़ दे, इससे ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के मकान गिर गए हैं और उनकी सावनी को फसलें बर्बाद हो गई हैं। रबी की फसलें बोई नहीं जाएंगी क्योंकि अभी तक इस सरकार का बाढ़ के पानी को पम्प-आउट करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। दिनांक 5. 9. 95 को सरकार की ओर से आदेश हुआ था कि पम्प खरीदे जाए लेकिन 16 तारीख तक पम्प नहीं खरीदे गए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के लोग बाढ़ का पानी अपने ट्रैक्टरों से निकाल रहे हैं। लोग अपने प्रयासों से बाढ़ का पानी निकाल रहे हैं इस सरकार की तरफ से लोगों को कोई इमदाद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह

सरकार आश्वासन दे कि जिन सरकारी अधिकारियों ने इस मामले में बेकायदगी की है जिनके कारण हरियाणा प्रदेश के लोगों का नुकसान हुआ है, जिन सरकारी अधिकारियों ने नहरे तुडवाई हैं, सड़कें तुडवाई हैं, रेल की पटरियां तुडवाई हैं, क्या सरकार उन अधिकारियों को बर्खास्त करेगा और क्या सरकार उन पर मुकदमा चलाएंगी? सरकार यह आश्वासन दे कि जो सावनी की फसल बर्बाद हो गई है, उसका मुआवजा किसानों को देगी। रबी की फसलों की बुआई के लिए भी कुछ मुआवजा दे। रबी की फसलें भी नहीं बोई जा रही हैं क्योंकि बाढ़ का पानी अभी भी खड़ा है सरकार कहने को तो कहती है कि किसानों को 400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे लेकिन जब सरकार ने पहले जो वायदे किए थे, उनको ही पूरा नहीं किया है तो नये वायदे कैसे पूरे करेगी? यह सरकार लोगों की इमदाद करने की बात कहती है और कहती है कि मृतकों के लिए 50- 50 हजार रुपए देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के कम्पनसेशन देने के दो पैमाने हैं। जब ऐसा हो तो किस तरह मान लिया जाए कि यह सरकार मरने वालों के परिवारों को दो-दो लाख रुपए दे ही देगी जिनको इन्होंने गोलियों से मरवा दिया उनको तो ये दो-दो लाख रुपये देते हैं। नारनौंद में मरने वालों के परिवारों को दो- दो लाख रुपये दिए। नासिरा में मरने वालों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये दिए। कादमा कांड में मरने वालों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये दिए और मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी। इनकी गलती की वजह से, इनकी नासमझी की वजह से जो

लोग मर गए, उनके परिवारों को 50- 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो लोग बाढ़ के कारण मर गए हैं, उनको 50-50 हजार रुपये किस कानून के तहत दे रहे हैं और जो लोग गोलियों से मरवाए गए नैं के परिवारों को किस कानून के तहत दो-दो लाख रुपये दिए गए? अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों का पशुधन मर जाएगा तो उनका गुजारा कैसे होगा? पशुओं के मरने पर किसानों को कितना मुआवजा देने का निर्णय किया है? हरियाणा प्रदेश में लोगों के कितने पशु मरे हैं और कितने पशुओं का यह सरकार मुआवजा देने जा रही है इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अध्यक्ष महोदय, आज भैंस की कीमत 20 हजार रुपए तक है। आज एक गाय की कीमत 10 और 15 हजार रुपए तक है। बैल 20 हजार रुपए में भी नहीं आता। इस बाढ़ के कारण कितने पशु मरे हैं, सरकार के आकड़ों के अनुसार, किसानों को किस हिसाब से मुआवजा देने जा रही है? पक्के मकानों के गिरने के बारे में सरकार 10 हजार रुपए प्रति मकान के हिसाब से देने जा रही है। क्या 10 हजार रुपए में पक्का मकान बन जाएगा? कच्चा मकान गिरने के पांच हजार रुपए दे रही है, क्या पांच हजार रुपए में कच्चा मकान बन जाएगा? कच्चे मकान की मुरम्मत के लिए 2500 रुपए दे रही है, क्या 2500 रुपए में कच्चे मकान की मुरम्मत हो जाएगी? लोगों के ट्यूबवैल बाढ़ के पानी में बह गए, उनके कुए पानी से बर्बाद हो गए। यह सरकार, जो ट्यूबवैल्ज बाढ़ से बर्बाद हुए हैं, उनको 42500 रुपये देने जा रही है, जबकि इनको पता है कि आज के दिन एक ट्यूबवैल

तुक—एक लाख रुपये से कम का नहीं लग पाता। स्पीकर साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को मजबूर करें कि सरकार दिल खोल कर किसानों की और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों की मदद करे। सरकार खुल कर बताए कि वह किस प्रकार की कितना—कितना मदद देने जा रही है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि 15 अक्तूबर तक सारा पानी निकाल दिया जायेगा जबकि ड्रेनेज के अधिकारियों की रिपोर्ट है कि दो महीनों में भी पानी निकालना संभव नहीं है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि यदि दो महीने तक पानी नहीं निकला तो लोगों की रबी की फसल की बुआई कैसे हो सकेगी? अगर बुआई नहीं हो सकेगी तो फिर लोगों का गुजर कैसे होगा?

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से हुए नुकसान से लोगों को बचाने के लिए मैं एक सुझाव देता हूँ। आल पार्टीज के मैम्बरो की एक कमेटी बनाए जो गांव—गांव में जा कर देखे और लोगों से पूछे कि पानी कैसे और किस तरीके से निकाला जा सकता है। यदि इस पानी को तुरंत नहीं निकाला गया तो एक महामारी फैलने का अंदेशा है जिसे सरकार को रोकना भी संभव नहीं होगा। सरकार का ड्रेनेज विभाग से कोई लगाव नहीं है। नैचुरल कलेमेटीज के नाम से चाहे थोड़ा बहुत पैसा नहर विभाग को दे दिया गया हो, लेकिन बाकी उसको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव प्यायंट आफ व्यू से कोई लगाव नहर विभाग के साथ नहीं है। उस बारे में

मेरा सुझाव है कि नहर विभाग को, इस काम के लिए, राजस्व विभाग के साथ जोड़ दिया जाय ताकि प्रशासनिक अधिकारी आपस में बैठकर इस समस्या का निदान करने में ज्यादा सहायक हो सकेंगे। दूसरे जो ड्रेनेज हैं उनकी जल्दी से जल्दी सफाई हो और पंप लगा कर या नई ड्रेनें खोद कर पानी को निकाला जाये। यदि सरकार ऐसा करती है तो लोगों को जल्दी राहत मिल सकेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार लोगों की मदद तो क्या करेगी, खाली कट्टे भी नहीं दे पायी। लोगो ने खुद खाली कट्टे इकट्टे करके अपने भाईयों की, जो बार से धिरे हुए हैं मदद की। आज भो बहुत से लोग जो बाढ से प्रभावित हैं, नहरों के किनारों पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। सरकार की वजह से और सरकार से जुड़े हुहु लोगो के कारण लोगो की ऐसी दशा हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब पहले बाढ आई थी तो उस समय पंजाब के लोगो ने 150-200 जगहों पर कट करके, जो एस०वाई०एल० हरियाणा में बनी हुई है, उसमें पानी डाल दिया था जिसके कराराग नुकसान हुआ था इस बार भी पंजाब के लोगो ने सारा पानी एस०वाई०एल० मे डाल दिया जिसकी वजह से कैथल जिला, कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिले को नुकसान हुआ। इस काम के लिए पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी बराबर के दोषी हैं क्योंकि उे समय के इंजीनियर इन चीफ, जो मि० पाठक थे, उन्होंने बंसी लाल जी को कहा था कि पहले एस०वाई०एल० नहर पंजाब में बनने दी जाये, उसके बाद हमारे यहां पर बने लेकिन उनकी बात को न मान कर कमीशन खाने की लालसा भै यह

एस०वाई०एल० नहर हरियाणा मे खोदी गई। (शोर) यह बात तथ्यों पर आधारित है।

चौधरी बंसी लाल: कमीशन खाना तो इन का धंधा रहा है। जैसे ये है वैसे ही दूसरों को समझते हैं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: यह तो एकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है। बिजली के खम्भों में इन्होंने कमीशन खाया। आई०जी० डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट है कि इन्होंने मुख्य मन्त्री के पद का दुरुपयोग करके 1, 12, 91,85,00/- रुपये इकट्टे किये हैं। (विधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि बाढ़ की जो बात चल रही है, इस भीषण बाढ़ के लिए चौधरी बंसी लाल का भी उतना ही उत्तरदायित्व है अगर यह नहर गोद-बड़ावा से शुरू नहीं की जाती तो यह नौबत न आती। 91 किलोमीटर लम्बी नहर हरियाणा में बनी गै। अगर पंजाब को बनी बनाई ड्रेन नहीं मिलली तो वे इस का पानी इसमें नहीं डाल सकते थे। पंजाब को बनी बनाई नहर मिल गई, इसका नतीजा यह निकला कि उन्होंने बाढ़ का सारा पानी इस में डाल दिया। चौधरी बंसी लाल जी बड़े फख और गर्व से कहते हैं कि उन्होंने पक्की ड्रेन बना कर दी है। इस ड्रेन से पानी आने के कारण भारी तबाही हुई है। चौधरी बंसी लाल जो सदन में बैठे हुए हैं, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इन्जीनियर मि० पाठक इस नहर के पक्ष में नहीं थे, उसकी रिपोर्ट है, लेकिन पाठक की बात को इन्होंने नहीं माना। वह बेचारा यू० एन०ओ० में चला गया। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त ये उस युग के

तानाशाह थे। ये तो आज भी कहते हैं कि एमरजैसी ठीक लगी थी और दांव लगा तो फिर एमरजैसी लगाऊंगा। इससे इस आदमी की जेहनियत का पता लगता है कि यह किस सोच का है। ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश की दयनीय स्थिति के लिए मैं प्राकृतिक प्रकोप को तो मानता हूं, लेकिन इसके साथ मौजूदा मुख्य मन्त्री और पूर्व मुख्य मन्त्री दोनों बराबर के दोषी हैं। इन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। अध्यक्ष महोदय, इनको मुलजिमाओं के कटघरे में खड़े करके इन पर मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए, इनके खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम इनके खिलाफ मुकद्दमे चलाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की यह जिम्मेदारी होगी, जब हमारी सरकार आएगी, हमारी पार्टी की सरकार होगी, सारे प्रदेश में प्रयास करके बाढ़ को रोका जाएगा और बाढ़ से आइन्दा लोगों का नुकसान नहीं होगा। हमारी पार्टी की सरकार ने 1978 में रिंग बान्ध बनाए थे, जिसकी वजह से आबादी बाढ़ के प्रभाव से बची थी क्योंकि हमारी सरकार के वक्त ड्रेनें खुदी थीं, अब जब हमारी सरकार बनेगी तो गांव-गांव में रिंग बांध बांधे जाएंगे ड्रेनो की सफाई करवाएंगे ओर जहां पर नई ड्रेनें खोदनी पड़ेगा, वहां खुदवाएंगे और हम सारे लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। जो सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में विफल हो जाए, उस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह चाहूंगा कि यह सरकार इस्तीफा दे। जो सरकार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं

चला सकती इस तरह की सरकार हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा कैसे कर पाएगी, हरियाणा प्रदेश कैसे चलेगा, क्योंकि यह सरकार नाअहल है। सत्ता चलाना इनके बस की बात नहीं है इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। समय आने पर इनको पता चल जाएगा। (विघ्न) हम तो अपने फर्ज के पाबन्द हैं लेकिन यह सरकार अपने फर्ज से कोताही कर रही है, अपने फर्ज को निभा नहीं पाई है और न ही स्वच्छ प्रशासन दे सकी है, इसलिए मैं आपके द्वारा कहूंगा कि आप केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति महोदय को लिखें कि यह सरकार नाअहल है, इस सरकार को बरखास्त किया जाए ताकि नये सिरे से चुनाव हों और लोगों को रहित प्राप्त हो। मैं चौधरी बंसी लाल जी से कहूंगा कि वह अपनी बात कहते समय एस०वाई०एल० के बारे में खुलकर बताएं ताकि सही बात सामने आए। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, इन श्रीमान जी नैं अनपार्लियामैंटरी लैग्वेज इस्तेमाल की है। ये खूद मुख्य मन्त्री रहे हैं इसलिए अनपार्लियामैंटरी लैग्वेज को इस्तेमान करते हुए इन्हें अनपार्लियामैंटरी लैग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। स्पीकर सर, बाढ़ का क्रोप वारिश ज्यादा होने की वजह से हुआ है, उसका ये पोलिटिकल गेन लेना चाहते हैं। इन्हें पोलिटिकल गेन नहीं लेना चाहिए। इनको लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, इन्हें सरकार को कोई सुझाव देना चाहिए ताकि लोगों को कोई

राहत मिल सके लेकिन ये पोलिटिकल गेन लेना चाहते हैं, यह विल्कुल गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि इन्हें अनपार्लियामेंट्री लैग्वेज का इस्तेमाल न हीं करना चाहिए। बाढ़ की वजह से जो ये पोलिटिकल गेन लेना चाहते हैं, वह नहीं लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब, आप अपने टाईम पर पूरा जवाब दे लेना। यह ठीक है, इन्होंने अपनी बात कह ली, आप अपने वक्त अपनी बात कह लेना। देहात में जो बांध बांधे हैं उनकी मुरम्मत हुई है, हमारे इलाके में भी पैसा आया है और काम हुआ है, ड्रेनों की मुरम्मत भी हुई है। सरकार ने जो राहत दी है वह भी हमें मालूम है। बाद में अपना पूरा जवाब दे लेना।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है। मुझे इनकी एक बात का तो अभी जवाब देना पड़ेगा, फिर पता नहीं ये हाउस में आएँ या नहीं आएँ। दो तीन दफा इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ गई। अध्यक्ष महोदय, अगर ये दोबारा एम०एल० ए० बन कर आ जाए तो यह भी राम जी की माया होगी। अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बाणी को नोट कर लीजिए कि आज ये 17 एम०एल०एज० हैं लेकिन अगली बार ये सात भी नहीं रहेंगे, मेरी यह बात रिकार्ड में रहेगी। आपके सात मैम्बर भे। चुन कर नहीं आएंगे। मुकाबला तो चौधरी बंसी लाल और आप में है। आप क्या कहते हैं कि आपका राज आएगा? इनको कुछ तो

करना चाहिए। इनको मर्यादा में रह कर बोलना चाहिए। हमारी तो 60 सीटें अवश्य आयेंगी और राम हम बनायेंगे।

(शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शब्द कहा है क्या वह पार्लियामैंटरी है? इसे आप एक्सपंज करवाइए।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जो ने जो अन-पार्लियामैंटरी शब्द कहा है वह कार्यावाही से निकाल दिया जाए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस कह रहे हैं कि हम दोबारा नहीं आएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं, ये यहां पर बैठे हैं और ये भी इस्तीफा दे दे। ये खुद देख लेंगे कि कौन आएगा, कौन नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहें कि ये इस्तीफा दे दे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छतर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। अब श्री बंसी लालजी बोलेंगे।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, इस बार जो प्रदेश में बाढ़ आई यह अनप्रेसिडेंटिड है। इस बाढ़ से जो

तबाही हुई है, इसका सही अन्दाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है कि इससे कितनी जान और माल का नुकसान हुआ है। इस बारे में तब तक पता नहीं चलेगा जर तक बाढ़ पर कंट्रोल नहीं होगा। तभी लोग बताएंगे कि उनका कितना-कितना नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, रोहतक, जीन्द, भिवानी, सोनी पत, कैथल, रिवाड़ी, गुडगांव, फरीदाबाद, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र का मैंने दौरा किया है। अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले में बहुत भारी तबाही हुई है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है। मेहम शौर बेरी कांस्टीचुएसी के बहुत से गांवों में जाने के लिए रास्ता नहीं है। हसनगढ़ के भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से जींद का भी यही हाल है। नरवाना में पांच गांव ही ऐसे हैं जो अन-इफैक्टिव हैं। कलायत में बताते हैं कि वहां पर जो सड़क का रास्ता था, वह अब बोट का रास्ता बन गया है। उचाना और राजौंद में भी गांवों तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। भिवानी जिले में जयश्री गांव है जो पूरा ही डूब गया है, वहां मकानों की पहली मन्जिल नजर ही नहीं आती है सोनीपत में गोहाना तहसील सबसे ज्यादा इफैक्टिव है। बाकी इलाकों में बाढ़ का काफी पानी भरा हुआ है और रिवाड़ी में 5 - 5 फुट पानी आ गया था और एक-दो गांवों में पानी अभी तक खड़ा है। कैथल में गुलियाना सौगरी गांव है, वहां आज भी बोट से जाया जाता है। हिसार जिले के बारे में तो मुख्य मन्त्री जी जानते हैं। मेवात जिले में 150 गांवों पर असर पड़ा है जो मैंने खुद देखे हैं। पानीपत में

समालाखा हल्के में 15- 20 गांवों में बाढ़ आई है। कुरुक्षेत्र में थानेसर, पेहवा और लगभग 31 या 32 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जो गांव सबसे ज्यादा खराब हैं, सबसे ज्यादा खस्ता हालत में हैं उनमें से मैंने एक गांव को देखा है वह जीन्द जिले में पोली गांव है। वहां पर आज भी 16 किलोमीटर लम्बी चौड़ी पानी की एक शीट बनी हुई है। खास- तौर से दडौदा, बढाना, मड़ोर ढाकल, किठाना आदि गांवों में न तो पाने का पानी शौ तभ न ही दूसरी जरूरियात की चीजों का प्रबन्ध है। अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां मैं गया, वहां मैंने एक बात देखी। किसी भी गाँव मे जहां लोगो को डूबने का खतरा हुआ तो उन्होंने सड़क काट दी। अगर उनका नहर का टने से काम चला ते। नहर काट दी। अध्यक्ष महोदय मैंने जो स्टडी किया है उसके आधार पर मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, बाकी स्टडी तो इन्जीनियर ही करेंगे। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि 1993 के बाद से अब तक जो भी गलतियां हुई हैं, उनको सरकार सुधारे और पूरे हरियाणा के लिए एक मास्टर प्लान बनाए ताकि अगर आईन्दा इस किस्म की बात हो जाए तो उसका इलाज किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि पाई सेरदा भूयाना से पानी चलता हुआ राजौन्द और असन्ध के इलाकों में से होता हुआ जींद जले में चला जाता है और वहां इस पानी के तीन चार हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा तो इस तरह से बन जाता है कि वह पानी पुरानी सिरसा ब्रांच में टकराता है। अगर इस पानी को, जिसका बहाव उचाना से होता हुआ सिरसा ब्रांच के पास तक जाता है को एक ड्रेन बना कर पुरानी

सिरसा ब्रांच में डालकर आगे भेज दिया जाए तो यह ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा, दूसरा रास्ता पानी ने इस तरह से बनाया कि वह जुलाना, महम वगैरह से होता हुआ कलानौर को चला गया। फिर वह पानी भिवानी जिले में भी चला गया है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे यहां पर बारिश होती ही नहीं लेकिन इस बार हमारे यहां बारिश हुई तो ऐसे हुई कि उसने हमारे को कुछ ज्यादा ही सजा दे दी। जैसा कि प्रो० छत्तर सिंह जी बता रहे थे कि दादरी की नहर के दोनों तरफ आदमी बन्दूक ताने खड़े हैं। कलानौर वाले चाहते हैं कि इस नहर को काटा जाए लेकिन बौद चिचा एवं रानीला वाले चाहते हैं कि नहर को न काटा जाए। इसी को लेकर यहां पर दिन में तो एक हजार और रात के। चार हजार आदमी पहरा देते हैं, यानी वहां पर बहुत बुरा हाल है। अगर सोचा जाए तो यह हो सकता है कि जो इन्दिरा गांधी कैनल है, जिमको लोहारु कैनल भी कहते हैं, उसको मैंने स्वयं देखा है, पहले इस नहर की कपैस्टी 1250 क्यूसिक्स की थी लेकिन अब इसमें 126 से लेकर 310 क्यूसिक्स तक ही पानी चल रहा है। लोहारु और बाढडा के इलाकों में बहल तक, अगर जुई कैनल, सिवानी कैनल और लोहारु कैनल को चलाएं तो वहां पर जो फसलो में सोखा आया हुआ हो उसमें काफी कमी आ सकती है। अध्यक्ष महोदय, दादरी में 32 या 36 पम्पों में से सिर्फ 8 पम्प ही चल रहे हैं। जो जे० एल० एन० कैनल है, अगर उसमें पानी डालकर आगे नारनौल एव सतनाली के बालू रेत के टिब्बों को दिया जाए तो रोहतक और सोनीपत का सारा पानी निकल सकता है, मगर उसमें भी

पानी निकालने का प्रबन्ध नहीं है, वह खाली पड़ी है। मैंने ड्रेन नं० 6 भी देखी। ड्रेन नं० 8 पर हम इत्तिफाक से खड़े थे तो वहां टैलीविजन वाले भी आए थे। बेरी हल्के के ढराणा गांव में एक किशती दे रखी है और सारा गांव लैट्रिन जाने के लिए किशती या ट्रैक्टरों से गांव से डेढ़ दो किलोमीटर बाहर सड़क पर आता है, कम से कम उनको दो किशती और दे दी जायें। इसी तरह से दुजाना गांव की 10 हजार से ज्यादा आबादी है। हमने उनसे पूछा कि कोई सहायता आई है तो उन्होंने कहा कि एक दिन एक हैलीकॉप्टर एक पैकेट फैंक गया था। उस पैकेट में 141 छोटे पैकेट थे जिनमें 3-3 पूरियां और खुश्क सब्जी थी। उच्च गांव की आबादी का 60 फो सदी हिस्सा हरिजनों का है, गरीब आदमी हैं। दवाई के लिए पूछा तो गांव वालों ने बताया कि हमारे यहां दो डाक्टर हैं, दोनों सी० एम० ओ० के पास दवाइयां लेने गए हैं। इसी तरह हम बेरी गए तो हमने पूछा कि क्या आ पके पास भी कुछ आया है? उन्होंने बताया कि हमारे आने से आवा पौन घण्टा पहले एक हैलीकाप्टर 419 पैकेट रखकर आया, जिनमें 5-5 पूरियां, खुश्क सब्जी और भुगडा था। पीने के पानी में दवाई डालने के लिए कहीं-कहीं थोड़ी पहुची है। यह हालत जींद जिले की है, यही सोनीपत की है यही रोहतक की है, यही भिवानी की है। जो कुएं हैं वह कुएं बराबर हो गए हैं, सब जगह पानी से भर गए हैं, अब अगर इन्सान या मवेशी पानी पीएंगे तो इससे लोगों को पीलिया होगा। पिछले। बार भी पीलिया के बड़े केसिज हुए थे। यह जो चीजे हैं, इनके०पर सरकार को खास तौर पर ध्यान

देना चाहिए। मैंने देखा कि इस बार कैथल और पेहवा में बाढ़ तो नहीं आई, मगर मैं आपके जरिए मुख्य मंत्री जी की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि हर जिले में एक फ्लड कंट्रोल बोर्ड होता है, जिसका अध्यक्ष दो० सी० होता है, 4-5 एक्सीयन मेंबर होते हैं और मानसून से 5 दिन पहले उन सबको पूरी तरह से अपने जिले का इन्सपैक्शन करके, स्टेट लेवल पर कंट्रोल बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। क्या वह रिपोर्ट भेजी गई है और अगर भेजी गई तो मैं कह सकता हूँ कि मुख्य मंत्री जी के पास सही रिपोर्ट नहीं आई? मुख्य मंत्री जी हिसार की तरफ कई बार जाते हैं, पेहवा में देख लें। पेहवा की जो ड्रेन है, उसमें कीकर खड़ी है। पेहवा और करनाल के इलाके में डेढ़ फुट लम्बी समुद्रसीख है जो पानी को चलने नहीं देती। वीड बड़ी हुई है, काटी नहीं गई है। इसी तरह से कैथल की ड्रेन है। अध्यक्ष महोदय, आपका भी वही रास्ता है कैथल ड्रेन में भी इसी तरह से समुद्रसीख और वीड खड़ा है, कीकर भी खड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब हम बेरी हल्के के पास ढराणा गांव में खड़े थे तो वहां टी० वी० वाले भी आए थे। मैंने उनको दिखाया कि ड्रेन नं० 8 में बड़ी-बड़ी कीकर बड़ी है। पेड़ों की टहनियां टूटकर साइफन के आगे आ गई हैं। पानी तो नहीं जा सकता। उस वक्त अगर आफिसर सोचते होते तो उनकी मिट्टी निकाली गई होती। अगर उस वक्त वे चौकन्ने रहते और साइफन को खुला रखते तो काम चल सकता था। आज दादरी पानी में डूब रहा है, भिवानी डूब रहा है, रोहतक डूब रहा

है अरि लोहारू, बाढडा, सतनाली और शिवानी के इलाके डूबे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, छोटा सा हरियाणा है। एक तरफ डूबा पड़ा है और दूसरी तरफ खाली है। मैं तो यह कहूंगा कि आपके पास नहरें बनी पड़ी हैं। वहां पर पम्प लगाकर पानी आगे तक किसानों की फसलों में पहुंचाने का सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये ताकि किसानों को राहत मिले। बहुत से खेतों में जाकर देखा है वहां पर छ रू छः—सात—सात फुट पानी अब भी खड़ा है। मैं यह नहीं कह सकता कि रबी की फसल कैसे होगी, इसका मुझे तो कोई ढंग नजर आ नहीं रहा, लेकिन जहां जहां रबी की फसल की काश्त हो सकती है, वहां से सरकार को जल्दी ही पानी निकालने का प्रबन्ध करना चाहिये लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अखबारों में आया है कि स्टेट के अन्दर 1200 या 1500 के लगभग पम्प चल रहे हैं। हमें तो कहीं कोई सरकार की अचीवमेंट दिखायी नहीं दी। वहीं कौई खास जगह पर सरकार ने इस का इन्तजाम कर रखा हो तो हम कह नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, पम्पों के बारे में, मैं क्या कहूं, उनमें भी बीमारी है। हम भिवानी से दादरी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में हमने रेलवे के पुल पर खड़े होकर देखा कि चार पांच पम्प चल रहे हैं परन्तु एक बहुत बड़ा पम्प था जिसको लोगों ने खोल रखा था। हमने उनसे पूछा कि भाई इसको क्यों खोल रखा है तो उन्होंने बताया कि इसमें प्लास्टिक के छ—सात लिफाफे फंसे हुए हैं,

उनको हम निकाल रहे हैं जिसकी वजह से पानी रुका पड़ा है। अध्यक्ष महोदय अगर उस पम्प की पिछली साइड पर छाबडी लगा दी जाए तो कम से कम प्लास्टिक के लिफाफे तो न फंसे जिस की वजह से पम्प नहीं चलते। कोई रुक। वट न आए, इस की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं, न ही अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देते हैं। इसलिये अगर सरकार व सरकार के अधिकारी मग्न छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देवें तो ऐसी दिक्कत द्र हो सकता है। मगर इस तरफ सरकार तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय, पलड कंट्राल बोर्ड की 30 जून से पहले-पहले मुख्य मंत्री महोदय हर साल एक मीटिंग करे और स्थिति को रिव्यू करें, पर मुझे पता नहीं कि मुख्य मंत्री महोदय ने कभी इस बात को रिव्यू किया या नहीं।

चौधरी भजन लाल: तीन-चार बार किया।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, एक नैचूरल क्लैमिटी फण्ड सरकार के पास होता है जौ खासतौर पर इन्ही कामो के लिये होता है कि कही भूकम्प आ जाए या बाढ़ आ जाए तो उस परपज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया गहर साल इस फण्ड मे से खर्च किया गया। मेरे विचार से तो सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है क्योकि जहां तक हमने देख है,

ड्रेनेज का बहुत बुरा हाल पै उनकी सफा ई नही हुई है। साईफन मिट्टी से रुके पड़े है। अध्यक्ष महोदय एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि जिन किसानों ने फसल के लिये कर्जा लिया है, ट्यूबवैल्ज के लये कर्जा लिया है या फिर किसी और चीज के लिये कर्जा लिया है, किसी फसल के लिये कर्जा लिया है। वह तबाह हौ गई है। ट्यूबवैल्ज के लिये कर्जा लिया, वह बै गया, मोटरे बेट गई, इस तरह का जो उनका कर्जा है या लैन्ड रेवेन्यू एरियर्ज है, जो भी कर्जा है, उस को दो चार सालों के लिये पोस्टपोन कर दिया जाए और इस अर्से का ब्याज भी उन से न लिया जाए। आज आम आदमी का, इस हालत में बाढ़ के कारण जो उसकी तबाही हुई है, गुजारा होना मुश्किल है। रबी की फसल की काश्त करने के लिए किसानों को कर्जा दिया जाए, सबसिडी दी जाए क्योंकि पहले ही किसान 1000- 1500 रु० लगाकर फसल बीज चुका है और वह फसल उसकी बर्बाद हो चुकी है अब दोबारा किसान बे चारा कहां से फसल के लिये पैसे लाएगा। इसलिये सरकार को किसानों की हर लिहाज से मदद करनी चाहिये। जिस किसान के मवेशी मर गये हैं, वह कहा से उनकी पूर्ति करेगा। आज एक भैस लगभग 10 हजार से 20 हजार रुपये तक की आती है और कई जगहों पर किसानों की भैसे मर गई। जो मवेशी बाढ़ आने पर खूंटे से बचकर निकल गये, भाग गये, वह तो बच गये और जो खूंटे पर बन्धे रह गये, वह मर गये। मैंने भिवानी में एक जगह पर देखा कि तक भैस मरी पड़ी थी और उसको सूअर खा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां सरकार कर्ने माफ कर सके वे करने चाहिए। गरीबों के कर्जे, किसानों के कर्जे या मजदूरों के कर्जे भी माफ करे और ब्याज जरूरी तौर पर माफ कर दें। अब आगे सर्दी आ रही है। सर्दी में बेचारा गररू। ब आदमी क्या करेगा। उसको सिरकी भी देनी चाहिए। कच्चे मकान जो गिरे हैं सरकार उनका मुआवजा पांच हजार रुपए देना चाहती है। फर्ज करो एक आदमी का पूरा कच्चा मकान पड़ गया लेकिन एक तूड़ी का कोठरा रह गया तो इनके अफसर कहते हैं कि पूरा मकान नहीं पड़ा है। उनका वह कोठरा भी साथ में लिखना चाहिए अध्यक्ष महोदय, बहुत से गायें 100-1500 घरों के हैं लेकिन यहां 50 से ज्यादा घर साबुत नहीं बचे हैं। हरिजनों को जो प्लाट मित्ने थे, वे गांवों के वाहर नीची जगह पर मिले थे। वे सारे पानी में डूब गए और पड़ गए। जो पक्के मकान थे उन सब में दरारें आ गईं। इनको भी सरकार को किसी न किसी किस्म की रियायत देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पानी की वजह से जितने दिन बिजली बन्द रही, कम से कम उस अरसे के बिल किसानों को नहीं जाने चाहिए क्योंकि आपने उस दौरान बिजली ही सप्लाई नहीं की। इन तरह से जो-जो रियायतें सरकार गरीब आदमी को दे सकती है, वह उनको देनी चाहिए। सरकार को मजदूरों के लिए मजदूरी का प्रबन्ध भी करना चाहिए। आज बहुत सारी सड़के टूट गई हैं, उन सड़कों पर उनको मिट्टी डालने का काम, ईट पत्थर और रोड़ी डालने का काम देना चाहिए। आन गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसके अलावा आज

90 परसैंट जगहों पर क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर नहीं पहुंचा है। जब तक यह नहीं पहुंचेगा तो बीमारी फैलेगी। हमने जिस गाव में भी पशुओं के बारे में पूछा तो पता चला कि 25— 30 परसैंट मवेशियों को गर्भ के टीके तो लगा दिए लेकिन पानी की वजह से बहुत से मवेशियों को मुंह और खुर आ एर हुए हैं, उसके टी के नहीं लगाए गए। वह टीके भी लगने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देहात में गरीबों के छोटे छोटे बच्चे हैं जिन के लिए दूध भी जरूरी है। उनको दूध के पाउडर के पैकेट भेजने चाहिए क्योंकि गरीब आदमी दूध कहां से लेगा। अध्यक्ष महोदय, एक चीन के बारे में मैं नहीं कह सकता कि ठीक है या गलत है, लेकिन हमें कुछ गांवों में लोगों ने कहा कि जो बांध हमने बनाए हैं, कई जगह हमने देखा कि गांव वालों ने नए बाग बनाए हैं और उन पर कट्टे लगा दिए। वे कहते हैं कि सरकार के बी०डी०ओ० या पटवारी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस पर दस्तखत कर दो यह बांध हमने बनाए हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जहां पर सरकार फंड रिलीफ का पैसा खर्च करती है उस पर गांव की आबादी के हिसाब से पंच या सरपंच के अंगूठे जरूर लगवाए। हो सके तो उस गांव के 20—26 मुअजिज आदमियों के दस्तखत भी करवाए जाए। अगर ऐसा न किया गया तो इस पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन होगा। इसका इलाज सरकार जरूर करे। एक बात और है। मुख्य मंत्री जी ने अपने एक व्थान में कहाँ कि हमने भिवानी का 90 परसैंट और रोहतक का 80 परसैंट पानी निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्री जी को अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी

हैं, वह ठीक नहीं है। कल मैं पूरे शहर में धूम कर आया हूँ। भिवानी में 40 परसेंट पानी निकला है, 60 परसेंट अभी निकालना बाकी है। भिवानी में हरिजनों की ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसका एक इंच भी पानी निकला हो। मैं अपनी आखों से देख कर आया हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। दादरी में दादरी दरवाजे से लेकर रविदास बस्ती तक और महेन्द्रगढ़ सड़क तक पानी खड़ा है। वहाँ के अस्पताल में अढ़ाई-अढ़ाई और तीन-तीन फुट पानी खड़ा है। इसके अलावा भी कई जगहों पर पानी खड़ा है। उस पानी को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दादरी के पास एक रावलदी गांव है। उस गांव में एक तिहाई गांव में 6-6, 7-7 और 8-8 फुट पानी खड़ा है। वहाँ से 15-20 किलोमीटर तक आप चले जाएं, समुद्र की तरह पानी खड़ा है। उस पानी को निकालने का प्रबंध करना चाहिए। इन्दिरा गांधी कैनल और उसके साथ लाते गांवों का पानी किसी तरह से नहीं निकाला गया और वह पानी अगर आगे बढ़ गया तो दादरी शहर को खतरा हो जाएगा। जो गांव बाढ़ के पानी से थोड़े बहुत बचे हैं, वे भी उस पानी से डूब जाएंगे। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच गया। इसके अलावा, मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ से बाबू का पानी निकल गया वहाँ से गाद निकलवानी जरूरी है। लोग गांव में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे तो उस गाद के कारण बीमार हो जाएंगे। शहरों और गांवों की गाद निकलवानी जरूरी है और उस गाद को गांव और शहर से काफी दूर डलवाए उस पर दवाई का छिड़काव भी कराएं। उस

गाद पर बालू रेत का 4 या 6 इंच का लेयर करवाएं। अगर गांवों और शहरों में बीमारी फैल गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उस गाद को निकलवाने में कम पैसा खर्च होगा लेकिन बीमारी को कंट्रोल करने में ज्यादा खर्चा होगा। मैं समझता हूँ कि सरकार को यह काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अगर रबी की फसल कास्त करने का प्रबन्ध नहीं होगा तो गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं परसों असंध से जींद जा रहा था, रास्ते में मैंने अपनी गाड़ी रोक ली। मेरे पास एक-दो आदमी आ गए, हेंने उनसे पूछा कि यह कौन सा गांव है? उन्होंने कहा कि यह खाण्डा गांव है। मैं तो यह समझता था कि खाण्डा हांसी तहसील का गांव है लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे इस गांव की जींद तहसील है। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस गांव में बाढ आई थी, तो उन्होंने बताया कि बाढ का पानी आया था और वह निकल गया। मैंने उनसे कहा कि आपके गांव में बाढ के कारण कितने घर गिर गए, तो उन्होंने बताया कि 60-70 घर गिर गए। फिर मैंने पूछा कि जिनके घर गिर गए, क्या उन सब के घर लिख लिए गए, तो उन्होंने कहा कि सब तो नहीं लिखे। मैंने कहा सब के क्यों नहीं लिखे तो उन्होंने कहा कि पटवारी शराब की बोतल मांगता है। पटवारी कहता है कि पहले आप मुझे बोतल दे दो फिर लिखूंगा। अध्यक्ष महोदय, पानी कम निकलने की बीमारी यह भी है कि जे० एल० एन० कैनल की कैपेसिटी 3200 क्यूसिक्स की है, अब उसमें मिट्टी भर जाने के कारण उसकी कैपेसिटी 1200 क्यूसिक्स रह गई है। इसी तरह से हांसी ब्रांच की कैपेसिटी 5600

क्यूसिक्स पानी की है, लेकिन उसमे मिट्टी भर जाने के कारण उसकी कैपेसिटी 4000 क्यूसिक्स रह गई है। अगर उनकी डी-सिल्टिंग का काम नहीं करेगे तो काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर दरखत कट कर न पड़े हों। बेशुमार दरखत टूट-टूट कर सड़कों पर गिरे पड़े हैं, कटे पड़े हैं। उन दरखतों को प्राईवेट लोगों ने आगे आगे से काट लिया है और रात को अगर कोई मोटर साइकिल या स्कूटर पर चढ़ कर आएगा और उसके सामने से कोई ट्रक या बस आ गई तो उस मोटर साइकिल या स्कूटर सवार का सिर सी धा लक्कड़ पर लगेगा। मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, उन दरखतों को फारेस्ट डिपार्टमेंट और पी०डब्ल्यू०डी० के द्वारा हटवाना चाहिए। अगर सरकार उन दरखतों को बेचेगी तो सरकार को भी फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए सिरकी का प्रबंध होना चाहिए और जैसे मैंने पहले कहा, बच्चों के लिए दूध का भी प्रबंध होना चाहिए। प्रदेश की सारी सड़कें बाढ़ के कारण टूट चुकी हैं, इसलिए उनकी मरम्मत करवाना बहुत ही जरूरी है। अगर सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तो रास्ते नहीं खुलेंगे। उन पर गाड़िया चलेगी पीं टायर ज्यादा घिसेगे और तेल का भी ज्यादा खर्चा होगा। यह नैशनल लौस होगा क्योंकि रबड़ भी बाहर से आता है और तेल भी बाहर से आता है। अगर मुख्य मंत्री जी जायज समझें तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से मदद लेने के लिए एक प्रस्ताव पास करके भेजें क्योंकि बाढ़ से अरबों रुपयों का नुकसान हरियाणा में हुआ है। रोहतक

शहर में जो सूरी मार्किट है, उसमें एक-एक आदमी का 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह मार्किट हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़े की मार्किट है। वहां शहर के अन्दर टैलीविजन-सैट इस प्रकार से तैर रहे थे जैसे कोई टहनी या फूल पानी में तैर रहा हो। साथ ही सरकार यह जांच करवाए, चाहे किसी हाई कोर्ट के जज से करवाए कि शहर में पानी कैसे आया और इसको किसने डुबाया।

अध्यक्ष महोदय, जो लोग बाटू से मारे गए हैं उनके वारिसों को कम से कम एक- एक लाख रुपये तो जरूर देने चाहिए। जो लोग बाढ़ से मारे गए हैं उनका कोई कसूर नहीं था। जो फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है उसका 3 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जरूर देना चाहिए। जहा पर नुकसान 50 से 75 प्रतिशत तक हुआ है, वहां 2000 से 2500 रुपये तक का मुआवजा सरकार को देना चाहिए ट्यूबवैल्ज डैमेज हुए हैं उनको भी 25000 रुपये जरूर देने चाहिए। एक तो लोगों ने कर्ज लेकर ट्यूबवैल लगाये थे और अब०पर से वे बेकार हो गए हैं। अतः सरकार इस बात पर ध्यान दे। हरियाणा का किसान मेहनत से काफी अन्न पैदा करता है और केन्द्र को हर साल लाखों टन अनाज जाता है। अतः सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिन लोगों के मकान इस बाढ़ से टूट गए हैं, उनको पक्के मकान के लिए कम से कम 25 हजार रुपए और कच्चे मकानों के लिए 20 हजार रुपए दिए जाए ताकि वे फिर

से बना कर रह सके। इसी प्रकार से जिन लोगों के पशु—भैस गाय व बैल आदि मारे गए हैं, उनकी कीमत का भी अन्दाजा लगा कर पैसे दिए जाएं ताकि वे फिर से अपना काम कर सकें। जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उनकी भी मदद सरकार को करनी चाहिए। दादरी में अकेले 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और रोहतक शहर में तो अरबों रुपये का नुकसान हुआ है दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में जब तक कोई सौलिड नीति नहीं बनाई जाएगी, तब तक यह काम ठीक प्रकार से नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, जिन—जिन प्राइवेट संस्थाओं ने और सामाजिक संस्थाओं ने या इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इतनी समाज सेवा की है, उनको सदन की तरफ से एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास करके भेजना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने वहां जा कर मदद की है जहां सरकारी मशीनरी नहीं पहुंच पाई थी। ये लोग अब भी खाना, दवाई और दूसरी चीजें लोगों को दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और देवी लाल ने एक बात कह दी कि एस० वाई० एल० से पंजाब का पानी हरियाणा में आ गया। मैं यह नहीं कहता कि पानी बिल्कुल नहीं आया। जब कैथल पिहोवा का पानी भिवानी तक पहुंच सकता है तो पंजाब का कुछ पानी एस० वाई० एल० में आया है लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब जरूरत होती है तो भाखड़ा मेन—लाईन तथा नरवाना ब्रांच का पानी एस वाई० एल० के थ्रू एन० बी० के जरिए ले जाया जाता है और उसको

इस्तेमाल भी किया जाता है अध्यक्ष महोदय, अगर वह नहर हरियाणा में न बनती तो हरियाणा पंजाब से क्या कह कर पानी मांगता? चौटाला साहब के पिता चौधरी देवीलाल के दोस्त प्रकाश सिंह बादल कह देते कि हरियाणा में नहर ही नहीं है, पानी कहां से ले जाएंगे, इसमें यह दलील आ जाती। चौटाला साहब को ऐसा लगता है जैसे वगैर खाए कोई आदमी कदम नहीं रखता, इसी तरह ये बगैर खाए अगला कदम रखते ही नहीं थे, इसलिए इन को हर आदमी खाने वाला और कमीशन लेने वाला नजर आता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इंजीनियर, श्री पाठक की राय मैंने नहीं मानी। अध्यक्ष महोदय, पाठक अभी जिन्द। जागता है, वह बहुत ही लायक इंजीनियर हैं। पाठक साहब से आप पूछ लें। पाठक साहब ने अगर इसके हक में राय दी हो और फिर वह नहर बनी हो तो फिर चौटाला साहब को सदन में माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गलत— सलत बात कहने की इनकी आदत शै। दूसरों को तो ये कहते हैं कि पार्लियामैंटरी भाषा का इस्तेमाल करो, चेयर को एड्रैस करो लेकिन खुद मुंह उधर दूसरी तरफ रखते हैं। लगता है इनको खुद नहीं पता, भाई की रेल कहा टिकती है। ये महम के कातिल हैं और दूसरों को कहते हैं कि कमीशन खा गए। अध्यक्ष महोदय, इनकी मुख्य मन्त्री जी से मिली भगत है, वरना ये श्रीमान जी आज अन्दर होते। मुख्य मन्त्री जी इनकी लिहाज कर रहे हैं इन्होंने महम में कितने कतल करवा दिए? जिस आदमी ने इतने कतल करवाए वह आज सदन में बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिख दिया कि उसका कातिल

कौन है वह कातिल सदन में बैठा हुआ है. यह बडी शर्म की बात है। वे कहते हैं कि इस्तीफा दे दो। अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा तो दो महीने में वैसे ही हो जाएगा। इन्होंने पहले भी इस्तीफा दिया था लेकिन बाद तक का टी० ए० डी० ए० ने गए। आज फिर ये इस्तीफे का ड्रामा रच रहे हैं, समझ में नहीं आता कि यह क्या तमाशा है। जो फिर इनकी मर्जी आए कह देते हैं, क्या इनको कहने का लाईसैंस मिल गया है?(विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को यह सुझाव दूंगा और कहूंगा कि ड्रेनेज के बारे में जो सुझाव मैंने दिए हैं उनको ये सो — नैं विचारें ओर गहराई से उन पर अमल करें। सैंटर से आज आपको जो सहायता आ रही है, उसको खर्च करने में नीचे वाले लोगों से दस्तखत जरूर करवाएं कि फलां यह इतना काम हो गया है, वरना यह फंडज का मिसयूज होगा। अगर इस सदन के सदस्यों की कोई 'कमेटी' बना दें तो बहुत फायदा है, कोई नुकसान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ (विधन)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। एस० वाई० एल० के बारे में मैंने जो बात कही थी चौधरी बंसी लाल उस बात पर आए ही नहीं। यह

तो रिकार्ड की चीज है, सरकारी रिकार्ड की बात है। एस० वाई० एल० नहर हरियाणा प्रदेश में 91 किलो मीटर इनके शासनकाल में बनी और वह नहर अगर शुरू में पंजाब में बन गई होती तो आज यह सारा बखेड़ा न होता। न बाढ का इतना पानी आता बल्कि हरियाणा प्रदेश की प्यासी धरती को पानी मिल जाता। इन्होंने यह नहर बनवाई ही इसलिए वो क्योंकि पंजाब में कंस्ट्रक्शन पर वर्क होता तो पैसा हमारा लगता लेकिन इनको कुछ नहीं मिलना था। ये कह रहे हैं कि मेरी ऐसी आदत नहीं। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में आडिटर जरनल की रिपोर्ट है, इसमें क्लीयर आया है कि पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिजैक्टिड पोल्ट्ज जो ज्यादा पैसा दे कर खरीदे गए हैं, उसमें पैसा खाया गया है (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी की बात बता रहा हूँ। मैं इनसे कोई गिला भी नहीं करता क्योंकि इनको हरियाणा के हितो से प्यार नहीं है। स्वर्गीय कम सिंह लोक सभा के एक्स स्पीकर की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, पंजाब और हरियाणा के बंटवारे के बारे में, चाहे पंजाब बने चाहे महा पंजाब बने इसका निर्णय होना था। चौधरी बंसी लाल राज्य समा के मैम्बर थे, स्वर्गीय चौधरी लहरी सिंह लोक सभा की तरफ से मैम्बर थे। चौधरी लहरी सिंह लोक सभा में जन संघ के टिकट पर जीत कर आए थे। जन संघ का राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय था कि महा पंजाब बनना चाहिए। चौधरी लहरी सिंह जी ने उसका समर्थन किया कि हरियाणा बनना चाहिए। जद जनसंघ के लोगों ने एतराज किया तो उन्होंने कहा कि “बारा तो टिबडा-टिबडा मेरे वे है और यह तेल और बत्ती

मेरी है। “चौधरी बंसी लाल ने उस पर डाइसैटिंग नोट दिया और उसके खिलाफ बोले। अध्यक्ष महोदय, ये पिछले से पिछले सेशन में आप से बोलकर गए थे कि मैं आपको रिकार्ड दिखाऊंगा। शायद आज ये रिकार्ड लेकर आए होंगे। अध्यक्ष महोदय इनका रिकार्ड तो पिछले अधिवेशन में जाहिर हो गया था। 107 गांव हरियाणा प्रदेश को न मिले, इसके बारे में तो फाईल हाउस में दिखाई गई थी, जिसपर इन्होंने दस्तखत करके दे दिए थे। 70 हजार एकड़ भूमि थी जिसमें पिटोरा पैदा हो गया। यह जो डेराबस्सी, लालडू और पटियाला की धरती है यह ले ले। जाए और 107 गांव दे दिए जाएं। यह तो फाईल को देखकर इन्होंने हाउस में माना है। इसी तरह से इन्होंने पार्लियामैंटरी कमेटी में कहा था कि हरियाणा नहीं बनना चाहिए। मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ क्योंकि ये हरियाणा बनाने के हक में ही नहीं थे, हरियाणा के हितैषी ही नहीं हैं, इसीलिए ये हरियाणा की डूबने का काम करते रहे हैं। एस० वाई० एल० नहर का आपको स्वयं पता होगा कि कैथल और कुरुक्षेत्र जिले तह बनी हुई थी। पंजाब के लोगों ने, जहां तक यह बनी हुई थी, चहा से बासा करके आगे तक ले गए और वह अब भी भरी हुई है और बह रहे हैं। उसमें पंजाब का सारा पानी आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1993 में जो 120 कि० मी० के। बात हुई थी, ये यहां पर अब अपनी बात से मुनकर हो रहे हैं।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लनेशन पर बोलना चाहता हूँ। पहले तो इन्हे यह पता नहीं कि एस० वाई० एल० 120 कि० मी० लम्बी नहीं है यह 93 कि० मी० है। दुसरी बात जो इन्होंने रि—आरगेनाईजेशन आफ पंजाब स्टेट की 'कही है, इस बारे में इन्होंने कहा कि मैं रिकार्ड लाऊंगा। अध्यक्ष महोदय आप अगले स्पीकर को बोलने के लिए खड़ा कर दें। मैं एक घंटे में वह रिकार्ड सदन में प्रस्तुत कर देता है और ये इस बात के लिए माफी मांगेंगे। मैं यहां पर खड़ा होकर बताऊंगा कि मेरा नोट क्या है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात बोल दूंगा। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी के लीडर हैं और चौधरी बंसी लाल जी भी नेता हैं। ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि वह झूठ मोल रहा है और एक दूसरे पर कमीशन खाने का आरोप लगा रहे हैं। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात को मान लें क्योंकि ये दोनों सच ही कह रहे हैं।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्रीमती चंद्रावती (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का —समय दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। यह जो बाद आई है, कुछ तो यह प्राकृतिक है और बाद आने में कुछ प्रशासन की भी कमियां थीं। दादरी के इतिहास में पहली बार

ऐसी बाढ आई है। सबसे पहले 11 अगस्त को बरसात हुई। दादरी में फुआरा चौक है उसमें 2-2 फुट पानी खड़ा हो गया। यह बात मैंने डी० सी० के नोटिस में लायी ओर ग्रीवेसिज कमेटी के नोटिस में भी लाई लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जब 1 तारीख को वह। पर पानी आने लगा, मैंने तब से ही कहना शुरू कर दिया था कि दादरी में बाढ आएगी। उसकी वजह क्या थी, वह भी मैं आपको बता देती हूँ। अग्रेजों के वक्त की दादरी में बड़ी रेलवे लाईन थी, उस पर बारह पुलिया थी और अब तीन ही रह गई थी जो अटीं पड़ी थीं वे तब खोली गई जब शहर डूब गया। (इस समय श्री उपाध्यक्ष, पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, क् यह बताना चाहती हू कि अचील, जयश्री और झींझर गांव आठ तारीख को डूबे हैं। मैं यह कहना चाहती हू कि वहां पर जैनरेटर लगाने चाहिं क्योकि आमतौर पर बिजली फ़ैल हो जाती है लेकिन वहां पर जैनरेटर नहीं लगाए गए। औफिसरों के भरों में तो फटाफट जैनरेटर लग गए। 14 तारीख के बाद पानी निकालने के लिए कुछ जैनरेटर आए हैं लेकिन आज भी जितना पानी निकलता है, उतना ही और आ जाता है। अगर देखा जाए तो लोहारू कैनल सूखी पड़ी है। डिप्टी स्पीकर, जे० एल० एन० नहर सूखी पड़ी है। डिप्टी स्पीकर साहब, जिसने भी जहां चाहा वहीं पर नहर काट दी, कोई रोक टोक ही नहीं है। वैसे चीफ इंजीनियर ने उन लोगों के खिलाफ ऐक्शन भी लिया है। मैं दो ऐक्सियन के बारे में बार-बार कहती रही हूँ कि जब लोगों को उनकी ज्यादा जरूरत थी, तब वे दोनों छिप गए। जब उनके घरों में पानी आ गया तो

वे सबसे पहले भाग गए, और तो और मेरे पड़ोस में डी० एस० पी० रहते हैं, उन्होंने भी पानी रोकने की कोशिश नहीं की और च भी रहने के लिए रैस्ट हाऊस में चले गए। मेरे घर के बगीचे में आज भी पानी खड़ा है, मुझे नहीं पता कि यह पानी वहां पर किस वजह से खड़ा है लेकिन पानी वहां अब भी खड़ा है। मैं तो वहां पर थी, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक औरत जा—रही थी, उसके एक हाथ में चप्पल थी और दूसरे हाथ में उसने लाठी ले रखी थी। उस औरत के सिर पर गठड़ी थी और उस के आगे—आगे भैस आर कटड़ा था। इसी तरह से एक और आदमी रास्ते में जा रहा था, उसके सिर पर भी एक गठड़ी थी एवं गोद में एक बच्चा था। जब उसको पानी ने धकेल कर नीचे गिरा दिया तो एक दस या बारह साल के लड़के ने उस आदमी को उठाया। लेकिन औफिसरों ने कुछ न ही किया, वे धरों में बैठे रहे। यह ठीक है कि कुछ औफिसर अच्छे भी थे। उपाध्यक्ष महोदय, पानी को रोकने के लिए बांध बाधना चाहिए था लेकिन वह क्यों नहीं बांधा गया। मैंने स्वयं चीफ सैक्रट्रेरी को टैलीफोन किया, मुख्य मन्त्री को टैलीफोन किया तथा जो भी मैं कर सकती थी वह मैंने किया। मैं दिसौदिया साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने वहां पर खाने पीने का सामान भिजवाया। इससे पहले तो वहां पर 20 रुपये किलो चीनी बिकी है, आलू भी बहुत महंगे बिके हैं। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने बाढ़ से धिरे हुए लोगों की मदद की है। दादरी के छोरे तो बहुत निकम्मे माने जाते हैं लेकिन उन्होंने भी घर—घर घूमकर पानी भिजवाया। मेरे अपने

भतीजे ने भी लोगों को घर-घर में पानी पहुंचाया। सरकार ने तो बाद में पानी भेजा है लेकिन हस बार गांव के लोगों ने बड़ी भारी मदद करो है। डिप्टी स्पीकर साहब, आदमी अपने पशु तब कहीं पर ले जाता है जब उसके पास उनको खिलाने के लिए चारा नहीं होता। मेरे हल्के तक के गांवों के लोगों ने यानी मिश्री, छपाड़, इटैला, बसराना, गलावांस आदि गांवों के लोगों ने उनको चारा दिया, खाने को खाना दिया और को अपने वहां ठहराया जिस आदमी का पशु मर जाएगा वह क्या करेगा पशुओं से ही लोग दूध पीते है। ये चीजे तो स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखी हैं जिनको देखकर आंखों से पानी नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? अगर समय पर नहरों की छंटाई हुई होती, अगर रेल की पुलियों में गंदगी नहीं होती, मिट्टी नहीं होती तो यह बाढ़ शायद न आती। जिन रेलवे वालों ने यह लाईनें बनायी है हमारी सरकार को उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने इन लाईनों में पानी निकलने के लिए पुलियां क्यों नहीं बनायी। पहले वहां पर 12 या 13 पुलियां थी लेकिन अब एक भी नहीं है। 3-4 पुलिया अटी पडी थीं। इस तरह की जो बात हुई है उसे मैं बता रही हूं। पानी एक तरफ से निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहा है, धिगाड़े की 22 में से 11 मोटरें लिफ्ट इरीगेशन की चली लेकिन अटेने की नहीं चली, पानी वापस आ गया। जो इनका लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम है उसके बारे में तो मैं आए बार हाउस में कहती हूं कि लिफ्ट खराब है, उनकी मशीनरी खराब है जो आज से बहुत साल पहले लगी थी। उनके पम्प काम नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आफिसर्ज फील्ड

में हैं, इनका फर्ज है कि खबर दें मगर नहीं दी जाती। वहां जनरेटर लगने चाहिए थे पर नहीं दिए। छोटे दुकानदारों की दुकान पर पानी आ गया, खोखे बह गए। ज्यादातर पानी नहर काटने से आया और नहरों में आगे नहीं जा सका। ड्रेन न० 8 की कमी सफाई नहीं हुई। किस तरह से यह पानी आया लोग कहने लगे कि घासोला में नहर काट ली, बाकरा के पास काट ली तो पानी आ गया, आज भी आ रहा है। झिंझर गांव हे, अचीणा है रानीला है इनमें अब भी पानी खड़ा है। किसी ऐक्सपर्ट को ले जाकर उसे दिखाकर ठीक से पानी जवाहर लाल नहर और लोहारू नहर में डलवाने की कोशिश करें, नहीं तो खेतों में पानी खड़ा रहेगा। यह फसल तो खराब होगी ही, आगे भी नहीं वो सकेंगे यह सारा काम इसी तरह से चला तो 15 अक्तूबर तक पानी नहीं निकलेगा। सब जगह नहरें कटी पड़ी है, कब तक आप उनको ठीक कराएंगे। इसलिए अब जरूरी है कि नक्शे लेकर जहाँ पानी का बहाव है वहां तालाब बनवाये। मैं हमेशा तालाबों पर जोर देती हूँ ताकि बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। मुख्य मन्त्री जी भिवानी आए थे तो उन्हें भी मैंने यदी सुझाव दिया था कि बरसात का पानी इकट्ठा होना चाहिए। जौहड़ों की जमीन पर योगों ने नाजायज कब्जे कर लिए हैं। दादरी का अस्पताल आए बार डूबता है। उसके पास खाई थी, वह मिट्टी से अट गई और लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए। शहर नहीं डूबा। क्योंकि शहर में एक जौहड है उसमें सारा पानी चला जाता है। कुदरत की प्लानिंग को आप कैसे रोक सकते है? अलवर के डी० सी० ने रिवाडी के डी०

सी० को टैलिफोन किया और बताया कि दो घंटे में पानी आपके पास पहुंच जाएगा और पानी इतनी तेजी से आया कि मकान के मकान बहा कर ले गया। कुछ करने की कोशिश नहीं कर सके। रिवाड़ी के औफिसरों ने कहा कि पानी हमने दो घंटे में निकाल दिया क्योंकि पानी अपनी ताकत से आया था और अपनी ही ताकत से बाहर चला गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। सर्दी आ रही है, हर देश में सर्दी बड़े दिन से शुरू हो जाती है। अरब देशों में जब सर्दी आती है तो सर्दी की चीजें सस्ती की जाती हैं। हमारे यहां जन्माष्टमी से अगले दिन गुग्गा होता है। गुग्गा के दिन से जाड़ा जन्म लेता है और दिवाली के दिन जाड़ा धु धरू बांध लेता है। मैं चाहूंगी कि बाद पीड़ित इलाकों में गर्म कपड़े व सर्दी की चीजें सस्ते रेट पर देनी चाहिए। मुझ से पूर्व बोलने वाले वक्ता बहुत से सुझाव दे चुके हैं, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहती। सड़क की बात आई है। 12 तारीख को मुख्यमंत्री जा हिसार गए थे, उनके नोटिस में भी लाया था, काफी सारे आफिसर थे, कि सारी सड़कें टूट चुकी हैं। जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। बसे, कारें टूटी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ बातें बाढ़ के नाम थोप दी जाएंगी, पर एक्चुअइली वे सड़कें घटिया मैटिरियल व बिचुमन न लगने के कारण टूटी हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यहां पर यह कहा गया कि पक्की नहरों से सीपेज नहीं

होती, यह गलत बात है। मैं कहती हूँकि पक्की नहरों से भी सीपेज होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पक्की नहरों से भी सीपेज होनी है तो फिर उनको पक्का करने में क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जाता है। कच्ची नहरें ही रहने देनी चाहियें क्यों कि एक तो कच्ची नहरें बहुत कम टूटती हैं क्योंकि उनमें रेत बहुत होता है और वह रेत साथ-साथ चलता है। कच्ची नहरें ही रखे ताकि सरकार का खर्चा कम हो। जो नहरें टूट चुकी हैं, उनको सरकार ठीक करवाने की कोशिश करे। इसके साथ-साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उन लोगोंको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस बाढ़ की 'स्थिति में एक दूसरे की जमकर मदद की है। जिन लोगों के मकान गिर गए हैं, मकानों में पानी भरा पड़ा है और किसी की भैंस मर गई है, किसी का दूसरा कोई पशु गाय वगैरह मर गई है, उनको सरकार की ओर से अवश्य व जल्दी मदद मिलनी चाहिये। जहां तक दवाईयों का सम्बन्ध है, दादरी में क्लोरिन तो बटी है और दूसरी दवाईयां भी शायद पहुंच रही हैं, इसके लियेमें स्वास्थ्य मन्त्री महोदया को धन्यवाद देती हूँ।

अब मैं सीवरेज के बारे में कहूँगी कि सीवरेज का भी बहुत पूरा हाल है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में, मैंने एक मछली तैरती देखी और वह मछली बाहर के गन्दे सीवरेज के या फिर नहर के पानी से ही अम्बेर आई होगी। इसलिये में यह भी सरकार से कहूँगी कि जो प्रशासन की कमजोरियां हैं, उनको

अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिन अधिकारियों ने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभाया है, उनको अवश्य सजा मिलनी चाहिये, चाहे कोई भी हो, उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी चाहिये। अगर प्रशासन पूरी तरह से तैयार होता, सजग होता तो जो मुसीबतें बाढ़ के कारण लोगों को उठानी पड़ी, उनको टाला जा सकता था। इन शब्दों के साथ डिप्टी सीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी (बेरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप ने अपनी नजरें हमारी तरफ भी की हैं और मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अन्दर इस बार अभूतपूर्व बाबू का प्रकोप रहा जिस के कारण सैकड़ों लोगों की जानें गईं। कम्प हजार पशु मारे गये, 28 लाख एकड़ जमीन में बड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। इस तरह से 35 लाख के करीब लोग हरियाणा के अन्दर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों को तरह-तरह की यातनाएं सहनी पड़ीं। लगभग 1500 करोड़ रुपये का नुकसान बाढ़ के कारण हुआ है जिसमें पशुधन भी शामिल है। इतना ही नहीं, दुकानदारों का भी सटा भारी नुकसान हुआ है। तर्क टूट गई हैं, लोगों के घरों में, दुकानों में बुरी तरह से पानी भरा रहा जिस कारण जान माल का बहुत नुकसान हुआ या जसकी पूर्ति शायद कभी नहीं हो सकती। किसानों के कीमती पशु मारे गये, पावर हाउसिज में भी पानी भरा

रहा। हफ्तों तक नहीं बल्कि महीनों तक पानी भरा रहा और बगैर बिजली के लोगों को गुजारा करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार लोगों की हर प्रकार से जल्दी से जल्दी मदद करे और किसानों को राहत मुहैया करे ताकि किसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस सारे नुकसान के लिये प्रकृति को दोषी ठहराती है जबकि सारा कसूर इस सरकार का रहा है। प्रकृति का काम बरसात करना है और सरकार का काम है बरसात से बचाव करना लेकिन सरकार ने पहले से ही इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आज प्रदेश की यह दुर्दशा हुई। इस बात को आप सब भली भांति जानते हैं। समय पर सरकार को बाढ़ का मुकाबला करना चाहिये था लेकिन सरकार उस समय बिल्कुल सोई रही। और प्रदेश की जनता को बाढ़ से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाय। नहरों और ड्रेनो की सफाई नहीं करवाई गई। केवल कागजों में सफाई दिखा कर अधिकारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए के गबन का काम किया है। न तो मोटरों और पम्पों की रिपेयर करवाएं गईं और न ही इस बात को महसूस किया गया। यह भी नहीं सोचा गया कि हमारे पास बहुत थोड़ी इलैक्ट्रिक मोटरें हैं। मैं यह इलजाम लगाना चाहूंगा कि अधिकारियों ने मोटरों की रिपेयर के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया है। इसलिए बाढ़ से जो हानि हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ड्रेन नं० 8, सब ड्रेनज आवि लोहारू फीडर, लोहारू कैनल और जे०एल०एन० कैनल की सफाई करवा दी

जाती तथा विभिन्न क्रिटिकल प्वायन्टस पर बरसात से पहले ही पम्पस लगवा दिये जाते तो बाढ़ के पानी से बहुत जल्दी राहत मिल सकती थी। इनकी रख रखाव के०पर पैसा खर्च किया जाता और नहरों की सफाई करवा दी जाती, पुरानी मोटरों की रिपेयर करवा दी जाती और नई मोटरें खरीद ली जातीं तथा क्रिटिकल प्वायंट्स पर बिजली की मोटरें लगा दी जाती तो बाढ़ का पानी एक हफ्ते के अन्दर निकाला जा सकता था लेकिन सरकार सोती रही और अधिकारी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खाते रहे। ऐसी हालत सरकार ने इस प्रदेश के अन्दर की है। बाढ़ आने के बाद किसी भी गांव में कोई अधिकारी तो क्या, एक छोटे से छोटा कर्मचारी भी नहीं गया कि वहां पर लोगों की क्या हालत है। मैं बताना चाहता हूं कि झज्जर में एस०डी०एम० के पर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर गांव खेडी कुमार है वहां पर एस०डी०एम० को पहुंचने में एक सप्ताह से अधिक समय लगा। अच्छेज के पहाड़ीपुर गांव पहले ही जे०एल०ऐन० की सी पेज से बर्बाद हो चुके थे और सरकार के निकम्मेपन की वजह से अब वे परमानैट तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। पहले वहां सरकार की तरफ से मोटरे लगाई हुई थीं लेकिन बरसात आने से पहले उनको वहां से हटा लिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 41 गांव हैं, जिनमें से 34 गांव आज पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। विशेष रूप से मैं उन गांवों के नाम लेना चाहूंगा जहां शत-प्रतिशत फसलें बर्बाद हो गईं तथा हजारों मकान बाढ़ के कारण गिर गये। उनके नाम हैं— डीघल, दुजाना, गांगटान, जहाजगढ़ मोहमदपुर

माजरा, अच्छेज, पहाड़ी पुर, वाघपुर, बेरी, मांगा वास, पलड़ा, खेड़ी खुमार, खातीवास बिसाहन, ढराणा, चिमनी, सिवाना, शेरिया, धान्ध लान, वरहाना दिमाना छोछी, गोछी, भम्भेवा, मदाना कलां, मदाना खुर्द, दुबलधन बस्ती भगल पुरी, महराना, घोड, चिमनपुरा बाकरा, वजीरपुर, गुढा ये गांव पूरी तरह से बाके से प्रभावित हैं। इन सभी गांवों की शत प्रतिशत फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, हजारों मकान गिर चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक न तो इनकी स्पेशल गिरदावरी करवाई गई है और न ही गिरे हुए मकानों का सर्वे करवाया गया है। कई गांवों में तो 80 परसेंट लोग गांव छोड़ कर बाहर जा चुके हैं। यह कितना बड़ा मजाक वहां के लोगों के साथ है। अब भी कई गांवों की बस्तियों में पानी खडा है टी०वी० के जरिए, रेडियो के जरिए और समाचार पत्रों के जरिए सरकार एलान कर रही है कि हमने इस बार बाढ़ राहत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया है। अगर मौके पर जाकर देखा जाए तो प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ काम बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का किया है वह स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया है। मैं उन स्वयंसेवी संस्थाओं का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना तक पहुंचाया। स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों ने डाक्टरों की टीम ले जा कर लोगों को दवाईयां दिलवाई। मैं स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की बहुत सहायता की। उपाध्यक्ष महोदय, डीगल गांव के लोगों ने तनि किलोमीटर लम्बा नाला खोदा। ऐसा करके उस गांव वालों ने एक भाईचारे का सबूत दिया है। उन्होंने तीन

किलो- मीटर लम्बा नाला खोदा ताकि बाढ़ का पानी निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के कारण डी गल गांव के लोगों का आने जाने का रास्ता नहीं रहा, जिसके कारण उस गांव के लोग फारिग होने के लिए ट्रैक्टरों में बैठ कर हजारों की तादाद में रोहतक जाने वाली सड़क पर आते थे। इस तरह से लोगो को मरने के लिए मजबूर कर दिया। 2 तारीख को जो तूफान आया था, उसके कारण हजारों की तादाद में दरख त टूट गए थे जिसके कारण रास्ते रुक गए। फारेस्ट डिपार्टमेंट और पी० डब्ल्यू० डी० वालों ने उन दरखतों को सड़कों से हटाना जरूरी नहीं समझा। गांवों के लोगों ने अपने आप उन दरखतों को हटाने का काम किया है इसमें सरकार का किसी किस्म का योगदान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के के 34 गांवों मे गया। एक दो गांवों को छोड़कर सब लोगो ने कहा कि आप पहले आदमी हैं जो गांवों में आए। लेकिन सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया। इस किस्म के हालात थे। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के कारण तीन-चार हजार करोड़ रुपए का हरियाणा प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है। लोगों के मकान गिरने से, लोगों 'की फसले' बरबाद होने से, दुकानदारों का सारा सामान खराब होने की वजह से, सड़कें और नहरें टूटने की वजह से तीन चार हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है लेकिन यह सरकार केवल 600 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से मांग रही है। मैं तो यह कहूंगा कि कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार से मांगने चाहिए थे ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके और

अच्छी तरह से दूसरी राहते दी जा सके। मैं तो यह कहता हूँ कि 600 करोड़ रुपया तो अधिकारियों की जेबें भरने के लिए भी काफी नहीं होगा। हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का पानी खड़ा न हो, इसके बारे में मैं एक सुझाव दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम जब भी गांवों में बिजली की मोटरें लगाने के लिए अधिकारियों से कहते हैं तो उनका जवाब होता है कि हमारे पास मोटरें नहीं हैं पानी कैसे निकालें। मैं कहता हूँ कि जो राहत का पैसा आया है, इसमें से इलैक्ट्रिक मोटरें खरीद कर हर गांवों के खेतों से पानी निकाला जा सकता है। रबी की फसलों की बिजाई हो सकती है, यदि इलैक्ट्रिक मोटरें लगा दी जाएं। इस बारे में युद्ध स्तर पर इन्तजाम किया जाए। इलैक्ट्रिक मोटरों के बगैर किसी गांव से पानी नहीं निकाला जा सकेगा। बाढ़ आने के 15 दिन बाद तक भी सरकार की तरफ से डाक्टरों की टीम दवाई देने के लिए गांवों में नहीं भेजी गई। सारा काम स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया। अब तो रास्ते खुल गए हैं इसलिए सरकार को हर गांव में डाक्टरों को भेजना चाहिए ताकि गांवों में कोई बीमारी न फैले। गांवों में दवाइयों का छिड़काव करवाया जाना चाहिए ताकि लोगों को मच्छरों से छुटकारा मिल सके। जिन-जिन गांवों में किस्तियों की जरूरत है उन गांवों में किस्तिया मुहैया कराई जाएं। सड़कों की सफाई कराई जानी चाहिए ताकि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो। सिरकियों का जिक्र आया। लोगों को सिरकियां भी कंजूसी के साथ दी गई। कई जगह तो पंचायतों से कह दिया कि सिरकियां अपने फण्डज से खरीदे। सरकार ने लोगों को किसी भी

किस्म की राहत नहीं दी। लोगों को गन्नी बैगज भी सरकार की तरफ से नहीं दिए गए। लोगो ने अपने घरों से बोरियां और कट्टे ले कर मिट्टी से भर-भर कर पानी को रोकने के प्रयास किए। इस तरह से लोगों ने अपने गांवों को बाढ़ के पानी से बचाया। अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन गांवों में रिंग बांध बनाना जरूरी है, मैंने उनके बारे में पिछले सेशन में भी कहा था और इस सरकार के औफिसर्ज से भी कहा था कि फलां-फलां गांवों में रिंग बांध बनाने, की जरूरत हूं लेकिन आज तक उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो रिंग बांध बने हुए थे, उनकी देखभाल नहीं हुई और न ही नए बनाए गए। इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि अगले साल बरसात के मोसम से पहले, जहां-जहां पर रिंग बांध बनाये जाने की आवश्यकता है, वहां पर बना दिए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ड्रेन नं० 8 और जे० एल० एन० के जरिए हमारे एरिया का पानी निकाला जा सकता है। ड्रेन नं० 8 की जो हालत थी, वह मैं बताना चाहता हूं। वहां पर टी० बी० की एक टीम गई थी 1 उस टीम ने देखा था कि वह किनारों तक चल रही थी और उसमें सैकड़ों दरखत पड़े थे, जिनकी वजह से उसको बराबर टूटने का खतरा बना हुआ था। लोहारु फीडर की कैपेस्टी भी घट कर केवल 20 प्रतिशत रह गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार हाउस की सभी पार्टियों के मैम्बरो की एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी के टर्मज आफ रैफेंसिज ये हों कि बाढ़ आने के लिए जिम्मेदार कौन हैं। जो अधिकारी और सरकार दोषी

हो, उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमे दब करा कर कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में लोगों के साथ इस प्रकार का खिलवाड कोई न कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार एक हैक्टेयर की फसल का मुआवजा 1000 रुपये देने की बात कह रही है जो बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि बड़ी मेहनत से किसान अपनी फसल बोता है और ०पर से जब नुकसान हो जाए तो एक हजार रुपया तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको कम से कम 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिनके पक्के मकान गिरे हैं, उनको 50,000 रुपये और जिनके कच्चे मकान गिरे हैं उनको कम से कम 25,000 रुपये सरकार को देने चाहिए। इसी प्रकार जिन लोगों के पशु मारे गए हैं, उन सभी की कीमत का आकलन कर के पंजाब पैट्रन पर पैसे मिलने चाहिए। जिन लोगों के ट्यूबवैल्ज खराब हो गए हैं, उनको 25 हजार रुपया मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वे ट्यूबवैल लगा कर आने वाली— फसल की सिंचाई कर सके। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को भी सरकार को दो-दो लाख रुपया देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा सुझाव यह है कि अगली फसल यानी रबी की फसल की बिजाई हो सके, इसके लिए हर गांव में बिजली की मोटरे लगा कर पानी निकाला जाये और दूसरे गांव के किसानों को खाद और बीज पर सबसिडी दी जाये। जहां पर सड़कें खराब हो गईं, वहां पर तुरंत मुरम्मत की आवश्यकता है। इन्हीं सब सुझावों के साथ मैं

उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन सुझावों पर विशेष गौर करके लोगों को राहत देगी, केवल घोषणा नहीं करेगी। अब मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। (शोर)

श्री सूरजभान काजल: मेरे हल्के में अब भी हालत बहुत खराब है। मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बाढ़ का पानी अब भी बढ़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको भी जरूर बोलने देंगे, लेकिन अब आप बैठ जाइए। अब श्री वीरेन्द्र सिंह जी बोलेगे। (विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्यांयट ऑफ आर्डर है। ये मन्त्री तो हैं, इनका कही नाम नहीं है। (विधन) इनका नाम नहीं आया है। ये मिनिस्टर हैं और ये तो रिप्लाइ देंगे। (विधन एवं शोर) मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। रूल 84 में जिन मैम्बर्ज के नामों का प्रस्ताव है उनको बोलने का राईट है। क्या मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? प्रस्ताव पर जिनके साईन हूँ, केवल वही पहले बोल सकते हैं। (विधन)

श्री उपाध्यक्ष: बी० ए० सी० की मीटिंग जब हुई थी तो आप भी उसमें मौजूद थे। इस बारे में काफी तफसील से बातचीत हुई थी। आखिर में यह फैसला हुआ था कि फलड के मामले में अनप्रैसिडेंटिड सिचुएशन जो पैदा हुई है, उस बारे में सभी मैम्बर्ज अपनी अपनी बात कह सकेंगे, उसी फैसले के तहत ये बोल रहे हैं। (विधन एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: जिन सदस्यों ने मोशनज दिए हैं, उनको क्लब करवाएं। डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी कौन जी मोशन है? इनका मोशन है ही नहीं, इसलिए इनके बोलने की बात कहां से आ गई? (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, अण्डर रूल 84 के तहत सभी मोशनज क्लब किए जाएं, जिनके नोटिस होंगे उनको बोलने का मौका दिया जाए। इनकी तरफ से कोई नोटिस ही नहीं है। कांग्रेस के एम० एल० एज० चाहे तो वो बोल सकते हैं लेकिन कांग्रेस के किसी भी एम० एल० ए० ने नोटिस नहीं दिया है। (विधन एवं शोर)

डा० राम प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, फसलें और मकान तो बाद में बह गए हैं, क्या कायदे और कानून भी बहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, जिन मैम्बर्ज ने कालिंग अटैंशन मोशन दिए हैं, पहले उनको बोलने दीजिए। इस बारे में इस स्टेज पर मन्त्री जी क्या कहना चाहेगे? यह बाढ़ का मामला है। इनके जो एम० एल० एज० हैं, वे अगर कुछ कहना चाहें तो कहे, इन्होंने तो जवाब देना है। अभी तो जवाब देने की बात नहीं है। ये इस स्टेज पर किस बात का जवाब देंगे? कहां-कहां फ्लड आया, उससे कहां-कहां क्या नुकसान हुआ, जब मैम्बर्ज अपनी बात कह लेंगे उसके बाद मन्त्रीगण अपने-अपने विभागों का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमने क्या-क्या कदम उठाए हैं। हम लोगों की अपनी-अपनी बात कह लेने के बाद ही मन्त्री बोल सकते हैं लेकिन जब तक हमने

अपनी बात नहीं कही, ये किस बात का जवाब देंगे? (विघ्न एवं शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के की बात तो कह सकता हूँ। (विघ्न एवं शोर)

I am not replying to the debate but I can very-very well say something about my constituency, Sir. (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker : Yes, he has a right to speak.

Ch. Birender Singh : Sir, my point of order is .(Noise & Interruptions.).

Mr. Deputy Speaker : Ch. Birender Singh, you u kindly see the rule.

Rule 84 says that —

A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly, but the Assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour, unless a Member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and on such motion the vote of the Assembly shall be take It means every member has a right to speak on this motion

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें हर मैम्बर को बोलने का राईट कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने जो पढ़ा है उसमें हर मैम्बर का नहीं लिखा हुआ है। जिन मैम्बर्ज ने मोशन दी है उस पर वे ही बोल सकते हैं और अगर दूसरे मैम्बर भी बोलना चाहते हैं तो अब मोशन दे दे।

Mr. Deputy Speaker : In rule 84, Assembly means all the 90 mebmbers and all can speak.

प्रो० सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव को तो रूल 84 के तहत कनवर्ट किया गया है।

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, आप भी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में मौजूद थे। रूल 84 के तहत सबको बोलने का हक है, सभी मैम्बर्ज चाहे वे कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टीज के हैं, वे सब बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने उसमें यह भी कहा था कि सभी मैम्बर्ज इस पर बोलेगे।

चौधरी भजन लाल: जी हां।

Ch. Birender Singh : You have rightly said that unless it is moved by the mover or the speech is completed by the mover. This is what we are saying that there are 27 members who have moved the motion and everybody should speak and after that the leader of the House should make a

reply. It is very clear .

Mr. Deputy Speaker . Mover means, who has moved the motion Ch. Birender Singh . No, Sir, it is not that.

Mr. Deputy Speaker : I have already given my ruling.

Ch Birender Singh : Mover means, whoselver has moved the resolution The resolution has been moved by 27 members. Until and unless every member speaks, it is not completed.

Deputy. Speaker : This may be your interpretation. (Interruptions).

श्री जगदीश नेहरा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। आपने जैसे रूल 84 के बारे में पढ कर भी सुनाया और ये भी उसे ठीक ढंग से परे। उससे यह कलीयर है कि ' ए मूवर ' का मतलब है एक मूवर बल्कि यह नही कि 26 मूवर। यह मोशन 26 मैम्बर्ज ने मूव की है। (विधन) ओमप्रकाश मुवर हैं और आपको नोटिस भी मिला होगा, उसमें एक मैम्बर ही मूवर है। जो दूसरे मैम्बर्ज है उनके सिर्फ सिग्नेचर ही होंगे तो obviously by this one if you read it again, it is clear. In rule 84, it is mentioned.

But the Assembly shall proceed to discuss such matters immediately after the mover has concluded his speech."

Here the mover means only one fellow, who is Ch. Om Parkash Chautala. You have given notice that tomorrow

discussion will be started. The discussion will continue for tomorrow also . Only mover is Ch. Om Parkash Chautala and you are the signatories only. उसमें एक ही मूवर है और जो सिग्नेटरी है, आपने उनके नाम भी दिए हैं। जो सिग्नेटरी हें वे मूवर नहीं हो सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० राम प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप बैठ जाएं। मैं अपनी रूलिंग पहले ही दे चुका हूँ। **प्रो० सम्पत सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा आपसे सबमीशन है कि मूवर का मतलब यह है कि एक मੈबर भी इसको मूव कर सकता है और एक से फालतू अगर मून करना चाहें तो वे भी मूव कर सकते हैं। कई मोशनज में संख्या निर्धारित नहीं होती है कि इतने मैम्बर होने चाहिए। अन्डर रूल 84 के तहत एक मैम्बर भी मोशन मूव कर सकता है और अलग-अलग मैम्बर अलग-अलग मोशन भी दे सकते हैं।

श्री जगदीश नेहरा: लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है।

Prof Sampat Singh : No, here the mover means, even a single person can also move and more than one person can also move.

श्री जगदीश नेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसा नहीं है। आपने नोटिस दिया है कि कल बाढ पर डिस्कशन होनी है। आपने जो नोटिस दिया है उसमें सारे कारण बताए हैं।

Prof. Sampat Singh : He is killing the time, Sir.

Shri Jagdish Nehra : You are killing the time. You are not serious at all. It is a natural calamity. It is not only their right. We are also sufferer, Sir. They only want to gain politically out of it. (Noise & Interruptions).

Prof. Ram Bilas Sharma : Deputy Speaker, Sir, I seek your observation. (Noise & Interruptions) ये बाढ़ की गम्भीरता को कम करना चाहते हैं।

Mr. Deputy Speaker : Ram Bilas Ji, I have made out your point.

Prof. Ram Bilas Sharma : Sir, it is a document, which has been circulated by your office and signed by 27 M.L.As. (Noise & Interruptions). Please listen to me. (Noise & Interruptions) Mr. Deputy Speaker, it is a document which has been circulated by your office and signed by 27 M.L.As. They have given adjournment motion, they have given call attention motion and they have given motion under Rule 84 also. All have been converted into motion under rule 84. Please have it considered.

Mr. Deputy Speaker : The discussion that is going on is under Rule 84. It is not adjournment motion that is being considered.

चौधरी बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है। मैं आपसे एक रूलिंग चाहता हूँ कि रूल 84 के अंडर जो मोशन का नोटिस है, इसमें एक नं० पर श्री ओमप्रकाश चौटाला

का नाम लिखा है और नं० 27 पर बहिन चन्द्रावती का नाम लिखा है। इस एक नं० की और 27 नं० की हैसियत या स्टेटस को क्या आप अलग-अलग समझते हैं?

What is the difference in number 1 and 27, because all the 27 members have given notice under rule 84. How do you discriminate one against another ?

श्री जगदीश नेहरा: सर, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। आपने जो रूल 84 के अंडर कल के लिए बाढ़ पर डिस्क शन के लिए नोटिस दिया है, उसमें कलीयरकट लिखा है। (व्यवधान) सर, शायद आपने यह बात सुनी नहीं है कि रूल 84 के तहत एक आदमी मूव करता है और बाकी साईन करते हैं। आपके सैक्रेट्रिएट से जो कल के लिए नोटिस आया है वह मैं पढ़कर सुना देता हू। इसमें कलीयर लिखा हुआ है कि—

"Resumption discussion on the following motion moved by Shri Om Prakash, M.L.A. on the 26th September, 1995, namely :-

"That the serious situation that has arisen on account of recent floods in the State and the substantial damage caused by it, be discussed."

Obviously your Secretariat is considering only one person, who is mover and you have mentioned his name. You have mentioned 27 names but for tomorrow it is only 21 members, who are also signatories and not they are the mover.

प्रो० सम्पत सिंह: लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब के, सैक्रेट्रिएट के भी तो कोई रूल्ज होंगे।

Mr. Deputy Speaker : I have already given my ruling. Please take your seat.

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप ट्रेजरी बैचिज के मैम्बर्ज से भी इस बार साइन करवा लें। (शोर एवं व्यवधान) ट्रेजरी बैचिज की भी आप एक ऐप्लीकेशनले लें।

Mr. Deputy Speaker : He has not been debarred to take part in discussion.

श्री सतबीर सिंह कादयान: डिप्टी स्पीकर सर, नेहरा साहब इसकी इन्टरप्रिटेशन अपने ढग से कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कादयान साहब, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयान: डिप्टी स्पीकर सर, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता, फिर भी आप उसको टाइम दे दें, यह बात ठीक नहीं है। अगर सरकार यह समझती है कि वह बाढ़ को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है तो ये भी उस पर हस्ताक्षर कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : There is discussion on the floods situation in the Assembly i.e. the

whole Assembly and not only the Opposition Members. We are also part of the Aesembly. हम भी बाढ़ से उतने ही चिंतित हैं, हम अपनी बात कहेगे ।

Mr. Deputy Speaker : I have already given my ruling. There is nothing which debars him to speak.

प्रो० सम्पत सिंह: डिप्टी स्पीकर सर, सरकार जवाबदेह है । यह नयी परम्परा डाली जा रही है, कोई हैल्दी ट्रेडीशन डालनी चाहिए ।

Mr. Deputy Speaker : Sampat Singh Ji, please take your seat. He is also Member of the house. He has the right to speak.

प्रो० सम्पत सिंह: डिप्टी स्पीकर सर, हम आपकी रूलिंग में अमेंडमेंट चाह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: नियम-84 में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई हाउस का मैम्बर उसमें पार्टीसिपेट न कर सके ।

प्रो० सम्पत सिंह: सर, ये जवाब देंगे, ये तो मिनिस्टर हैं ।

Mr. Deputy Speaker : He is also a Member of the House first.

प्रो० सम्पत सिंह: कुलैक्टिव रिसपोसिबिलिटी है आप सब की ।

Mr Deputy Speaker : Sampat Singh ji, please take your seat now I have already given my ruling (Interruptions)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, यह तो समय ऐसा था कि हम बाढ में धिर गए और आप रूलिंग में धिर गए। हिसाब से कायदा तो यही है कि जो ऐडजर्नमेंट मोशन आए, उन पर जो दस्तखत करने वाले लोग हो, पहले उनको अवसर मिले और सरकारी बैचिज में बैठे हुए लोग उसका जवाब दें। श्री वीरेन्द्र सिंह जी बतौर विधायक अपने हल्के की बात कह सकते हैं लेकिन जब ये 27 लोग बोल लें, तब इनको मौका दीजिए। एक गलत परम्परा कायम करोगे तो और बखेड़े खड़े हो जाएंगे। आप फंस गए हैं तो इससे निकलने का रास्ता तो आपको निकालना ही पड़ेगा गैर—कानूनी बात या गलत तरीके अपनाओगे तो गलत रिवायत हो जाएगी। अगर मूव करने वाले 27 लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा, उसके बाद ही कांग्रेस बैचिज के मैम्बर बोलें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये दस्तखत कर दें, इन्हें ड्यू दे दो तभी ठीक रहेगा। पहले बोलने का अगर इन्हें चाव है तो बोल लें, वरना इस पर जवाब दे दें, स्पष्टीकरण दे दें। सरकार दोषी है। (विधन) सरकार की वजह से यह हुआ है, ये उसका स्पष्टीकरण देने वाले हैं।

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डिस्कशन हो रही है, वह इस मोशन की वजह से नहीं है यही वजह होती तो बहस एक दो घंटे होकर मामला समाप्त हो जाता। बाकायदा

बी०ए०सी० की मीटिंग में यह प्रोग्राम तय हुआ था, जिसमें अध्यक्ष महोदय आप भी मौजूद थे, लीडर आफ दी अपोजीशन भी थे और चौधरी बंसी लाल जी भी थे। इन सब ने वहां कहा था कि फ्लड से सम्बन्धित सभी मैम्बर्ज को बोलने का पूरा –पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। इसलिये इसके लिये दो दिनों का समय रखा जाए। (शोर) उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि लीडर आफ दी हाउस कभी भी कहीं भी इंटरवीन कर सकत। शौ और सरकार की ओर से कोई भी मंत्री इंटरवीन कर सकता है तो फिर ये श्री वीरेन्द्र सिंह जी को बो लने सै क्यों रोक रहे है? इनको किसी को टोकने का कोई अधिकार नहीं है। सारे हाउस के मैम्बर्ज को बोलने का पूरा-पूरा अधिकार है और इस पर आपकी रूलिंग भी आ गई है। ये लोग अब किस बिना पर आपकी रूलिंग को चौलेज कर रहे हैं। आग इनकी बातों पर गौर न करते हुए हाउस की कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे चलाए।

चौधरी बंसी लाल: मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि हाउस का हर माननीय सदस्य बोल सकता है लेकिन मैं एक बात की ओर इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिनिस्टर को तभी बोलना चाहिये जब अपोजीशन की ओर से कम से कम 10-15 मैम्बर्ज बोल चुके हों क्योंकि इसमें बिजली की बात भी आई है, दूसरी बातें भी आई हैं लेकिन मिनिस्टर महोदय को कम से कम 10- 15 मैम्बर्ज के बोलने के बाद ही बोलना चाहिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल: बे जवाब नहीं दे रहे हैं, वे तो अपने हल्के की बात कहना चाहते हैं।

चौधरी बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले हाउस में एक बात पर वो लते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि मैंने हरियाणा स्टेट बनने के खिलाफ डाइसैटिंग नोट लिखा था। इस बारे में पार्लियामैन्ट की एक कमेटी बनी थी, आन दी डिमांड फार दा पंजाबी सूबा और उसकी रिपोर्ट पार्लियामैन्ट में 18 मार्च, 1966 को पेश हुई थी। उस कमेटी में सरदार हुकम सिंह चेयरमैन थे। मनीराम गोदारा, चौ० ब्रह्म प्रकाश जी, श्री सुरेन्द्र सिंह, सरदार धन्ना सिंह, श्री हेमराज, हिजहाई नेस कर्ण सिंह जी, चौधरी लहरो सिंह, श्री सुरजीत सिंह मजीठिया, श्री मालवा य जी, श्री मुकर्जी, श्री साधु राम, श्री के० सी० पन्त, श्री बंसी लाल, श्री उत्तम सिंह और श्री वाजपेयी वगैरह उसमें मैम्बरज थे। जो मेरा डाइसैटिंग नोट था, मैं उसको पढ़कर सुना देता है—

"On principle I agree with the report except the shape of Haryana State. The people of Haryana have argued that they want to be separated from the Punjab region because of backwardness of Haryana and its economical and political exploitation by people of Punjabi speaking areas and the imposition of compulsory teaching of Punjabi in the Hindi region."

"In my opinion, if Haryana is amalgamated with old Delhi City. The Chances of Haryana people being exploited by

Delhi people are much more than even by the people of the present Punjabi speaking region as there are more advanced people living in old Delhi City."

मैं यहां एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि चौधरी बह्म प्रकाश चाहते थे कि रोहतक तक का इलाका करनाल तक का इलाका दिल्ली में मिलाया जाए और बाकी का हिस्सा राजस्थान में मिलाया जाए। आगे लिखा है—

"in my opinion, Delhi is a cosmopolitan city and its administration should always remain directly under the charge of the Central Government. I am of the definite view that the present Hindi region minus the hilly areas should be created a full fledged Haryana State so that the people of this backward area should have an opportunity to develop themselves. It is not within the competence of the Committee to tuck any adjoining State in any form. So the question of Haryana being attached to Delhi does not arise.

I would also like to point out that the use of Golden Temple' the Sacred place by Sant Fateh Singh and others for political purposes is highly objectionable. The Government may have to decide whether the use of Gurdwaras, Temples, Churches and Mosques should be allowed to continue for political purposes or not. In my opinion, politics should not be mixed with religion."

In my dissenting note, I have said that I am of the definite view that the present region minus the hilly areas should be created a full fledged Haryana State so the people of this backward area should have an opportunity to development

themselves.

18.00 बजे

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं के इस ब्यान के मुताबिक ये छोटे हरियाणा के पक्षधर रहे हैं। उसमें भी कमी रह गई तो ये हरियाणा के 107 गांव और देकर 70 हजार एकड़ जमीन लेने के दस्तखत कर आए। ये हरियाणा के पक्षधर कभी नहीं थे। इसलिए हरियाणा को बर्बाद करने में इनकी अहम भूमिका रही है। इन्होंने 107 गांवों के बदले 70 हजार एकड़ भूमि लेने के लिए भी दस्तखत किए और जो इन्होंने हरियाणा में एस० वाई० एल० बनाई उसने भी पंजाब का पानी आने से हरियाणा बर्बाद किया।

चौधरी बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा बना पै, तब से लेकर अब तक जो भी बाउंडरी का डिस्प्यूट है, मस पर डिस्कशन के लिए आप एक मोशन एडमिट कर ले। फिर माप देख लें कि किस ने क्या किया। फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी फाईलो में इन्होंने एडमिट किया है कि मेरे दस्तखत है। उस फाइल में है कि अबोहर और फाजिल्का के 107 गांव चले जाएं, हम उनके बदले 70 हजार एकड़ भूमि लेने के लिए तैयार हैं। यह इनके बतौर मुख्य मन्त्री के दस्तखत हैं। इन्होंने पिछले अधिवेशन में भी एडमिट किया था, आप मौके पर मौजूद थे। फाइल भी बता

रही है तो क्या इसके बावजूद भी कोई और बात दर किनार रह गई हैं? जब भी इनको कोई अवसर मिलता ई तौ ये हरियाणा को बर्बाद करने की बात करते हैं ।

चौधरी जगदीश नेहरा: सूर, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैटेगरीकली यह कहा था कि इन्होंने हरियाणा के बनने में विरोध किया । सामने खम्भे पर लिखा है कि “सभा में या तो प्रवेश न किया जहा, यदि प्रवेश किया जाए तो यहां स्पष्ट और ठीक बात कही जाए । क्योंकि यहा न बोलने से या गलत बोलने से दोनों स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है ।” तो पाप का भागीदार बनने में ये कम नहीं है । इन्होंने यह भी कहा था कि यदि यह बात सच न हो तो आगे इन्होंने डैश लगा लिया । हमने सोचा कि आगे डैश का मतलब यह होगा कि ये अस्तीफा दे देगे । इन्होने पहले 25 सितम्बर को अस्तीफे देने थे लेकिन नहीं दिए । अगर यह थोड़ा बहुत पाप का भागीदार बनने से बचना चाहते हैं या सच बोलना चाहते हैं तो इनको अस्तीफा दे देना चाहिए । चौधरी बंसी लाल ने क्लीयर कट बता दिया इसलिए बेहतर होगा कि आप अस्तीफा दे दें । इधर उधर चक्कर क्यों काट रहे हैं?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अस्तिफा देने का प्रश्न कहां से आ गया ? हरियाणा प्रदेश को छोटा बनाने की बात चौधरी बंसी लाल जी के अपने ब्यान में है । इन्होंने पंजाब को 107 गांव और देने का निर्णय लिया था । मैं कह रहा हूं कि चौधरी

बंसी लाल हरियाणा प्रदेश के पक्षधर नहीं है। इनके सामने हरियाणा प्रदेश के हित कुछ नहीं हैं। इनकी वजह से एस०वाई०एल० कैनाल हनी और उसमें पंजाब का बाढ़ का सारा पानी आ गया जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में उस पानी से तबाही हुई। उस पानी ने हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर दिया। (शोर)

प्रो० छतर सिंह चौहान: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी बंसी लाल जी ने इस किताब का हवाला देकर सारी बात बताई है। चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए एप्रोच किया था। या तो अम्बे प्रकाश चौटाला यह सिद्ध कर दे कि चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए एप्रोच नहीं किया या ये अपने कहे हुए शब्द वापिस ले लें।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल के बयान से यह सिद्ध हुआ है कि ये छोटा हरियाणा बनाने के पक्षधर थे। मैं अब भी कहता है कि ये हरियाणा प्रदेश के हितैषी नहीं हैं। आपने अबोहर फाजिल्का के बदले में 107 गांव और 70 हजार एकड़ भूमि पंजाब को दी। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

प्रो० छत्तर पाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरी कांस्टीच्युएँसी भी फलड इफैक्टिड है इसलिए आप मुझे भी बेसने के लिए टाईम दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। आपको भी बोलने के लिए टाईम मिलेगा।

Prof. Ram Bilas Sharma : My humble submission is this स्पीकर साहब, आपने ठीक फरमाया कि बी०ए०सी० की मीटिंग में इस हाउस के रीप्रेजेंटेटिव थे और आप स्वयं भी उस मीटिंग में मौजूद थे। हमने आपकी सेवा में बाढ़ के बारे में एडजर्नमेंट मोशन दिया था लेकिन सबको मिला कर क्लब करके 27 एम०एल०एज० की एक लिस्ट आपके कार्यालय ने प्रकाशित की है। Your office circulated a document to us that these persons have given a notice and they have been allowed to proceed और यह मोशन आपकी हिदायतों के अनुसार श्री ओम प्रकाश चौटाला ने मूव की। बाबू का मसला कोई पोलिटिकल मसला नहीं है। इस बारे में सबको चिन्ता है। जी, Sir, there is a procedure of this august House. आप हाउस को बड़ी संजीदगी से चला रहे हैं। चौधरी वीरेन्द्र सिंह बिजली मन्त्री बोलने के लिए खड़े हो गए। हमने उपाध्यक्ष महोदय से रिक्वैस्ट की कि स्पीकर साहब ने एक प्रोसीजर शुरू किया है, उस पर अगे चलते हुए चार आदमी बोल चुके हैं। यानी सर्वश्री ओम प्रकाशा चौटाला, बसी लाल जी, श्री ओमप्रकाश बेरी, श्रीमती चन्द्रावती आदि भी बोल चुके हैं और अपने हिसाब से

चेयर की तरफ से समय दिया जा रहा है। हम जिन लोगों ने नोटिस दिया हुआ है, पहले उनको बोलने दिया जाये। इम लोग बाढ़ से जो व्यक्ति पीड़ित हैं, उनका जिकर कर रहे हैं, सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहे। सरकार जवाब दे सकती है कि सरकार ने क्या कदम उठाये। जब हमारे 27 एम. एल. ए बोल लेंगे तो उसके बाद बेशक फिर आप सारे मंत्रियों को बुलवा लें। आप बेशक इनको एक-एक घंटे का समय दे, हमें कोई ए तराज नहीं। (शोर)

डा० राम प्रकाश: स्पीकर साहब, पहले हमारी बात तो सुनिये। डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग आई है....

श्री अध्यक्ष: अगर डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से रूलिंग आ चुकी है तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता।

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि 27 आदमियों ने दस्तखत करके एडजर्नमेंट मोशन अलग अलग ढंग से दिए हैं और आपने उन सब को एक साथ मिलाकर रूल 84 के तहत यह डिस्कशन शुरू करवाई है। यदि श्री वीरेन्द्र सिंह जी उस पर दस्तखत कर देते और इनका नाम भी फिर आप 28वें नं० पर दर्ज कर लेते तो इनके बोलने पर हमें कोई एतराज नहीं। अगर ये सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं तो अब एडजर्नमेंट मोशन बारें लिखकर दे दें और फिर बोल लें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, रुलिंग दे चुके हैं।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जिन 27 आदमियों की सूची आपके पास है, पहले उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी बैठे-बैठे कह रहे थे कि 27 आदमियों की सूची हमारे दफतर की तरफ से नहीं दी गई, यह तो आप बता दें कि दी गई है या नहीं, जबकि यह लिस्ट इनके पास इनकी टेबल पर भी है। एक माह यह है कि he cannot speak on the motion

Shri Verender Singh : He has taken 15 minutes on this issue. Speaker Sir, let me speak on this motion,

Prof. Sampat Singh : Sir, I was saying that he cannot speak at this stage इन्टरवीन करके कलैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो एज ए मन्त्री जवाब देना चाहिए। अगर ये यपने हल्के की बात कह रहे हैं तो फिर आपको लिख कर देना चाहिए, उसके याद ही आप इनको बस्तेने का मौका दें। बी० ए० सी० की मीटिंग में भी एडजर्नमेंट मोशन की बात आई थी कि अलग-अलग लोगों ने पांच- पांच दस- दस के ग्रुप में एडजर्नमेंट मोशन दी है। आपने कहा था कि रूल 84 के तहत सारी इक्वटी करके क्य सभी को मोलने का मौका दिया जायेगा किन हमने एडजर्नमेंट मोशन पर जोर नहीं दिया।

स्पीकर सर, हमने तो ग्रेस दिखाई है। गवर्नमेंट चाहती थी कि इस पर डिस्कशन हो, हमने कहा रूल 84 में इस को

कन्वर्ट करके प्रस्ताव मन्जूर करवाईये। हमारी मन्शा यही थी कि मामला सीरियस है इसलिए इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। इस गम्भीर सिचुएशन पर पहले मैम्बर्ज अपनी बात कह लें लेकिन मिनिस्टर्ज बीच में इन्टरवीन करें यह ठीक बात नहीं है। (विधन) विपक्ष के लोग और ट्रेजरी बैचिज पहले अपनी बात कह लें, उसके बाद नेहरा साहब जवाब दें, चाहे मुख्य मन्त्री जी जवाब दें या दूसरे कन्सर्ड मन्त्री जवाब दे सकते हैं। They want to kill the time. If he wants to participate in the discussion, he should move the motion and apply to the Speaker. स्पीकर सर, इस बारे में तो आप ही अपनी रूलिंग दे सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन स्टेट में हो तो कौन डिस्कशन करेंगे मिनिस्टर इस पर कैसे डिस्कशन करेंगे वे तो सिचुएशन का जवाब देंगे। सरकार की पालिसी क्या है, इस बारे में वे डिस्कशन के बाद ही जवाब देंगे, न कि हमारे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वे डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पहले मोशन पर साईन करें और उसके बाद अगर आप इजाजत दे तो वे बोल सकते हैं। (विष्य) स्पीकर सर, अभी जो मैम्बर्ज बोल रहे हैं पहले वे उसको सुनें। (विधन एवं शोर) स्पीकर सर, इन लोगों को इस तरह से अपनी बूट मेजोरिटी का फायदा उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। (विधन एवं शोर)।

उद्योग मन्त्री (श्री ए०सी० चौधरी): स्पीकर सर, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। एक प्वांयट पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। स्पीकर सर, एक ईशु जिसको डिफरेंट एंगलज से पेश किया गया

है और उस वक्त के चेयरमैन ने उस पर अपनी फाईनल रूलिंग दे दी हो, क्या वह मुद्दा रि-ओपन हो सकता है? (विधन एवं शोर)

Prof Sampat Singh : The Speaker can re-open. We are submitting before the Hon'ble Speaker for reopening

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, जो मसला आपके सामने है, वह यह है कि इन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया लेकिन अण्डर रूल 84 के तहत डिफरेंट पार्टीज ने इस को माना। 26-27 के करीब मैम्बर्ज ने मोशन दिया है और आपने कहा था कि इसमें सारे मेम्बर पार्टीसिपेट करे। जब सारे हाउस के पार्टिसिपेशन की बात आ गई हो तो फिर उसमें मिनिस्टर भी आ गए। आप इस रूल को ध्यान से पढ़े, इस में लिखा है -

"A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly, but the Assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech....."

Now, the question is that what is the definition of Assembly. The Assembly means "Legislative Assembly of the State of Haryana". It includes all the members. It does not mean only the Opposition Members. मूवर्ज के अलावा इस पर कोई भी बोल सकता है। स्पीकर सर, यह मुद्दा बी०ए०सी० में भी डिस्कस हुआ था। स्पीकर सर, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी चिन्तित है, जिसमें ये लोग आते हैं और ट्रेजरी बेंचिज के लोग भी आते हैं। हम सभी ने मिल कर फैसला किया था कि यह एक

नैचुरल क्लैमिटी हुई है। हम सभी इसमें शामिल हैं ओर इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है। डिस्कशन के बाद मुख्य मन्त्री जी जवाब देगे लेकिन जो मन्त्री हैं, उनके हल्के की जो बात है वे लोग उसे भी कह सकते हैं। जो दिक्कतें उनकी हैं वे उनको व्यान कर सकते हैं। I quote the rule further—

"no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a Member moves a Substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and on such motion the vote of the Assembly shall be taken."

We cannot move the substantive motion. This motion has to be moved by the member. As I already stated, the Assembly includes all the members as not only the opposition members.

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, बात बड़ी सिम्पल सी है। जिन मैम्बरज के मोशनज आपको मिले हैं, कालिंग अटेंशन मोशन भी आए हैं तथा एग्जर्नमेंट मोशनज भी मिले हैं, आपने सभी पक्षों की सहमति से सभी मोशनज को रूल 84 में तबदील कर दिया है।

श्री जगदीश नेहरा: यह मूवर की तरफ से नहीं हुआ है।

Ch. Birender Singh : Sir, I want to submit that this is from this Secretariat, the adjournment motion has been converted into notice of motion under Rule 84. They have given the list of 27 members and it reads like this that such

and such members have given notice of the motion which is to be moved during the current Session of the Vidhan Sabha. The wording of the motion is—

"That the serious situation that has arisen on account of recent flood In the State and the substantial damages caused by it, be discussed."

This is the motion and there are 27 movers. It is very clear that **if** a Minister wants to intervene, he is most welcome. But he cannot make a speech on the floor of the House because he has to give certain policy statement on certain matters which are referred by the Hon'ble Members regarding his motion. Sir, I am here only to straighten the record because you are to give your ruling and your ruling is must. It is very clear from Rule 84 that all the 27 members, those who have been listed, can speak and then the Government should give the reply. That should be the procedure. If Minister says, "I am to intervene", he is most welcome. Let it be very clear. There should not be any ambiguity.

Shri Jagdish Nehra : Sir, my question is, whether there are only 27 Members in the Assembly, who can speak ?

प्रो० छत्तर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक मोशन मूव किया था।

श्री अध्यक्ष: यह मोशन का टाइम नहीं है। आप बैठ जाइए।

प्रो० छत्तर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जब बोल रहा था तो आपने एक आदेश पारित किया था कि कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी क्या बात कही थी जो वह रिकार्ड से हटाया गया? अगर कोई मैम्बर बोलना चाहता है तो क्या उसकी बात को रिकार्ड से हटाया जाता है?

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही से तब हटाया जाता है जब कोई अनपार्लियामेंट शब्द बोल रहा हो या बिना इजाजत के रोल रहा हो।

प्रो० छत्तर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी इजाजत से बोल रहा था। मैंने जो मोशन दिया था। क्या मुझे भी उस पर रोलने का समय दिया जाएगा? Sir, whether my name is in the list of Speakers ?

श्री अध्यक्ष: आपको भी बोलने को समय दिया जाएगा।

प्रो० छत्तर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अब बोल लूँ।

Mr. Speaker : I have asked you to take your seat. Let me give my ruling आप चेयर को ऐड्रेस करें, सीधा एक दूसरे को न बोले,।

चौधरी ओम प्रकाश बैरी: अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमने रूल 84 के तहत मौसन दी है और आपने उसको कसब कर

दिया तो उसमें 27 मैम्बर ही बोलेंगे। इस बारे में मूवर का मतलब यह है कि जो मैम्बर मोशन को मूव करता

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिए आपको रूलिंग से पहले योजना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब ने एक एक्सेप्ट डून्डा कि के भी गेम सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी इस किताब में नहीं लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, चन्द्रावती जी ने भी तो यह मोशन मूव किया है। वे भी तो इनकी पार्टी से हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात ठीक है, अब आप बैठ जाए।

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

Prof. Sampat Singh : Sir, I have also my point of order.

Mr. Speaker : I will quote Rule 84 which reads as under :—

"A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly but the Assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a Member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and on such motion the vote of

the Assembly shall be taken."

इस रूल के तहत सभी डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं।

डा० राम प्रकाश: स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर साहब ने तो कोई रूलिंग नहीं दी है। नाम की क्या बात है, नाम तो दूसरे का भी लिया जा सकता है। उन्होंने कोई भी रूलिंग नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष: राम प्रकाश जी, आप बैठिए। पहली बात तो यह है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला मूवर हैं, there is no plural word in the Rule. दूसरी बात इसमें यह है कि 'असैंबली' लिखा हुआ है जिसका मतलब है 'आल'। Assembly means 'all,' all the opposition as well as the members of the ruling party. अब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, आप बोल लें और अपने हल्के की बात कहे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आपने केवल मूवर ही कहा है।

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, आप बैठे। जब आप बोल रहे थे तो किसी ने आपको इंटरुप्ट नहीं किया था। जब एक बार रूलिंग आ चुकी है तो उसके बाद डिस्कशन नहीं होगा। वीरेन्द्र सिंह जी, आप एज ए० एम०एल०ए० बोलें, एज ए मिनिस्टर जवाब न दें। आप फ्लड के बारे में अपने हल्के और सारी स्टेट की पोजीशन के बारे में ही बोलें।

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सर, कोई नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप मुझे बोलने का समय तो दे। सारे लोग मुझे भाषण दे रहे हैं। स्पीकर सर, मैं बीस साल से इस असैम्बली में हूँ। सर, जब चौटाला साहब अपना भाषण दे रहे थे तो यह कह रहे थे कि दलगत राजनीति से ०पर उठकर हरियाणा की जनता पर आए हुए इस प्राकृतिक प्रकोप का मुकाबला करें। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं या अपने हल्के की बात कर रहे हैं? ये केवल अपने हल्के की बात करें।

श्री अध्यक्ष: ओमप्रकाश जी, आप बीच में न बोलें क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो आपको किसी ने भी इट्रप्ट नहीं किया था।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: सर, आपने स्वयं ही फैसला दिया है कि केवल एम०एल०ए० के तौर पर ही ये अपनी बात कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: ये हल्के के बारे में भी और स्टेट के बारे में भी अपनी बात कह सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र रामबिलास शर्मा हैं, परमात्मा का

शुक्र है इनका हस्का फलड से हलट नहीँ इया। अगर ये मुझेँ बोलने से रोके तो अच्छी बात नहीँ है न चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी लेके, सम्पत सिंह जी तो मजे ले रहे थे, लेकिन फिर भी अगर ये मुझेँ बोलने से रोके तो ठीक नहीँ है। मैं उस हल्के से आतप हूँ जहां पर चालीस गावों में से 34 गांव बार के पानी में डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, अगर फिर भी मुझेँ ये लोग बाढ की डिस्कशन पर रोकना चाहें तो क्या ठीक है? मैं एम०एल०ए० पहले हूँ, अपने हल्के का नुमाईन्दा पहले हूँ और मिनिस्टर बाद में हूँ। मेरे हल्के के लोगों ने मुझेँ कनी नुमाइन्दगी करने के लिये यहां भेजा है इसलिये इन लोगों को ऐसी बातें नहीँ करनी चाहिये थीं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधा घन्टे के लिये बढ़ा दिया जाए।

आवाजे: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय आधे घन्टे के लिये बढ़ाया जाता है। —

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैं तो पीडित हूँ, मैं गले से०पर नहीँ बोलूंगा मैं तो पीड़ा में हूँ। (विघ्न) आज बहुत बुरी हालत मेरी कांस्टीच्यूएसी को हुई है मेरे हल्के के 40 में से 34

गांव पानी में डूब गए हैं, फसल का तो कहीं तिनका भी नहीं है। मेरे हल्के में बड़े-बड़े गांव हैं जहां एक-एक गांव में 8-10 हजार वोट हैं और 26 हजार आबादी हैं, कम से कम 6 हजार घर हैं। उस गांव में जिसमें 5 हजार घर हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी के नोटिस में तो मैं बार बार लाया हूँ और उन्होंने मेरे हल्के में विजिट करने की तकलीफ भी की। मेरे हल्के में एक घर भी ऐसा नहीं हो सकता जो साबूत बच गया हो। जो घर गिरा नहीं उसमें दरार इतनी चौड़ी आई है कि 'रहने के काबिल नहीं रह गया है। मैं उस इलाके से आता हूँ जिसमें 5 सौ साल पुरानी नहर बहती थी। आज का जो हरियाणा है, उसे नहर का पानी पार्टिशन के बाद मिला होगा। मैं खुश-किस्मत हूँ जो ऐसे इलाके में पैदा हुआ हूँ। यह वह इलाका था जहां बागान थे, कोयले कूकती थी,, फर्टाइल लैंड थी। यहां के लोग हमेशा उस इलाके के चौधरी लोग कहलाते रहे हैं। रस इलाके को आज के दिन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से रि-प्रेजेंट कर जा हूँ। इस इलाके के लोगों ने जीवन भर पलायन नहीं किया लेकिन इस बार ऐसी बाढ़ की मार पड़ी कि उन लोगों को पलायन करना पड़ा है। 34 गांवों में मुश्किल से 30- 35 परसेंट लोग रह गए हैं, बाकी 65 परसेंट लोग पलायन कर गए हैं। जहां तक हरिजनों और बैकवर्ड का ताल्लुक है, शायद ही कोई घर बचा हो, एक एक घर पूरी-पूरी हरिजनों की बस्ते। बिलकुल बर्बाद हो गई है। चौटाला साहब कह रहे थे कि जब मैं खडवाली गांव में कृष्णमूर्ति इडा के गांव में ट्रैक्टर पर चढ़कर गया तो उनकी गलियों

में पानी बहते देखा, तो इटली का शहर वीनस याद आया जहां लोग मनोरंजन करते हैं, कलोले करते हैं, रोमांटिक मूड बनाते हैं। चौटाला साहब, आपको ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिये था। आप गले से०पर बोले हैं, अगर आपके दिल में पीड़ा होती, कष्ट होत तो आप उस गांव की बर्बादी के बारे में बताते। आपने जो कम्पेयर किया यह दिल, की बात नहीं, पीडा की बात नहीं, यह गले से०पर की बात है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप गले से०पर बोले हैं। आप खडवाली गांव में तो चले गए लेकिन नरवाना नहीं गए। आपके दिल मे पीडा होती तो नरवाना जाते। आपने अमी अरनी स्पीच के दौरान कहा था कि आप नरवाना नहीं जा सके।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: मैंने यह कहा था कि मैं नरवाना के 6-7 गांवों में नहीं जा सका।

श्री वीरेन्द्र सिंह:आप, चौटाला साहब, पांच सात गांव में नहीं पहुंच सके। आर आरकी दिन होती तो अवश्य पहुंच जाते लेकिन आपकी ऐसी कोई बिल थी ही नहीं, क्योंकि आपने दोबारा उसी स्थान से इलैक्शन नहीं लड़ना होता। हर बार आना हल्का बखशा लेते है। आपको तो किसी से भी हमदर्दी नहीं, है। किसी के सुख दुख में आप कमी शरीक नही हुए किसी की पीडा को आप क्या जानी। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, क्या कोई मैम्बर इस तरह से फिजूल की बातों में हाउस का कीमती समय व बाद कर सकता है? आपने इन्हें फ्लड पर गेजने का समय दिय कि आप अपने हल्के की बात कहिए। क्या ये नारनोंद की बात कह रहे हैं या फिर जनाब दे रहे हैं या फिर किसी पर कटाक्ष कर रहे हैं? (शोर)

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब आप बैठिए। इन्हें बोलने दीजियेगा। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह जा था कि बंसी लाल जी, चौटाला साहब जी, और दूसरे साथियों ने भी यह कहा कि दुस बार बरसात ने रिकार्ड तोड़ दिया है। मुख्य मंत्री जी की स्पीचिज भी न्यूज पेपर्ज में छपी हैं जिन में लिखा है कि ऐसी दादू पिछले सौ सालों में कभी नहीं आई। 90-95 सालों के जो बुजुर्ग लोग थे, वे भी यही कहते सुने गए कि पानी तो देखा था, बारिश भी बहुत देखी थी परन्तु पहले इतना भारी विनाश बारिश के कारण कमी नहीं देखा। पहले हरियाणा के अन्दर 400 मिली मीटर और ज्यादा से ज्यादा जो रिकार्ड की गई थी, वह 800 मिनी मीटर थी लेकिन अब की बार तो 1200 मिली मीटर वर्षा रिकार्ड की गयी जो कि एक रिकार्ड थी और वह भी 30 घण्टों के अन्दर अन्दर एक तज से यह आश्चर्य की बात है। इससे सारे का सारा हरियाणा प्रांत बिल्कुल तबाह होकर रह गया। मुख्य मंत्री जी ने जब पहली बार बार की स्थिति का निरीक्षण किया, मुझे भी

उनके साथ जनि का मौका मिला। चौधरी हरपाल सिंह जी भी उनके साथ थे। पहले हमने टोहाना, नरवाना, जीन्द, महम, रोहतक, दादरी, भिवानी, मुडाल, मास, पेटवा, खांडा गांवों को देखा, फिर हांसी बलि। सड़क हमने पकड़।। इस तरह से इस सारे इलाके का हमने निरीक्षण किया। पानी की शीट मीलो मील दिखायी देती थी, मीलों मील पानी वह रहा था। बरबादी की मुंह बोलती तस्वीर ही हमें नजर आई। हांसी के बाद तो मैं कहीं जा नहीं सका क्योंकि मैं वहीं पर लगभग 15 दिनों तक टिका जा। उस तबाही से लोगों को आज तक भी होश नहीं आया।

मुख्य मंत्री महोदय ने पहले हांसी को देखा, फिर हांसी के 6 किलो मीटर दूर गांव खेड़ा गगन में गए। उसके दो रास्ते थे। एक हांसी-जींद रोड से और दूसरा हांसी-पेटवाड़ रोड से जाता था। उसी रास्ते पर तबाही थी। मैंने मुख्य मंत्री महोदय से कहा कि अगर आप हांसी -जींद रोड से जाओगे तो बरबादी इतनी ज्यादा दिखायी नहीं देगी। अगर आपने बरबादी की मुंह बोलती तस्वीर देखनी है तो हांसी-पेटवाड़ रोड से जाएं, तब आपको असली हालत का पता चलेगा लेकिन वहां 6-6 फुट पानी में से होकर जाना होगा। इस बात के लिये अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा वीरेन्द्र सिंह जी, जहां से हमें बरबादी की मुंह बोलती तस्वीर नजर आए, मैं उधर से हो चलूंगा। हम 6 फुट गहरे पानी में से होते हुए गांव में पहुंचे। गांव में कोई गला ऐसी नहीं बची थी जिसमें 4-4 फुट

पानी न खड़ा हो। फिर भा जहां थोड़ा बहुत सूखा था, वहां पर हमने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की कि आप इस गांव के मकानों की हालत भी देखिए, किस प्रकार से कच्चे- पक्के मकान बर्बाद हुए हैं। मैं इनका आभारी हूं कि ये उस गांव में 15 मिनट तक मेरे साथ घूमे। जहां मैं इनको ले गया, वहां तक गए। इन्होंने मकानों की हालत देखी। ऐसे मकान देखने के बाद जो, भावना एक आदमी को बनती है, जितनी पीड़ा होती है, वह बात मुख्य मंत्री जा का चेहरा देख कर साफ दिखाई दे रही थी कि इनको कितनी पीड़ा हुई। एक हमारा लोहारी गांव है जो टोटल पंजाबियों का गांव है, डिसप्लेस्ड पर्सन्ज का गांव है। उसमें हम गए। इसके अलग, माडा, मजिरा, राजपुरा और पाली गांव भी फलड की लपेट में थे। हम लोहारी गांव में पहुंचे। वहां जो नजारा मुख्य मंत्री जी ने देखा वह भो यद्वा दर्दनाक था। कहा कोई भी गली बची हुई नहीं थी जो पानी से भरी न हो। वहां पर पानी निकालने के लिये 4- 5 इंजन लगा रखे थे। 10-10 दिन तक लोगों को लैट्रीन जाने के लिये जगह नहीं मिली। चारों तरफ खेतों में, आबादी में पानी ही पानी था तो कैसे लोग लैट्रीन जाएं? इस हालत में नैयर की काल को कैसे टाला जाए। मुख्य मंत्री जी ने इन हालात को देखा और इन्होंने जो कुछ लोगों को कहा, उससे लोगों की जान में जान आई। उसके बाद मेरे बहुत से इलाके ऐसे रह गए जिनको मैं मुख्य मंत्री जी को दिखा नहीं पाया। मैंने इनको कहा कि कुछ गांव मेरे बच गए हैं, जैसे बडोला बास, पुट्टी, मोला और खांडा। चौधरी अमर सिंह मेरे पास बैठते हैं, कंडा इनको खुद का

गांव है। खांडा गांव मैं आज तक आपको सौ सौ साले के लोग मिलेंगे। वे बताते हैं कि आज तक एक कतरा पानी भी इस गांव में नहीं आया था। उन्होंने बताया कि अब तक बड़ा से बडी बाढ आ चुकी है लेकिन वहां कभी एक कतरा पानी नहीं आया। लेकिन आन भो खांडा गांव में इतना पानी है कि हम गांव के किसी साइड से भो बिना ट्रैक्टर के नहीं निकल सकते। अगर ट्रैक्टर से भी जाएं तो हमें आने पैर०पर उठा कर खड़े हाना पड़ता है। धर्म खेड़ी, उगालन, जामनी खेड़ो और खांडा खेड़ा गांवों मै लागों ने कुछ सामान लाने के लिये, रोशन पानी लाने के लिए ट्रैक्टर निकालना चाहा। गरीब लोगों को सरकार ने राशन देना शुरू किया था। मैंने कहा ट्रैक्टर ले कर आएँ। ट्रैक्टर जब घर से निकाला तो वहां पर कल दल इतनी हो गई थी कि ट्रैक्टर जमीन के अन्दर बैठ गया। उस ट्रैक्टर के०पर का सिरा आज भी, नजर आ रहा है। खेड़ा रगडान गांव में केवल 25 परसेंट लोग रह गए हैं, बाकी 75 परसेंट लार वहां से पलायन कर गए हैं। इसी तरह से हैबतपुर, डाटा ओर मसूदपुर गांवों की हालत है। डाटा गांव में एक गउशाला है जिसमें करीब 1500 गाए हैं। गउशाला का सारा का सारा रकबा पानी के नीचे बह गया और कुछ गउएं भी पानी में बह गईं। मैंने मुख्य मंत्री जी को निवेदन किया है कि उस गांव के लिये कोई ऐसा जगह दी जाए जो सुरक्षित हो। मुख्य मंत्री जो ने हिसार डी० सी० को आदेश दे कर उन गांवों को हिसार बाड़ में जगह दिलवाई और उनके चारे का बंदोबस्त करने का भी हुकम दिया। लोगों को राशन लगातार पहुंचाया जा रहा है। लेकिन

लोगों को पीड़ा बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला काम और पुण्य का काम जो आज हम कर सकते हैं, वह हम सभी मिलकर सकते हैं। मैं चौधरी बंसी लाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी कहूंगा कि इस पीड़ा में हमें दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिये और हमें कोशिश करनी चाहिये कि किसी प्रकार से किसानों को अगली फसल काश्त करवा दें। यदि हम यह काम कर दें तो यह बहुत ही पुण्य होगा। इस बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश 15 साल पीछे चला गया है लेकिन इस प्रदेश के किसान बहुत बहादुर हैं। अगर हम किसानों को अगली फसल काश्त करवा दें और उनको उनके नुकसान का सही मुआवजा दें तो वे इस पीड़ा को भूल जायेंगे। इस प्रदेश के किसान तीन महीने में इस पीड़ा को भूल जाएंगे। गांवों के अन्दर खुशी से किसानों की किलकारियां उठती हैं, गांवों के अन्दर किसानों में जो खुशी होती है और वे जिस तक की यातें करते हैं, हम वही हंसी खुसी हरियाणा के गांवों और शहरों में ली सकते हैं, मगर हम किसानों की अगली च्यल काश्त करवा दें। किसानों को अगली फसल की बुआई के लिये बीज खाद की सहूलियत दें और बार के पानी से उनकी धरती को मुक्त करवा दें तो हरियाणा के किसानों में वले हंसी खुशी फिर आ सकती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, पैसा कहीं से भी लाना पड़े, इस प्रदेश का किसान यह न कह दें कि उन पर एक 3 दफा यह मुसीबत आई थी मजबूरी आई थी वह बर्बाद हो

गए थे, और उस समय फलां आदमी की सरकार थी उसने हमें कोई सहायता नहीं दी। आज हम सभी यह संकल्प में कि हम से जो कुछ भी बन पड़ेगा, वह हम करेंगे, किसानों की अगली फसल काशत करवायेंगे और किसानों के घरों में दोबारा खुशी ले आएंगे। सीकर साहब, एक दुकानदार सुबह से रात तक आनी दुकान में बैठता है और रात तक मुश्किल से वह 40 रुपये कमाता है। बाढ़ के कारण 'उनका कारोबार भी ठप्प हो गया'। इसी तक से गरीब हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों का सब कुछ लुट गया। अगर परमात्मा ने किसानों 'को आगे फसल दे दो तो किसान इस पीड़ा को भूल जाएंगे जिन गरीब हरिजन भाइयों ओर बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों के मकान गिर गए, वे अपने मकान कैसे बना पाएंगे? यह एक बहुत ही विकट समस्या है। हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी हम सब पर है। सीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा है' कि मेरे हल्के के 34, के 34 गांवों में बाढ़ 'के पानी को 15 अक्तूबर तक निकलवा देंगे, इसलिए मैं आपके जरिए मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि 15 अक्तूबर तक उन गांवों में बाढ़ के पानी की बूंद भी नहीं मिलनी चाहिये। यदि मुख्य मंत्री जी ऐसा कर देते हैं तो उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह (दादरी): परम आदरणीय सीकर साहब, हम सभी को मालूम है कि भगवान की लीला ने सभी को इस बाढ़ से लीला है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के 8-10 गांवों को छोड़ कर पूरे क्षेत्र में 24 से 30 किलोमीटर के बीच में पानी

ही पानी खड़ा है। मेरे हल्के में कई गांव तो बहुत बुरी तप से बर्बाद हुए हैं। मेरे गांव चरखी के अन्दर 8-10 फुट पानी है। वहां पर 2 हजार घरों में से 500 घर गिर चुके हैं और न जाने कितने मकानों में दरारें आ गई हैं। वहां पर पानी इतना अधिक खड़ा है कि वहां पर हुए नुकसान का कुछ नहीं पता। मेरे हल्के झिंझर, वरीहकला, उचीना, भागी, आदि गांवों में बहुत बुरी हालत है। कई गांव तो अब भी बाढ़ की लपेट में आते ही जा रहे हैं क्योंकि उन गांवों में पीछे से पानी आने के कारण उनका जल स्तर दिन प्रति दिन बढ़ जा है। मेरे हल्के का घीकड़ा गवि लगभग तान चौथाई खालो हो चुका है। मानकावास में और पाण्डवान में खड़ी फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसी प्रकार अटेला, बुराखेड़ा, मेहराखेडी, जयश्री व मिश्री आदि गांव ऐसे हैं जहां पर पानी के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका है। वहां पर मेरे हल्के के अन्दर पूरी तक फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरे हल्के में जानी नुकसान भी हुआ है। तीन आदमी बार की वजह से मारे गए जिनमें 2 आदमी तो मकान गिरने के कारण नीचे दबने की वजह से और एक बिजली का करंट लगने से मरा है इसी तज से पशुओं का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने पशु मारे गए। वहां पर खड़ी फसल का तो नुकसान हुआ ही लेकिन जो अनाज लोगों के घरों में था, जो इस इंतजार में थे कि भाव बढ़े गा तो दो पैसे आएंगे, उनका पूरा नुकसान हुआ है और इस प्रकार करोड़ों का नुकसान हुआ है। आज पानी की वजह से वहां पर लोगों का अनाज सड़ रहा है। दादरी शहर में भी 10 फुट, कहीं पर 8 फुट, कहीं पर 6

फुट पानी खड़ा हुआ है और मंडी में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वहां पर करोड़ों का नुकसान हुआ है। जहां तक पानी निकालने का सवाल है, वह तो निकला है लेकिन शहर में 20 प्रतिशत आबादी के अन्दर अब भी पानी खड़ा है। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर चौधरी हुकम सिंह के मकान से लेकर होस्पिटल और हरिजन बस्ती तक पानी खड़ा हुआ है। अब वहां पर नए डी० सी० साहब के आने पर लोगों को राहत मिली है और पूरा सहयोग उनका मिल पा है। सैं। कर साहब, लोगों को फौरन राहत की आवश्यकता है। जिन गांवों में पानी खड़ा है वहां तुरन्त राहत दी जाये। जहां तक मेरे हल्के के गांवों का पानी निकालने का सवाल है, वह लोहारू कैनल के जरिए निकाला जा सकता है। लोहारू कैनल के 11 पंप चल रहे हैं, एक दिन 14 पंप चले थे। वहां पर 300-350 क्यूसिक प्रति दिन पानी निकल रहा है। जब तक 600 से 800 क्यूसिक पानी नहीं निकल पायेगा तब तक मेरे हल्के का दिसम्बर तक पानी निकलना असंभव है। जहां तक पंप लगाने का सवाल है, मेरे गांव में भी पंप लगे हैं और कुछ दूसरे गांवों में भी पंप लगे हैं। दूसरे दिन जिन गांवों में पंप पहुंचने चाहिये थे, वे अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुखर मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि हमें जो भी पम्प सैट्स भेजे जाएं, वे कम 2 से कम 10 क्यूसिक के भेजे जाएं। छोटे पम्प सैट्स दिमागी राहत तो दे सकते हैं कि पम्प सैट्स भेजे हैं परन्तु उनसे पानी नहीं निकलेगा। 10 क्यूसिक के पम्प सैट्स जहां पर बिजली उपलब्ध है, वहां पर चलाया जाए और जहां बिजली नहीं

है, वहां डीजल के इंजनों से चला कर पानी निकाला जाए और पानी नहर में डाला जाए। बढवाना फीडर पर पम्प हाउसे नं? 3 बन्द पड़ा है, इसको फौरन चालू करवाया जाए। इस मामले में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ महकमें द्वारा कार्यवाही की जाए। मैं तो यहां तक गुजारिश करूंगा कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करके मुकदमें चलाए जाने चाहिए। हालांकि बारिश तेज चल रही थी लेकिन बिजली उपलब्ध थी। 5 तारीख तक बिजली तब तक उपलब्ध रही जब तक कि पानी बी०एम० एस० में नही घुस गया। बिजली उपलब्ध होने पर मोटर चलाई जा सकती थी परन्तु उन अधिकारियों ने ऐसा बुरा हाल किया हुआ था कि उन्होंने मोटर नहीं चलाई। शायद उन अधिकारियों की नीयत खराब थी जिसकी वजह से यह सारा नुकसान हुआ है। बिजली मिलने तक उस मोटर को लगातार चलाया जा सकता था। मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस मामले में वे उच्चस्तरीय जांच करवाएं कि 5 तारीख तक पम्प सैट क्यों बन्द रहा? लोहारू नहर के पम्प को बन्द करने में जिसने लापरवाही बरती, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, दादरी शहर में पीने का पानी 8- 10 दिन का रह गया है और लॉहारू फीडर से ही पानी की सप्लाई होती है लेकिन उसमें फ्लड का गंदा पानी चल रहा है। जब तक फीडर में सफाई वगैरा का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक दादरी में पीने का पानी बाहर से नही आ सकता है। इसी नए मेरी गुजारिश है कि दादरी के लिए पीने के पानी का बन्दोंबस्त करवाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही देरे हल्के के 'जो गांव पलड में डूब चुके हैं, उनकी वाटर सद-नाई स्कीमें भी फेल हो चुकी है। इन गांवों में पी ने का साफ पानी शीघ्र-अति-शीघ्र उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध करें। अध्यक्ष महोदय जिन अधिकारियों ने आने काम में कोताही बरतो है, उनके खिलाफ तो ऐशक्न होना ही चाहिये लेकिन जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और लोगों की मदद की है, तथा उन लोगों ने जिन्होंने लोगों की मदद की है, उनका धन्यवाद किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैं डी० सी० को तारीफ करूंगा जिन्होंने रात-रात भर जाग कर हमारे साथ लोगों की मदद करो हुए घूमते रहे और उनके साथ ही देखभाल, एस०ई० खुद घूमते रहे कर, रातों को जाग-जाग कर, लोगों की मदद करते रहे, उनके धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि बारिश की समस्या तो थी ही, परन्तु जिन अधिकारियों की लापरवाही से बाकरा हैड से जो पानी वापिस आता एं, उसका कोई सोल्यूशन किया जाए और उसका पानी जे०एल०एन० में डालने के लिए काम शुरू किया जाए। इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि जो फ्लड अफैक्टिड ऐरियाज हैं उनमें सभी मकान गिर गए हैं और फसल तबाह हो गई हैं, उनको पूरा मुआवजा देने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए ओर किसानों को बीज, खाद आदि उपलब्ध करवाने का बन्दोबस्त भी करें। 20 तारीख तक खड़े हुए पानी को निकलवाने के लिए पूरे बन्दोबस्त होने चाहिए ताकि जमी न की बिजाई हो सके। इसके साथ हरिजन बस्तियों में भी बहुत मारा नुकसान किया

है, वे पूरो की पूरी तबाह हो गई हैं, उन को भी पूरी मदद की जरूरत है, उन गरीब लोगों को भी मकान का मुआवजा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरे हलके में जो फ्लड के कारण मौतें हुई हैं, उनके आश्रितों को सरकार ने जो मुआवजा फिक्स किया है, वह भी फौरन दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य कवी जी से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बाढ के पानी को निकलवाने का प्रबन्ध करें, तथा लोहारु फीडर के पम्पों को शीघ्र चालू किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप यह बताए कि अब टाईम कितना और बढ़ाया जाए?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आधी रात तक की बात कही थी तो अब कम से कम 11 बजे तक टाईम तो बढ़ाएं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं, आप जब तक चाहें समय बढ़ा दे। लेकिन कल सुबह 9.30 बजे से हाउस चलेगा और ये जब तक चाहे बोल ले। ये चाहे तो 3 बने तक बोल लें और उसके बाद मुझे भी जवाब देने में एक घंटा तो लगेगा।

Mr. Speaker : Now the house stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 27th September, 1995.

***19.00 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on
Wednesday the 27th September, 1995.)